सत्यमेव जयते

असंशोधित

बिहार विधान–सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

04 मार्च, 2020

षोडश विधान सभा बुधवार, तिथि 04 मार्च, 2020 ई0

पंचदश सत्र 14 फाल्गुन, 1941(शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है ।

प्रश्नोत्तर-काल । अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे ।

प्रश्नोत्तरकाल

अल्पसूचित प्रश्न सं0-16 (श्री मिथिलेश तिवारी)

श्री विजय कुमार सिन्हा,मंत्री : समय चाहिए ।

अध्यक्ष : अब तारांकित प्रश्न लिये जायेंगे ।

तारांकित प्रश्न सं0-763(श्री अनिल सिंह)

श्री नन्दकिशोर यादव,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि न्यू बाईपास, पटना में बेउर मोड़ पर अंडरपास बनाने का फिजिबिलिटी प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु बी0आर0पी0एन0एन से अनुरोध किया गया है । फिजिबिलिटी प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरान्त अग्रतर कार्रवाई की जाएगी।

अध्यक्ष : उत्तर तो आपका दिया हुआ है, पूरक पूछिए ।

श्री अनिल सिंह : महोदय, जवाब आया है, जिसमें बी0आर0पी0एन0एन0, पुल निर्माण निगम से अनुरोध किया गया है फिजिबिलिटी रिपोर्ट के लिए, मेरा सिर्फ इतना आग्रह होगा माननीय मंत्री महोदय से कि उसके लिए समय सीमा दिया जाय और समय सीमा के अन्दर जो फिजिबीलीटी रिपोर्ट आता है, उस आधार पर इसपर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए इसका कार्य कराया जाय ।

श्री नन्दकिशोर यादव,मंत्री : महोदय, हम तो उससे आगे भी काम कर रहे हैं, फिजिबिलिटी रिपोर्ट मांगा है मैंने, बल्कि आप देखेंगे वहां पर बेऊर जेल जाने का जो रास्ता है, उसकी भी हालत खराब है, उसके निर्माण का भी निर्देश दिया है मैंने और मुझे लगता है कि बेऊर जेल होते हुए हसनपुर-जयप्रकाशनगर इस पथ की चौड़ीकरण और मजबूतीकरण करने का भी काम कर रहे हैं, इसलिए माननीय सदस्य चिन्ता मत करें, हम फिजिबिलिटी रिपोर्ट जैसे ही प्राप्त होगा, हम अग्रतर कार्रवाई करेंगे ।

टर्न-1/आजाद:अंजली/04.03.2020

तारांकित प्रश्न सं0-764(श्री विजय कुमार खेमका)

श्री नन्दकिशोर यादव,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि पथ निर्माण विभाग को उक्त पथ का हस्तांतरण नगर निगम, पूर्णियां द्वारा जून 2019 में किया गया है । पथ के हस्तांतरण के पश्चात प्रशासनिक स्वीकृति हेतु पथ का डी0पी0आर0 प्राप्त है । अग्रतर कार्रवाई की जा रही है।

अध्यक्ष : आपका भी उत्तर दिया हुआ है और उत्तर तो साफ है ।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, मैं पूर्णियां की जनता की ओर से माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ और आग्रह करूंगा कि इसका जल्दी निर्माण हो जाय ।

तारांकित प्रश्न सं0-765(श्री अजीत शर्मा)

अध्यक्ष : आपका भी उत्तर दिया हुआ है ।

श्री अजीत शर्मा : मैंने उत्तर पढ़ा नहीं है सर ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, पढ़ दीजिए

श्री नन्दकिशोर यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि बिहार राज्य में भागलपुर के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-33 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर ढाका मोड़ को जोड़ते हुए बलझोर के निकट बिहार/झारखंड सीमा पर समाप्त होनेवाले राजमार्ग को राष्ट्र उच्च पथ संख्या-133E के रूप में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है।

नव अधिसूचित राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या-133E के मार्गरेखन पर राज्य सरकार द्वारा मंत्रालय में प्रजेंटेशन किया गया है । मार्गरेखन की स्वीकृति मंत्रालय द्वारा प्रक्रियाधीन है । भारत सरकार के द्वारा मार्गरेखन की स्वीकृति के पश्चात कार्रवाई की जायेगी ।

श्री अजीत शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जनवरी में बैठक था डी0एम0 के यहां, सब लोगों को बुलाया गया था, उसमें कहा गया है कि फोरलेन बनने की स्वीकृति हुई थी लेकिन पैसा के अभाव में यह टू-लेन बनेगा । अभी प्रोपोजल आया होगा आपको, अब इसमें क्या सत्यता है लेकिन वह फोरलेन बनना जरूरी इसलिए है कि वह विक्रमशिला बाईपास दूसरा भी समानान्तर पुल बन रहा है और जाम हमेशा लगा रहता है, अगर बने तो फोरलेन ही बने, नहीं तो पैसा का दुरूपयोग होगा ।

श्री नन्दकिशोर यादव,मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य अवगत हैं कि सड़क के निर्माण में जो अग्रतर कार्रवाई करनी है, उसके पार्ट माननीय सदस्य भी रहे हैं । चूंकि एक लोक सहमति प्राप्त करने का जो नियम है, उसके तहत माननीय विधायकों, माननीय पार्षदों से भी उस जिले के लोगों से बातचीत की गई है, जब तक इस सड़क का मार्गरेखन तय नहीं हो जायेगा, तब तक अभी टू-लेन बनेगा या फोरलेन बनेगा, इसका निर्णय नहीं हुआ है । अगर टू-लेन भी बनेगा तो वीथ पे-फोल्डर बनेगा, यानी 10 मीटर बनेगा, नहीं तो हमलोग फोरलेन के लिए कोशिश करेंगे ।

श्री अजीत शर्मा : अध्यक्ष महोदय, टू-लेन वीथ 10 मीटर के लिए बात हुई है अभी, लेकिन हम कहना चाहेंगे चूँकि ट्रैफिक बहुत है, उसको मंत्री महोदय देख लेंगे, फोरलेन हो जाय तो अच्छा है ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

तारांकित प्रश्न सं0-766(श्री नौशाद आलम)

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन दोनों पुल पर 2017 में आयी बाढ़ में क्षतिग्रस्त हो गई है, क्षतिग्रस्त वाले भाग में डाईवरसन मोटरेबुल बनाकर यातायात को तत्काल प्रभाव से बहाल कर दिया गया है । क्षतिग्रस्त पुल के निर्माण हेतु टेक्नोफिजिबीलीटी रिपोर्ट की मांग की गई है । तत्पश्चात् समीक्षोपरान्त अग्रतर कार्रवाई किया जाना संभव हो सकेगा ।

श्री नौशाद आलम : अध्यक्ष महोदय, यह कहा गया है कि डाईवरसन बनाया गया है तो मेरा कहना है कि डाईवरसन नहीं बनाया गया है, उसके बाद अभी टेक्नोफिजिबिलिटी रिपोर्ट के लिए कहा गया है, जबकि इसका डी0पी0आर0 जमा हो गया है । हमलोगों ने डी0पी0आर0 जमा करा दिया है लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि डी0पी0आर0 जमा होने के बाद यह कब तक बनने का आश्वासन देते हैं ?

अध्यक्ष : शीघ्र देखवा लीजिए ।

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : जी ।

तारांकित प्रश्न सं0-767(श्री मो0 नवाज आलम)

अध्यक्ष : आपका भी उत्तर दिया हुआ है, पढ़े हैं ?

श्री मो0 नवाज आलम : नहीं पढ़े हैं सर ।

अध्यक्ष : मंत्री जी, पढ़ दीजिए ।

श्री नन्दकिशोर यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि भोजपुर जिला अन्तर्गत आरा-सलेमपुर पथ में बड़की सनदियाँ पुल का निर्माण कार्य वर्ष 2019-20 के वार्षिक कार्य योजना में स्वीकृत है । इस पुल का डिजाइन एन0आई0टी0, पटना से अनुमोदन की प्रक्रिया में है । डिजाइन के अनुमोदनोपरान्त प्रशासनिक स्वीकृति कराकर निविदा के उपरान्त कार्य कराने का लक्ष्य है।

साथ ही सनदियाँ के नजदीक छलका के बगल में घर बनने से छलका नीचे हो जाने से बाढ़ के समय पानी बढ़ने पर आवागमन में कठिनाई होती है, परन्तु शेष अवधि में वाहनों का आवागमन छलका से होता है। छलका ठीक कराने के उपरान्त भी बाढ़ के समय पानी का बहाव छलका पर होगा, इस कारण अगले वित्तीय वर्ष 2020-21 के वार्षिक कार्य योजना से इस स्थान पर पुल निर्माण की योजना शामिल करने का लक्ष्य है ताकि इस समस्या का स्थायी हल हो सके ।

श्री मो0 नवाज आलम : ठीक है महोदय, धन्यवाद ।

तारांकित प्रश्न सं0-768 (श्री निरंजन कुमार मेहता)

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, आंशिक स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि डफरा टोला से शर्मा टोला वार्ड नं0-12 तक जाने वाली पथ मुख्य बसावट डफरा टोला का आंतरिक सड़क है, जो किसी भी कोरनेटवर्क में सम्मिलित नहीं है । मुख्य बसावट डफरा टोला को शीर्ष एम0एम0जी0एस0वाई0 अन्तर्गत निर्मित पथ से सम्पर्कता प्राप्त है । अत: पथ निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

श्री निरंजन कुमार मेहता : अध्यक्ष महोदय, 2017 में हम ग्रामीण कार्य विभाग को प्रश्न से अनुरोध किये थे लेकिन डफरा टोला जिसके बारे में बताया जा रहा है माननीय मंत्री महोदय द्वारा, आपके माध्यम से श्रीमान् हम बताना चाहेंगे डफरा टोला वार्ड नं0-12 एक रायपुर टोला है, वहां से पैदल एक आड़ी से जाता है, 200-300 का वहां पर बसावट है परिवार का और यहां राजस्व कटा हुआ है । राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को जमीन क्रय करके जब तक वहां पर रास्ता नहीं देंगे, उनलोगों को रास्ता है ही नहीं, हम इसके बारे में ग्रामीण कार्य विभाग को दिये थे, इस बार हम राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को इसलिए दिये हैं कि जमीन खरीद करके इन लोगों को रास्ता दिया जाय । वहां पर सभी जाति के लोग हैं, अति-पिछड़ा लोग हैं, शर्मा लोग हैं, अल्पसंख्यक भी कुछ बसे हुए हैं और रायपुर टोला होकर रास्ता जाता है, कोई रास्ता उसका दूसरा नहीं है । राजस्व यहां पर कटा हुआ है, देखा जाय, हम राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को प्रश्न दिये थे, बिना क्रय करके जमीन

जब तक नहीं दिया जायेगा तो रास्ता है ही नहीं, कोई सड़क है ही नहीं अध्यक्ष महोदय, इसको देखा जा सकता है, हम प्रार्थना करेंगे ।

अध्यक्ष : मंत्री जी, इसको देखवा लीजिए, अगर सड़क की जमीन नहीं है ।

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : महोदय, हमने जवाब में बताया कि यह गांव का आंतरिक पथ है, जो सात निश्चय होना है महोदय, जहां तक माननीय सदस्य का कहना है डफरा टोला जिसको सम्पर्कता एम0एम0जी0एस0वाई0 से पहले से दिया हुआ है महोदय ।

श्री निरंजन कुमार मेहता : महोदय, अब तो माननीय मंत्री महोदय से हम डिस्कशन करने लिए नहीं चाहेंगे और ग्रामीण कार्य विभाग से हमने जितना रोड मांगा है, हमको सब रोड मिला है, हमारे क्षेत्र में सब रोड बन रहा है, हम तो क्वेश्चन भी नहीं किये हैं, हम तो जमीन खरीद कर रास्ता देने के लिए कहे हैं, इसकी जॉच करायी जाय महोदय।

अध्यक्ष : ठीक है, इसको देखवा दीजिए ।

तारांकित प्रश्न सं0-769(श्रीमती स्वीटी सीमा हेम्ब्रम)

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : महोदय, आंशिक स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति है कि प्रश्नाधीन पथ के आरेखन में दो बसावट अवस्थित है नम्बर-1 बगडुवा बसावट, उक्त बसावट को शीर्ष पी0एम0जी0एस0वाई0 अन्तर्गत निर्मित सोनाबरन से केसरिया पथ से सम्पर्कता प्राप्त है, नम्बर-2 तीन सीमानी बसावट, उक्त बसावट के अर्हता की जॉचोपरान्त पूरक कोर नेटवर्क में सम्मिलित करने की अग्रतर कार्रवाई की जा रही है ।

श्रीमती स्वीटी सीमा हेम्ब्रम : महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को बता देना चाहती हूँ कि सीमानी बगडुवा पथ के बारे में पिछले वित्तीय वर्ष में भी सवाल मंत्री महोदय से की थी, उस समय भी हमको जवाब मिला था कि इसका डी0पी0आर0 तैयार किया जा रहा है । इसको मैंने पुन: फिर सवाल किया और फिर दूसरा जवाब हमको मिल रहा है, मैं धन्यवाद इसलिए दूँगी कि इनके द्वारा हमारे यहां काफी पथों का निर्माण हुआ है, धन्यवाद के पात्र हैं लेकिन मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगी कि जो सीमानी बगडुवा पथ है, वह लगभग 8 कि0मी0 है और 4 कि0मी0 आपका वन विभाग का पड़ता है, उनके पास कोई सम्पर्क पथ नहीं है, इसीलिए महोदय, मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगी कि मंत्री महोदय, इसकी जॉच आप करवा लें ।

अध्यक्ष : मंत्री जी, जॉच कराकर इसको देखवा लीजिए ।

टर्न-2/शंभु-धिरेन्द्र/04.03.20

तारांकित प्रश्न सं0-770(श्री मो0आफाक आलम)

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ का वास्तविक नाम श्रीनगर एम0डी0आर0 रोड से खोखापाटू पथ है । जिसकी मरम्मति हेतु प्राक्कलन बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति, 2018 अन्तर्गत स्वीकृति की प्रक्रिया में है । तदुपरान्त अग्रेतर कार्रवाई किया जाना संभव हो सकेगा ।

श्री मो0आफाक आलम : महोदय, वह रोड बहुत जरूरी है जितना जल्द हो सके उसको करवा दें।

अध्यक्ष : वह भी कह रहे हैं कि प्रक्रिया में है ।

श्री मो0आफाक आलम : बहुत-बहुत धन्यवाद ।

तारांकित प्रश्न सं0-771(सुश्री पुनम कुमारी उर्फ पुनम पासवान)

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : महोदय, स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पुल शीर्ष पी0एम0जी0एस0वाई0 अन्तर्गत स्वीकृति उपरांत पुनर्निविदा की प्रक्रिया में है । तदुपरांत अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी । निविदा में है महोदय उसका ।

सुश्री पुनम कुमारी उर्फ पुनम पासवान : ठीक है सर, धन्यवाद ।

तारांकित प्रश्न सं0-772(श्री लाल बाबू राम)

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पुल स्थल के एक तरफ स्थित बसावट बेरूआ को संपर्कता प्रदान करने हेतु पथ जी0टी0एस0एन0वाइ0 अन्तर्गत निर्माणाधीन है एवं दूसरी तरफ अवस्थित तकियाचक को जिला योजना से निर्मित पी0सी0सी0 पथ से संपर्कता प्राप्त है । पुल स्थल के अप स्ट्रीम में डेढ़ कि0मी0 एवं डाउन स्ट्रीम में ढाई कि0मी0 पर पूर्व से पुलिया निर्मित है । अत: पुल निर्माण का प्रस्ताव तत्काल विचाराधीन नहीं है ।

श्री लाल बाबू राम : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि इनको जो रिपोर्ट अभी जिला से आया है जो रिपोर्ट पढ़कर सदन में सुनाये हैं यह रिपोर्ट गलत है । वह एक पंचायत जैसे दो भागों में बंटा हुआ है । यहां पर लक्ष्मीपुर ग्राम है यह पंचायत बरूआडीह में पड़ता है और मिडिल स्कूल हो, प्राइमरी स्कूल हो चाहे उच्च विद्यालय हो सभी उस पार पड़ता है और यह रोड जो है यह तीन प्रखंडों को जोड़ता है- चेहराकला प्रखंड, कुढ़नी प्रखंड और सकरा प्रखंड को इसलिए यह पुल

बनना बहुत जरूरी है । इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इसकी आवश्यकता को देखते हुए यह पुल कब तक बनाने का विचार रखते हैं ?

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य जिस पुल की चर्चा कर रहे थे बसावट को जोड़ने के लिए तो वह औलरेडी जुड़ा हुआ है । हमने बताया कि एक तरफ स्थित बसावट बेरूआ को संपर्कता प्रदान करने हेतु जी0टी0एस0एन0वाई0 अन्तर्गत निर्माणाधीन है जो काम चल रहा है । दूसरी तरफ तकियाचक को जिला योजना से निर्मित पी0सी0सी0 पथ से संपर्कता प्राप्त है । महोदय, सबसे बड़ी बात है कि अप और डाउन स्ट्रीम में डेढ़ और ढाई कि0मी0 पर पुल है फिर भी देखवा लेते हैं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य अतिरिक्त और पूरक सूचना दे रहे हैं कि संपर्कता के अलावा दो-तीन प्रखंडों को जोड़ने के लिए यह पुल उपयोगी होगा, इसलिए इसको आप अलग से देखवा लीजिए ।

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : ठीक है ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0-773(श्री चन्दन कुमार)</u>

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पुल स्थल के एक तरफ के बसावट रामपुर को शीर्ष पी0एम0जी0एस0वाई0 अन्तर्गत निर्मित रामपुर अलौली पी0एम0जी0एस0वाई0 पथ से संपर्कता प्राप्त है एवं दूसरी तरफ बसावट परास मुशहरी को शीर्ष पी0एम0जी0एस0वाई0 अन्तर्गत निर्मित आनन्दपुर मारण से परास मुशहरी पथ से संपर्कता प्राप्त है । प्रश्नाधीन पुल के आरेखन में कोई अन्य योग्य बसावट नहीं होने के कारण इसे किसी भी कोर नेटवर्क में शामिल नहीं किया गया है । इसके निर्माण का प्रस्ताव तत्काल विचाराधीन नहीं है ।

श्री चन्दन कुमार : महोदय, जिस पुल का हम प्रश्न किये हैं उस पुल के बन जाने से चार पंचायत लगभग 20 से 25 गांव ऐसा है जो प्रखंड मुख्यालय से जुड़ेगा, पता नहीं किस प्रकार वहां के पदाधिकारी माननीय मंत्री जी को रिपोर्ट दिये हैं । हम चाहेंगे इससे पहले भी हम गैर सरकारी संकल्प में इसका प्रश्न किये थे । उसका जवाब आया था कि पदाधिकारी के द्वारा जो कुछ कमी है उसको ठीकठाक करके वहां अतिशीघ्र पुल बनेगा । आज जो जवाब दिया जा रहा है इससे हम संतुष्ट नहीं हैं । हम चाहेंगे कि फिर से जॉच कराकर वहां अतिशीघ्र पुल का निर्माण कराया जाय ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0-774(श्री उपेन्द्र पासवान)</u>

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ मालीपुर गांव का आंतरिक पथ है जिसमें पी0सी0सी0 का कार्य स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन द्वारा

कराया गया है । मालीपुर गांव को पी0एम0जी0एस0वाई0 पथ से संपर्कता प्राप्त है । अत: पथ निर्माण का प्रस्ताव तत्काल विचाराधीन नहीं है ।

श्री उपेन्द्र पासवान : अध्यक्ष महोदय, चूंकि उस गांव से मेरा बहुत लगाव है और वहां हम बराबर आने-जाने का काम करते हैं । माननीय मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है कि वहां पी0सी0सी0 ढलाई दूसरे स्रोत से किया गया है, लेकिन वहां अभी तक कहीं भी पी0सी0सी0 ढलाई नहीं हुआ है और न ही ग्रामीण विकास कार्य विभाग में इस रोड से संबंधित कोई मामला है । मैं बहुत सोच समझकर इस रोड के प्रश्न को यहां लाया था, लेकिन माननीय मंत्री महोदय का जो उत्तर आया है यह बहुत ही उस क्षेत्र के लिए शर्मजनक है ।

अध्यक्ष : संतोषजनक है ।

श्री उपेन्द्र पासवान : संतोषजनक नहीं है, चूंकि बराबर हम वहां आने जाने का काम करते हैं । इसलिए मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से......

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, जो माननीय सदस्य कह रहे हैं उसको भी......

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, हमने बताया कि प्रश्नाधीन पथ मालीपुर गांव का यह आंतरिक पथ है ।

श्री उपेन्द्र पासवान : जी-जी ।

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : यह सात निश्चय से बनना है, लेकिन जहां तक गांव के संपर्कता की बात है तो मालीपुर गांव को पी0एम0जी0एस0वाई0 से संपर्कता प्राप्त है ।

श्री उपेन्द्र पासवान : मैं संपर्कता की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रोड निर्माण की बात कर रहा हूँ कि मालीपुर ग्राम का यह सही में आंतरिक पथ है । मैं गाड़ी में से ही इस रोड का फोटो मोबाइल से लिया हूँ ।

अध्यक्ष : आप उस फोटो का प्रिंट निकालकर के मंत्री जी को उपलब्ध करा दीजियेगा, तब आप मंत्री जी को और मंत्री जी आपको संतुष्ट करेंगे ।

श्री उपेन्द्र पासवान : ठीक है, हम वह उपलब्ध करा देंगे ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0-775(श्री यदुवंश कुमार यादव)</u>

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, 1-स्वीकारात्मक है ।

2-आंशिक स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पुल एम0एम0जी0एस0वाइ0 अन्तर्गत स्वीकृति उपरांत निविदा की प्रक्रिया में है । तदुपरांत अग्रेतर कार्रवाई किया जाना संभव हो सकेगा ।

अध्यक्ष : अब तो टेंडर हो रहा है ।

तारांकित प्रश्न सं0-776(श्री सत्यनारायण सिंह)

श्री नरेन्द्र नारायण यादव,मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, 1-स्वीकारात्मक है ।

2- रोहतास जिलान्तर्गत डिहरी प्रखंड के खुदरावां, रजवाहा के हाउडी गांव में स्थित पुल का निरीक्षण कराया गया । पुल के जीर्णोद्धार कार्य एवं गेट निर्माण हेतु प्राक्कलन तैयार कराया जा रहा है । विहित प्रक्रिया के तहत जीर्णोद्धार कार्य हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी ।

श्री सत्यनारायण सिंह : बस केवल समय सीमा मंत्री जी, चूंकि ऐसा यह रजवाहा है कि उपर-उपर बक्सर कैनाल है और पानी उससे रिसकर सालों भर कहीं पानी नहीं रहेगा तब भी रजवाहा में रहता है, सिर्फ फाटक अगर बन जाय तो बीसों गांव को फायदा होगा । माननीय मंत्री जी कब तक इसको बनवा देंगे हम यही आग्रह करना चाहेंगे ।

श्री नरेन्द्र नारायण यादव,मंत्री : महोदय, तीन महीने के अंदर ।

श्री सत्यनारायण सिंह : धन्यवाद ।

तारांकित प्रश्न सं0-777(श्रीमती भागीरथी देवी)

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि यह प्रश्न 2 पथों से संबंधित है ।

नंबर 1 चमुआ से बभनी पथ, यह पथ राज्य कोर नेटवर्क में रामनगर से बभनी के नाम से सम्मिलित है, पथ का प्राक्कलन तैयार कर लिया गया है । स्वीकृति उपरान्त अग्रेतर कारवाई की जा सकेगी ।

नंबर 2 महुईडीह से बेलवा महादलित टोला होते हुए मुख्य पथ बेलवा तक- महुईडीह से बेलवा महादलित टोली होते हुए मुख्य पथ बेलवा तक पथ आंतरिक पथ है, जो राज्य के किसी भी कोर नेटवर्क में सम्मिलित नहीं है । महुईडीह को पी0डब्लू0डी0 रोड से मुरादा पी0एम0जी0एस0वाई0 रोड से एवं बेलवा महादलित टोला को पी0डब्लू0डी0 रोड से सिकटा पथ से संपर्कता प्राप्त है । अतः पथ निर्माण का प्रस्ताव तत्काल विचाराधीन नहीं है।

टर्न-3/04-03-2020/ज्योति-पुलकित

श्रीमती भागीरथी देवी : माननीय अध्यक्ष जी, बभनी गांव चमुआ स्टेशन से हुजूर रोड नहीं है, मैं मंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि कम से कम चमुआ स्टेशन से बभनी गांव तक रोड नहीं है इसलिए ये विचार करें और इसके लिए समय सीमा बतला दी जाय ।

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, हमने बताया कि माननीय सदस्या जो कह रही थी रामनगर से बभनी तक पथ सम्मिलित है उसका प्राक्कलन बन चुका है । जिस मुहुईडीह से बेलवा महादलित टोला होते हुए मुख्य पथ बेलवा तक यह गांव का आंतरिक पथ है ।

अध्यक्ष : जो प्राक्कलन बन गया है उसको जल्दी करवा दीजिये ।

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : जल्दी करवा देंगे ।

तारांकित प्रश्न संख्याः 778 (श्री विनय वर्मा)

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि पश्चिमी चंपारण जिला के नरकटियागंज प्रखंड में त्रिवेणी शाख नहर के आर.डी. 186.242 दायां से निस्सरित जमुनिया उप वितरणी के आर.डी. 1.90 से मरहिया उप वितरणी निकलती है जिसकी लम्बाई 42.50 आर.डी. है । प्रश्नगत मरहिया उप वितरणी के आर.डी. 14.70 पर तकिया फाल एवं आर.डी. 24.35 पर सेरवा फाल है जो तकनीकी दृष्टिकोण से ठीक है एवं उप वितरणी में जल स्राव सुगमता से प्रवाहित होता है । खरीफ सिंचाई 2019 में चालिक विषयक जल स्राव कर किसानों को सिंचाई सुविधा मुहैय्या करायी गयी है । वित्तीय वर्ष 18-19 में उप वितरणी के अंतिम भाग 36.25 आर.डी. से 42.50 आर.डी. तक एवं वित्तीय वर्ष 19-20 में 11.10 आर.डी. से 34.35 आर.डी. तक तल सफाई कार्य पिछले माह फरवरी 2020 में करा लिया गया है । उप वितरणी के शेष आर.डी. का तल सफाई कार्य वित्तीय वर्ष 2020-21 के कार्यक्रम में सम्मिलित कराने का कार्यक्रम है ।

श्री विनय वर्मा : अध्यक्ष महोदय, वहाँ कोई काम नहीं हुआ है । माननीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि साथ चलें और देख लें कि अगर कोई काम हुआ हो तब उनका जवाब हम सही मानेंगे । खाली जवाब दे दिया जाता है । जवाब से हमलोग सटिस्फाइड नहीं हैं । मंत्री महोदय आपसे अनुरोध है कि आप स्थल पर चलिए, अगर होगा तो हम तैयार हैं आपकी बात मानने के लिए ।

अध्यक्ष : फिलहाल आपको कहना क्या है, वह कह दीजिये ।

श्री विनय वर्मा : हुजूर, त्रिवेणी नहर करीब करीब बंद हो गया है और यह जो सिंचाई है मेरे यहाँ दस नहरें हैं जो साफ नहीं होने से किसी का फाल गड़बड़ होने से आज 2017 से कोई सिंचाई का काम नहीं हो रहा है । इसकी जाँच करवायी जाय हम रहना चाहते हैं उस जाँच में सर ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : हम देखवा लेंगे ।

श्री गुलाब यादव : अध्यक्ष महोदय, मुझे भी इसमें प्रश्न पूछना है, मेरा भी इसमें संबंध है ।

अध्यक्ष : ये अच्छा है, चम्पारण का जवाब वे लेकर आये होंगे और आप मधुबनी का सवाल पूछ लीजिए ।

श्री गुलाब जाधव : हमारे क्षेत्र के माननीय मंत्री जी का घर है इसलिए मंत्री जी को जानकारी है ।

अध्यक्ष : अगर मंत्री जी का घर होने के परिप्रेक्ष्य में पूछ रहे हैं तो आप उनके घर पर जाकर पूछ लीजिएगा ।

श्री विनय वर्मा : जांच करने की तिथि होनी चाहिए ।

अध्यक्ष : विभाग से माननीय मंत्री जी जांच करवा लेंगे ।

तारांकित प्रश्न संख्या: 779 (श्री राजेश कुमार)

श्री शैलेश कुमार मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ से संबंधित बसावट वनपरूआ से एवं पुरौना गांव को एम.एम.जी.एस.वाई पथ से संपर्कता प्राप्त है, नारायणपुर गांव इसी एम.एम.जी.एस.वाई. पथ से कुछ दूरी पर अवस्थित है, पथ गांव का आंतरिक पथ है जो खरंजाकृत है । अत: पथ निर्माण का प्रस्ताव तत्काल विचाराधीन नहीं है ।

तारांकित प्रश्न संख्या: 780 (श्री संजय कुमार सिंह)

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1-स्वीकारात्मक है ।

2-वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ का निर्माण पी.एम.जी.एस.वाई. योजनान्तर्गत कराया गया था परंतु संबंधित पुल एवं फौल का निर्माण किसी अन्य योजना द्वारा कराया गया था जो वर्तमान में क्षतिग्रस्त है इसकी मरम्मती हेतु टेक्नोफिजिब्लिटी की रिपोर्ट की मांग की गयी है समीक्षोपरान्त अग्रतर कार्रवाई की जा सकेगी ।

श्री संजय कुमार सिंह : धन्यवाद ।

तारांकित प्रश्न संख्या: 781 (श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह)

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, 1- स्वीकारात्मक है ।

2- स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ की लंबाई 7.8 कि.मी. है इस पथ का पथांश दुर्गापुर चौक से नारायण प्रसाद के घर तक पथ की लंबाई 3.03 कि.मी. है जो एम.एम.जी.एस.वाई. अंतर्गत स्वीकृत है जिसकी निविदा प्रक्रियाधीन है । शेष पंथांश चंद्रशेखर ठाकुर से चिमनी होते हुए लोहरगांवा एस.

एच. 74 से मिलती है, पथ पर योग्य बसावट में नहीं रहने के कारण किसी कोर नेटवर्क में सम्मिलित नहीं किया गया है एवं अन्य संबंधित बसावट सिसुआ पटना पी.एम.जी.एस.वाई. पथ एवं लाहेरगांवा गांव एस.एच. 74 पर अवस्थित है अत: पथ निर्माण का प्रस्ताव तत्काल विचाराधीन नहीं है ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, जिस पथ की इन्होंने चर्चा की है कि दुर्गा चौक से यह पथ निकलता है तो वह दूसरा पथ है हमको लगता है कि जिन्होंने इनको रिपोर्ट दी है वह सही नहीं है । दूसरी बात है लोहरगांव एस.एच. 74 पर है और सिसुआ पटना एस.एच. 74 पर है तो यह भी गलत है । सिसुआ पटना एस.एच. 74 पर नहीं है । मैं चुनौती देता हूँ जिन्होंने इस जवाब को बना कर भेजा है वह कंपलीट गलत जवाब बनाकर भेजा है । तीसरी बात है कि हम विधान सभा में क्वेश्चन इसलिए करते हैं कि जो काम जो नियम में नहीं है उसके लिए क्या नियमावली बनेगी अगर वह कोर नेटवर्क में रहता पथ तो फिर यहाँ हमको सवाल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है तो यह 8 कि.मी. की सड़क यह अन्त:प्रखंड को जोड़ती है एक तरफ कॉलेज है, दूसरी तरफ बौधस्तूप है अब इसका क्या उपाय निकलेगा ? मंत्री जी यहॉं कुछ बतावें कि जो कोर नेटवर्क में अगर रहता तो हम उसकी अनुशंसा करते, कोर नेटवर्क में नहीं है तब ही सवाल कर रहे हैं तो इसको कोर नेटवर्क में लेंगे या क्या विकल्प है । नवार्ड से करा सकते हैं या दूसरी योजना से करा सकते हैं ।

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिये ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : महोदय, ये नाबार्ड या कोई दूसरी योजना से कराने का विचार रखते हैं।

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : अगर बसावट रहता तो निश्चित रुप से हम उस पथ को ले लेते लेकिन महोदय हमने बताया कि शेष पथांश चन्द्रशेखर ठाकुर के चिमनी होते हुए लोहरगांवा एस.एच. 74 से मिलती है जो योग्य बसावट नहीं रहने के कारण किसी भी कोर नेटवर्क में सम्मिलित नहीं किया गया है । महोदय, नक्शा भी मेरे पास है, इसमें कहीं बसावट नहीं है तो बसावट को सम्पर्कता देना है जहॉं तक दुर्गा चौक से नारायाण प्रसाद के घर तक की बात है जो माननीय सदस्य जिसकी चर्चा कर रहे थे वह एम.एम.जी.एस.वाई. अंतर्गत स्वीकृत है महोदय ।

अध्यक्ष : अलग से पूछ लीजिये ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : महोदय, मैंने इनकी बात को मान लिया कि जिसको इन्होंने कहा कि नारायण प्रसाद से दुर्गा चौक तक एक अलग पथ है योग्य बसावट अगर है टोला को सम्पर्कता देना है तो इसके लिए इनके पास जी.टी.एस.एन.वाई. स्कीम है ग्राम

टोला सम्पर्क निश्चय योजना मैंने इस क्वेश्चन को जी.टी.एस.एन.वाई. में नहीं किया है । मैंने इस प्रश्न को ग्रामीण कार्य विभाग में किया है कि यह पथ बनेगा कैसे, योग्य बसावट नहीं है पथ है तो लोग आते जाते हैं कैसे उधर केसरिया है इधर कल्याणपुर का पूरा इलाका है तो इसका न कोई सौल्यूशन कोई मंत्री जी बतायें ।

अध्यक्ष : ठीक है, इसको मंत्री जी अलग से देख लें ।

तारांकित प्रश्न संख्या: 782 (श्री भोला यादव)

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि पथ निर्माण का कार्य आरम्भ होने के समय पथ के प्राक्कलन के संबंध में कतिपय अनियमिताओं की शिकायत प्राप्त हुई, जिसकी जॉंच मुख्यालय के जॉंच दल द्वारा करायी गयी है । तत्काल पथ निर्माण को स्थगित किया गया है, जॉंच प्रतिवेदन के आलोक में अग्रतर कार्रवाई की जा सकेगी ।

टर्न-04/कृष्ण/04.03.2020

श्री भोला यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी कहीं न कहीं अधूरा जवाब दे रहे हैं । एक माननीय सदस्य इसी सदन के हैं, इस पथ पर ऑब्जेक्शन किये कि यह पथ नहीं बनना चाहिए । पथ स्वीकृत था, शिलान्यास हो गया और कार्य प्रारंभ होनेवाला था और मंत्री जी उनके दबाव में, महोदय, आज शिलान्यास का एक साल होने जा रहा है, उसको रोके हुये हैं और इतने दिनों से जांच करवा रहे हैं, जांच कराने की कोई इनका समय-सीमा है या इसी तरह पांच वर्ष खेप देंगे ?

अध्यक्ष : मंत्री जी, आप समय-सीमा में जांच करवा लीजिये ।

श्री भोला यादव : महोदय, इसका उत्तर आने दीजिये । यह कोई साधारण बात नहीं है । सर, रोड बनने जा रहा था ।

अध्यक्ष : हम तो वही कहे कि समय-सीमा में इसकी जांच करवा लीजिये ।

श्री भोला यादव : जांच सालभर में क्यों नहीं पूरा हुआ, बतायेंगे न माननीय मंत्री जी । आखिर उसकी क्या जांच करवा रहे हैं ?

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : महोदय, दो-तीन बिन्दुओं पर इसकी जांच करानी थी । पथ की चौड़ाई को देखना है, दूसरा, इसमें जल संसाधन विभाग की कुछ जमीन पड़ रही है, इसकी भी जांच करवा लेते हैं और तीसरी बात है कि इसमें उस समय संवेदक द्वारा एग्रीमेंट नहीं किया गया था । लेकिन माननीय सदस्य की भावना है तो हम जल्द से जल्द इसको दिखवा लेते हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष: माननीय मंत्री जल्द से जल्द दिखवाने के लिये कह दिये तो अब उसमें आप कहां खड़ा हो गये हैं, इसके पहले के प्रश्न पर भी आप खड़े हो गये थे । हर सवाल में आपका पूरक है क्या ?

तारांकित प्रश्न संख्या: 783 (श्रीमती सुनीता सिंह चौहान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्या अनुपस्थित ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 784, माननीय सदस्य श्री प्रभुनाथ प्रसाद ।

(व्यवधान)

आप दोनों माननीय सदस्य मिलकर माननीय सदस्य श्री प्रभुनाथ प्रसाद जी के प्रश्न को मार रहे हैं ।

तारांकित प्रश्न संख्या: 784 (श्री प्रभुनाथ प्रसाद)

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : महोदय, 1- आंशिक स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्न में उल्लेखित तीनघरवा बसावट के चारो तरफ रैयती भूमि रहने के कारण पथ का निर्माण नहीं कराया जा सका । अंगिआंव प्रखंड के आजाद नगर को पक्की सड़क से संपर्कता प्रदत है ।

2- आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्न में उल्लेखित बसावट तीनघरवा के एक तरफ सवा किलोमीटर दूसरी तरफ 1.20 किलोमीटर लंबाई में रैयती भूमि है । इस बसावट की आबादी लगभग 260 है । यह किसी भी कोर नेटवर्क में शामिल नहीं है । पूरक कोर नेटवर्क में शामिल करने हेतु जांचोपरांत आवश्यक कार्रवाई की जा रही है । प्रश्न में उल्लेखित दूसरी बसावट आजाद नगर अंगिआंव प्रखंड के एस0एच0 आरा सहार पथ से 24वें किलोमीटर बनौली पथ से विशम्भरा तक पक्की सड़क से संपर्कित है, जिसकी मरम्मति करा ली गयी है ।

(व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो आजाद टोला है, जो संवेदक बनाया था, लेकिन अभी तक उस गांव में रोड की संपर्कता प्रदान हीं की गयी है, अभी अधूरा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि उसको दिखवा कर पुन: उसको बनाया जाय ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आपलोग इधर से ऊधर बात करते हैं, माननीय सदस्य पूरक प्रश्न पूछते हैं, न सदस्य समझ पाते हैं, न मंत्री समझ पाते हैं । माननीय सदस्य श्री प्रभुनाथ जी, आप फिर से पूरक पूछिये ।

श्री प्रभुनाथ प्रसाद : महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मंत्री जी ने जो बताया, लसाढ़ी गांव तक ही रोड आया है, वह आजाद नगर तक नहीं गया है । अभी भी वहां पर कच्ची सड़क है, वहां रोड नहीं बन पाया है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, इसको दिखवा लीजियेगा ।

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : दिखवा लेते हैं ।

तारांकित प्रश्न संख्या: 785 (श्रीमती गुलजार देवी)

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्न दो पथों से संबंधित है । एन0एच0 57 ब्रह्मपुर से कोसी बांध कालिकापुर तक पथ, इस पथ की मरम्मति बिहार पथ अनुरक्षण नीति, 2018 के तहत प्राक्कलन तैयार कर लिया गया है, स्वीकृति के उपरांत मरम्मति कार्य कराया जा सकेगा । नंबर 2, अररिया से घोघरढीहा पथ, इस पथ की मरम्मति हेतु बिहार पथ अनुरक्षण नीति,2018 प्राक्कलन तैयार कर लिया गया है, स्वीकृति के उपरांत मरम्मति कार्य कराया जा सकेगा ।

श्रीमती गुलजार देवी : बहुत-बहुत धन्यवाद ।

तारांकित प्रश्न संख्या: 786 (श्री जनार्दन मांझी)

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पुल सहुढ़ा एवं चन्द्रपुरा, सहुढ़ा ग्राम के बीच अवस्थित है । नदी के एक तरफ के बसावट सहुढ़ा ग्राम को शीर्ष पी0एम0जी0एस0वाई0 अन्तर्गत निर्मित एल. 067 जलानी बगही पथ सरविटा पथ से मोहनपुर एवं दूसरे तरफ के बसावट चन्द्रपुरा सहुढ़ा ग्राम को मुख्यमंत्री ग्राम्य संपर्क योजनान्तर्गत निर्मित गोविंदपुर नहर रोड से चन्द्रपुरा सुहढ़ा पथ से संपर्कता प्राप्त है । प्रश्नाधीन पुल के आरेखन पर कोई योग्य बसावट नहीं रहने के कारण इसे किसी भी कोर नेटवर्क में शामिल नहीं किया गया है । इसके निर्माण का प्रस्ताव तत्काल विचाराधीन नहीं है ।

श्री जनार्दन मांझी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि एक तरफ सुहढ़ा में बना हुआ है, दूसरा भी है, बीच में नदी है, जितने लोग हैं, उनके जाने-आने के लिये तारापुर से वही एक है, अत: पुल बनने से संपर्क हो जायेगा तो दोनों के बीच में पुल बनाया जाय, जिससे जनता को सुविधा हो ।

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : महोदय, जिस पुल की चर्चा माननीय सदस्य कर रहे हैं, दोनों तरफ बसावट है, वह संपर्कित है तो जब ऑलरेडी संपर्कता दिया हुआ है तो महोदय, उसमें कुछ लाचारी है ।

श्री मेवालाल चौधरी : महोदय, गोविंदपुर के पास भी बसावट है, बड़ा महत्वपूर्ण पुल है और बालू निकाल लेने के बाद आवागमन बिल्कुल बंद हो गया है । सर, आपके माध्यम से निवेदन करेंगे कि इस पुल को बनाया जाय ।

तारांकित प्रश्न संख्या: 787 (श्री राज कुमार राय)

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ चार पथों से सबंधित है । लरझा घाट से परकौली तक पथ की लंबाई 1.5 किलोमीटर है, जो पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत निर्माणाधीन है । परकौली से तेतराही पथ का पथांश है । नंबर-2, शिवराहा से परकौलिया पथ, इस पथ की लंबाई 1.61 किलोमीटर है, जो एम0एम0जी0एस0वाई0 से निर्मित है, पथ अनुरक्षण अवधि में है एवं अनुरक्षण कार्य कराया जा रहा है । नंबर-3, झझरा आर0ई0ओ0 से चिगारी परकौलिया पथ- इस पथ की लंबाई 2 किलोमीटर है, जो एम0एम0जी0एस0वाई0 से निर्मित है । पथ अनुरक्षण अवधि में है एवं अनुरक्षण कार्य कराया जा रहा है । नंबर-4, समैला से शाहपुर पथ- इस पथ की लंबाई 4 किलोमीटर है, जिसकी मरम्मति हेतु बिहार अनुरक्षण नीति, 2018 के तहत डी0पी0आर0 प्रशासनिक स्वीकृति की प्रत्याशा में है । तदुनसार अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी ।

श्री राज कुमार राय : अध्यक्ष महोदय, यह सड़क तीन प्रखंडों के लिये एक महत्वपूर्ण रास्ता है और सब अलग-अलग सड़कें हैं, सीधा लरझा घाट पुल विथान प्रखंड से शक्ति घाट तक सीधा सड़क है और इसके बनने से तीन-तीन प्रखंड के लोगों को - कुशेश्वर स्थान, दरभंगा जाने के लिये यह मुख्य सड़क है । हम माननीय मंत्री से चाहेंगे से कि सड़क का शीघ्र निर्माण कराया जाय । महोदय, यह 15 वर्षों से जर्जर है ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

तारांकित प्रश्न संख्या: 788 (श्री चन्दन कुमार)

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ के आरेखन में कोई योग्य बसावट नहीं होने के कारण इसके निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है

श्री चन्दन कुमार : महोदय, माननीय मंत्री जी का जो जवाब आया है, उससे हम संतुष्ट नहीं हैं । हम चाहेंगे कि उसका फिर से जांच करवा लिया जाय । जहां 10-10 हजार,

12-12 हजार की आबादी है, पदाधिकारी जो लिखकर भेज दिये हैं कि यहां कोई बसावट नहीं है, यह बड़ी दुर्भाग्य की बात है । महोदय, इस से पहले मैंने पुल के लिये भी प्रश्न किया था तो उसमें भी यही जवाब आया है। महोदय, वहां माननीय मंत्री जी का रीलेशन भी है अलौली विधान सभा के सहसी गांव में, मैं चाहूंगा कि आप वहां जरूर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें । हमने लगभग 10 पुल-पुलिया के लिये लिखकर दिया था और माननीय मंत्री जी एक द्वारा एक भी पुल, पुलिया और बड़ा सड़क का निर्माण नहीं कराया गया । अगर माननीय मंत्री जी वहां अपने रीलेशन में जायेंगे तो तो इनको भी सुनना पड़ेगा । इसलिये हम महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहेंगे माननीय मंत्री जी को कि वहां आप किसी भी प्रकार का इधर-उधर के दबाव में नहीं रहकर के, हम आर0जे0डी0 के एम0एल0ए0 हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि हमको इगनोर करके चला जाय और महोदय, हम आशा और उम्मीद करते हैं कि अलौली विधान सभा क्षेत्र के जो भी सवाल हैं, उसको एक बार जरूर देख लिया जाय और उस पर ध्यान दिया जाय ।

क्रमश :

टर्न-5/अंजनी/04.03.2020

श्री चन्दन कुमार : (क्रमश:) : हम आपसे आशा और उम्मीद करते हैं कि अलौली विधान सभा का जो भी सवाल है, उसको एक बार जरूर देख लिया जाय और उसपर ध्यान दिया जाय । बहुत-सी सड़कों के संबंध में लिखकर हमने दिया है, जो अति महत्वपूर्ण है और अभी तक नहीं बना है । महोदय, आप जानते ही हैं कि हम किस क्षेत्र से एम0एल0ए0 हैं और वहां हमारे प्रतिद्वंदी आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी थे, इसलिए वहां पर किसी प्रकार का दबाव नहीं रखकर के हमलोगों का भी काम कराया जाय...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सड़क से जुड़े हुए या इस सड़क के बीच में जितने भी बसावट हैं, जितने गांव हैं....

श्री चन्दन कुमार : महोदय, एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि.....

अध्यक्ष : आप मेरी बात सुन नहीं रहे हैं ? जो-जो बसावट इस सड़क पर हैं, उन सबके बारे में लिखित सूचना माननीय मंत्री जी को दे दीजिए, सूचना देने के बाद मंत्री जी के रिश्तेदार से इनको एक दिन निमंत्रण करा दीजिए और जाकर इसको देख भी लेंगे । आपकी सारी समस्या भी दूर हो जायेगी ।

श्री चन्दन कुमार : महोदय, वही काम कराकर उद्घाटन, शिलान्यास करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ।

तारांकित प्रश्न संख्या-789(श्री (मो0) तौसीफ आलम)

(व्यवधान)

श्री भाई वीरेन्द्र : ***

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जिस बात को माननीय सदस्य भाई वीरेन्द्र जी ने उठाया है, उसपर मेरा औब्जेक्शन है, वह बिल्कुल आपत्तिजनक है ।

अध्यक्ष : वह बात प्रोसीडींग्स में नहीं जायेगी ।

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : लेकिन महोदय, एक चीज है कि बिना सोचे समझे कई बार फालतू बात भाई वीरेन्द्र जी बोल देते हैं, जो उनको नहीं बोलना चाहिए । सदन की अपनी गरिमा है लेकिन आपके मन में जो बात रहती है, वह आप बोल देते हैं ।

अध्यक्ष : भाई वीरेन्द्र जी, बैठ जाइए ।

(व्यवधान)

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, एक बार मैं कहना चाहता हूँ कि यह बिल्कुल गलत बात है। महोदय, माननीय सदस्य चन्दन जी चर्चा कर रहे थे, आपके कार्यकाल में 723 किलोमीटर पथ बना और हम किसी भी दल के साथ पक्षपात नहीं करते हैं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय के निदेशानुसार नहीं लिखा गया ।

हमारे नेता आदरणीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि किसी के साथ पक्षपात नहीं करना है और यही कारण है कि 93हजार किलोमीटर सड़क बना इस बिहार में ।

(व्यवधान)

आप लोगों को शर्म आनी चाहिए । जो मन में आता है, वह आप बोल देते हैं । यह बिल्कुल गलत बात है । होश में रहिए । हर चीज हंसी मजाक में नहीं होता है। आप चुप रहिए, बिना प्रमाणित किये हुए ही बोल दीजियेगा, यह बिल्कुल गलत बात है । महोदय, इनसे आप माफी मंगवाइए । यह बिल्कुल गलत बात है । महोदय, इनकी आदत है बैठे-बैठे हर बात बोलना । यह कोई बात हुई ।

अध्यक्ष : सभी माननीय सदस्यगण आसन ग्रहण करें ।

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, पहले इनसे माफी मंगाया जाय इस बात के लिए ।

अध्यक्ष : आप लोग आसन ग्रहण कीजिए ।

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : जो व्यक्ति 15 साल में 523 किलोमीटर रोड बनाया और हमारे नेता आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 93हजार किलोमीटर रोड बनाया है । क्या हमलोग पक्षपात करते हैं ? बिहार को तो आप लोग पाताल तक पहुंचाने का काम किये हैं।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आप तौसिफ आलम जी का जवाब दीजिए ।

*** आसन के आदेशानुसार अंश विलोपित ।

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, यह बहुत गंदा काम है, बैठे-बैठे कुछ-न-कुछ बोलते रहते हैं।

अध्यक्ष : वह बात प्रोसीडींग्स से निकाल दी गयी है ।

तारांकित प्रश्न संख्या-789(श्री (मो0) तौसीफ आलम)

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पुल वर्ष 2017 में आयी बाढ़ के कारण ध्वस्त हो गया है । नये पुल के निर्माण हेतु प्राक्कलन तैयार कराया जा रहा है ।

अध्यक्ष : बैठे-बैठे कोई माननीय सदस्य न बोलें ।

श्री (मो0) तौसीफ आलम : महोदय, समय-सीमा दे दिया जाय ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य कह रहे हैं कि कब तक हो जायेगा, समय-सीमा दे दिया जाय।

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, अब तो सत्र समाप्ति पर है, अगले सत्र में कर देंगे ।

तारांकित प्रश्न संख्या-790(श्री शिवचन्द्र राम)

श्री नंद किशोर यादव, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि पटना जिलान्तर्गत गायघाट के उत्तरी छोर हाजीपुर के तरफ किसी भी तरह का वृहद कटाव नहीं हो रहा है, जिसके कारण पीपा पुल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े । पीपा पुल का संचालन/परिचालन ठीक ढ़ंग से हो रहा है एवं आवागमन प्रभावित नहीं है ।

श्री शिवचन्द्र राम : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री नंद किशोर बाबू पुराने मंत्री हैं और खास करके पटना के भी हैं और हमारे जिला के प्रभारी मंत्री भी हैं । बड़ा अफसोस आता है, हम भी मंत्री रहे हैं, जो जवाब बनाकर पदाधिकारी ने दिया है, हम कहते हैं कि माननीय मंत्री जी किसी को भेजें मेरे साथ और इतना महत्वपूर्ण पीपा पुल है, जो उत्तर बिहार को जोड़ता है । अध्यक्ष महोदय, आप भी उससे वाकिफ हैं और पूरे सिक्किम, सिलिगुड़ी तक के, नेपाल देश तक के लोग उससे आते-जाते हैं और एक किलोमीटर में वह लगातार कट रहा है और जो पीपा पुल बनाया गया है, उसमें तीन बार हमारी गाड़ी नीचे चली आयी है और इसके अलावे मैं माननीय मंत्री जी को व्यक्तिगत रूप से कहा भी हूं कि आप इसको देखवा लीजिए लेकिन मुझे यह आश्चर्य हो रहा है कि जो सवाल है, उसका जवाब पढ़कर हमलोगों को बता दे रहे हैं, हम बउआ नहीं न हैं ? हम बिना देखे हुए बोल रहे हैं क्या ? आप इसका कोई उपाय कीजिए । यह साधारण काम नहीं है पीपा पुल का मामला, यह

पूरे उत्तर बिहार को जोड़ता है, आप इसको देखवायें, नहीं तो हम अभी जाकर फोटो खींचकर ले आते हैं और जो पदाधिकारी ने गलत रिपोर्ट दिया है, क्या उनपर कार्रवाई करेंगे ?

श्री नंद किशोर यादव, मंत्री : पूरक क्या है, यह तो आप बोलें ? सवाल ही नहीं किये।

श्री शिवचन्द्र राम : अगर माननीय मंत्री जी नहीं समझ पाये तो हम क्या करें । ये कहते हैं कि कोई कटाव नहीं हो रहा है तो मेरा इसी पर कहना है कि कटाव हो रहा है और कटाव ही नहीं हो रहा है....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य का कहना है कि कटाव हो रहा है, उसको देखवा लीजिए ।

श्री शिवचन्द्र राम : थोड़ा कटाव नहीं हो रहा है, लगभग 20-20 फीट कटा हुआ है । डेली कट रहा है, कोई देखने वाला नहीं है । पीपा पुल की भी वही जर्जर स्थिति है, उसकी जो व्यवस्था है डेली एक्सीडेंट हो रहा है लेकिन मुझे आश्चर्य हो रहा है, जबकि वे वहां के प्रभारी मंत्री भी हैं और बात कर रहे हैं कि कोई कटाव नहीं हो रहा है । इसकी जांच तो कराइए ।

(व्यवधान)

जांच कराइए, नहीं तो फोटो खींचकर लायेंगे और मुख्यमंत्री जी को देखायेंगे ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी को बोलने दीजिए ।

श्री नंद किशोर यादव, मंत्री : महोदय, शिवचन्द्र बाबू माननीय मंत्री रहे हैं और वे जिस प्रकार से बोल रहे हैं महोदय, अगर ये मंत्री रहते और माननीय सदस्य इसी प्रकार से बोलते रहते तो कैसा लगता उनको । महोदय, आपको जो पूछना है, उसका जवाब देने के लिए हम तैयार हैं । हमसे तो पूछ ही नहीं रहे हैं, खाली भाषण दिये जा रहे हैं । इसमें विषय दो है- विषय यह है कि जो जेनरल कटाव की बात गंगा नदी की होगी, उसका जवाब तो जल संसाधन विभाग देगा । चूंकि यह प्रश्न जुड़ा हुआ है पीपा पुल से, इसलिए मैं जवाब देने के लिए खड़ा हुआ हूं । महोदय, आप भी जानते हैं कि जैसे-जैसे पानी घटता है वैसे-वैसे जो एप्रोच रोड पीपा पुल का है, वह छूटता जाता है, उसको ऐड करना पड़ता है । आपको यह भी ध्यान में होगा कि इस पीपा पुल के लिए हमलोगों ने पांच साल का कंट्रेक्ट दिया था । पहले यह पीपा पुल पुल के बहुत नजदीक था लेकिन इधर के पूर्वी हिस्से को तोड़ने की योजना बन गयी है तो उस पीपा पुल को दूर किया गया है तो हाजीपुर की तरफ जो एप्रोच उसका है, वह प्राइवेट जमीन पर है तो जब पानी घट रहा है तो वहां गैप हो जाता है और उसके कारण जब-जब कठिनाई होती है, तब-तब उसको ठीक करने के लिए निदेश दिया गया है और लगातार तीन बार ठीक किया गया है और फिर मैं माननीय सदस्य से कहता हूं कि हम इसपर लगातार नजर बनाये हुए हैं

और जब भी ऐसी स्थिति आती है । प्राइवेट जमीन वाले से विभाग के लोगों ने बातचीत भी किया है और बातचीत करके सहमति भी बनायी है ताकि लोगों को कठिनाई न हो । अगर शिवचन्द्र बाबू को लगता है कि बड़ा एक्सीडेंट हो जाने वाला है, खराब हो गया है तो आप कहें तो हम पीपा पुल वहां से हटा देते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री शिवचन्द्र राम : अध्यक्ष महोदय, इसकी जांच विधान सभा की कमिटी से करायी जाय । पीपा पुल का मामला है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है ।

अध्यक्ष : उन्होंने कहा है कि वे जांच करा देंगे ।

श्री शिवचन्द्र राम : कुछ जांच नहीं हो रही है, लगातार एक्सीडेंट हो रहा है ।

अध्यक्ष : जांच करा देंगे ।

टर्न-6/राजेश-राहुल/4.3.20

तारांकित प्रश्न संख्या: 791 (श्री विजय प्रकाश)

श्री शैलेश कुमार, मंत्री: महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि यह प्रश्न दो पुलों से संबंधित है:-

नम्बर 1: मझवे मोड़ से मननपुर तक की सड़क में क्यूल नदी पर पुल-उक्त पुल के एक तरफ मझवे एवं ढंढ़ बसावट अवस्थित है, जिसकी संपर्कता आर0सी0डी0 तेतरहाट से मननपुर पथ से प्राप्त है एवं दूसरे तरफ मननपुर बसावट अवस्थित है, जिसकी संपर्कता मलयपुर क्यूल आर0सी0डी0 पथ से प्राप्त है । यह पुल 2.80 किलोमीटर कच्ची सड़क पर अवस्थित है जिसकी आरेखन में कोई योग्य बसावट नहीं रहने के कारण इसके निर्माण का कोई प्रस्ताव तत्काल विचाराधीन नहीं है ।

नम्बर 2: बड़ीबाग से फतेहपुर तक की सड़क में क्यूल नदी पर पुल, उक्त पुल के एक तरफ फतेहपुर बसावट अवस्थित है, जिसकी संपर्कता पी0एम0जी0एस0वाई0 अंतर्गत निर्मित निमनवादा से फतेहपुर पथ से प्राप्त है एवं दूसरे तरफ बड़ीबाग बसावट अवस्थित है, जिसकी संपर्कता बड़ीबाग से मंगोबंदर से प्राप्त है । उक्त दोनों तरफ के बसावटों के बीच कोई योग्य बसावट नहीं रहने के कारण इसके निर्माण का कोई प्रस्ताव तत्काल विचाराधीन नहीं है ।

श्री विजय प्रकाश: महोदय, हमने माननीय मंत्री जी से निवेदन किया था एक पुल के बारे में यहां पर, मननपुर मझवे के बीच में बहुत लम्बी दूरी पड़ती है, तेतरहाट जो लखीसराय जिले में पड़ता है और बहुत ही नजदीक पड़ेगा, जो मझवे एक चट्टी है, वहां से आवागमन की सुविधा होगी मननपुर क्यूल होते हुए, बरहट की तरफ जाते हुए इसके लिए माननीय मंत्री जी से निवेदन किया था कई बार और दूसरे जो

पुल की बात है बीसलपुर की, महोदय जिस तरह से आप घुमाकर बता रहे थे मंगोबंदर की तरफ से नीम नवादा होते हुए आने का वह लगभग 30 किलोमीटर दूर पड़ता है और हमारे यहां से प्रखण्ड आने की व्यवस्था नहीं है । बहुत पहले आज से 10-15 वर्ष पहले एक ललदया पुल माननीय राबड़ी देवी जी ने उद्घाटन किया, जो कि जर्जर स्थिति में हो गया है, उसके बाद आज तक क्यूल नदी पर एक भी पुल नहीं बना है । महोदय, उसको घुमाकर जो आप बता रहे हैं नीम नवादा होते हुए मंगोबंदर जाने के लिए, जबकि उसकी दूरी 10 से 15-20 किलोमीटर लम्बी पड़ेगी, इधर जो हम बता रहे हैं वह 3 किलोमीटर की दूरी पड़ेगी खैरा प्रखण्ड ब्लॉक आने के लिए, तो मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि इतना मत घुमाइये।

अध्यक्षः ठीक है, अब 792 श्रीमती रंजू गीता ।

तारांकित प्रश्न संख्याः 792 (श्रीमती रंजू गीता)

(माननीय सदस्या अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्याः 793 (डॉ0 रामानुज प्रसाद)

अध्यक्षः अब 793 डॉ0 रामानुज प्रसाद । उत्तर दिया हुआ है आप पूरक पूछिये ।

डॉ0 रामानुज प्रसादः अध्यक्ष महोदय जी, मैं माननीय मंत्री जी से पूरक के रूप में यह जानना चाहता हूं कि अभियंताओं ने रिपोर्ट बनाकर दी है, उसको इस पुस्तिका में छाप दिया गया है लेकिन हम लोगों ने वहां देखा है और दोनों जिलों के डी0एम0, सारण जिला डी0एम0 और वैशाली जिला डी0एम0, अब जाम की यह स्थिति है कि पूरा जन-जीवन तबाह हो गया है और आप जो एक बगल से पुल की बात कह रहे हैं, वो पुल भी जाम रह रहा है, तो अगर बढ़ती हुई जनसंख्या को रेशनलाईज करना है, तो इस पर हम लोगों ने देखा था कि जो सम्बन्धित अभियंता है, उन लोगों ने भी स्वीकारा है इसको कि हां इसको ऐसे कर दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा और आज अटपटा जवाब बना करके भेज दिया, तो मैं इस पर जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी आप मुख्यालय से अभियंताओं की टीम भेज करके इसका सर्वेक्षण करा लें अन्यथा एक मेरा दूसरा आग्रह होगा कि जो बुम ऑफ पॉपुलेशन है, जो बुम ऑफ व्हीकल्स है, उसको रेशनलाईज करने के लिए हाजीपुर और सोनपुर के बीच एक और पुल की निहायत आवश्यकता है, यह बात हमने पहले ध्यानाकर्षण के दौरान भी उठाई थी कि मन्दिर के पास से पहलेजा घाट से जो जाता है और मेला में भी सवाल उठा था माननीय मुख्यमंत्री जी उस मेले का उद्घाटन करने गए थे और तब उन्होंने भी कहा था कि ये पुल बनेगा । माननीय

उप-मुख्यमंत्री जी आज यहां उपस्थित हैं, मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी का स्पष्ट जवाब आए ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य रामानुज जी, मंत्री जी ने कहा है कि टेक्निकली फिजिबल नहीं है, इसके बारे में आप पूरक पूछिये न............

(व्यवधान)

डॉ0 रामानुज प्रसाद: माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहता हूं कि माननीय मंत्री जी बिलकुल फेक और फिक्स जवाब बनाकर आए हैं । अध्यक्ष महोदय जी, मैंने माननीय मंत्री जी से पहले ही कहा और पूछा कि क्या आप मुख्यालय से सक्षम अभियंताओं की टीम भेजकर जांच कराएंगे और कैसे ये बन पाएगा, इस पर आप कार्रवाई करवाएंगे । दूसरा इसके साथ-साथ आग्रह भी मैं कर रहा हूं..............

(व्यवधान)

श्री नंदकिशोर यादव, मंत्री: महोदय, उस पुल से माननीय सदस्य भी गुजरे हैं और बहुत बार मैं भी गुजरा हूं और जब वहां पुल बनना तकनीकी दृष्टि से संभव नहीं है, तो पुलों के बारे में कोई जिद नहीं होनी चाहिए क्योंकि वह तकनीकी चीज है, जिसके बारे में पूरी तरह हम और आप नहीं जानते हैं । जब इंजीनीयर्स ने कह दिया है कि साहब इसको चौड़ा करना सम्भव नहीं है, इसके अप्रोच को बढ़ाएंगे, तो कठिनाई पैदा होगी पुल पर, तो उसकी जिद नहीं करनी चाहिए, जो पुल अभी बना हुआ है, नया पुल जो बना है उसके जाम की चिन्ता जो आप कर रहे हैं, तो हम इस पुल के बगल में एक और नया पुल बनाने वाले हैं, जब पटना रिंग रोड़ जो बनने वाला है, उसमें गंडक नदी पर एक और नया पुल प्रस्तावित है, जो वर्तमान पुल से थोड़ा दक्षिण से होकर बनेगा, वह सीधा छपरा चला जाएगा, जिससे पूरा गोपालगंज, छपरा की जो सवारी आती है, इससे आपको राहत मिल जाएगी, फिर इसका इस्तेमाल छपरा और सोनपुर के लोग ज्यादा कर सकेंगे, तो आपको राहत मिलेगी ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद: महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि हम सोनपुर के लोग सारण जिले के अन्तिम छोर पर बसे हुए हैं और यह सारण जिला एवं वैशाली जिला का बॉर्डर है । माननीय मुख्यमंत्री भी बैठे हैं, हमने बार-बार उठाया है कि हमको जिला ही बना दिया जाय । सारे कार्यों के निष्पादन के लिए हमको छपरा जाना पड़ता है...........

(व्यवधान)

अध्यक्ष: आप पूरक छोड़कर सब कुछ पूछ रहे हैं ?

डॉ0 रामानुज प्रसाद: महोदय, मैं कह रहा हूं कि आप गंडक नदी पर एक पुल और बनवा दीजिए.............

(व्यवधान)

अध्यक्ष: ठीक है अब हो गया, बैठिये ।

तारांकित प्रश्न संख्या: 794 (श्रीमती अरूणा देवी)

श्री नरेन्द्र नारायण यादव, मंत्री: महोदय, उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि नवादा जिले के पकरीबरावां प्रखण्ड अन्तर्गत ढोढ़ा पंचायत के रेबार गाँव के तालाब के आंशिक भाग में मिट्टी भर गयी है । इसके तीन चौथाई भाग में पानी है। किनारे में 6 इंच से 9 इंच एवं बीच में एक से डेढ़ फीट पानी है । महोदय, प्रश्नाधीन तालाब का सर्वेक्षण कराया जायेगा । सर्वेक्षणोपरांत डी0पी0आर0 तैयार कर विहित प्रक्रिया के आधार पर अग्रेत्तर कार्रवाई की जायगी ।

अध्यक्ष: ठीक है ।

तारांकित प्रश्न संख्या: 795 (श्रीमती अमिता भूषण)

(माननीय सदस्या अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या: 796 (श्री सीताराम यादव)

श्री शैलेश कुमार, मंत्री: महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ की लम्बाई 0.74 कि0मी0 है । बासोपट्टी मुख्य सड़क से अरधवा टोला हनुमाननगर के नाम से एम0एम0जी0एस0वाई0 अन्तर्गत स्वीकृत है, जो निविदा की प्रक्रिया में है । निविदा की प्रक्रिया पूरी कर निर्माण कार्य कराया जायेगा ।

श्री सीताराम यादव: महोदय, कब तक समय सीमा बता दीजिए ?

श्री शैलेश कुमार, मंत्री: महोदय, उसको जल्दी ही पूरा करा दिया जायगा ।

अध्यक्ष: ठीक है । अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ । जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों उन्हें सदन पटल पर रख दिये जायं ।

श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह: महोदय, मेरा तारांकित प्रश्न था इसके बाद हुजूर ।

अध्यक्ष: अब तो आगे बढ़ गये हैं, आप लिखकर दीजियेगा, हम देखेंगे ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 04.03.2020 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है- श्री समीर कुमार महासेठ, श्री राजेन्द्र कुमार, श्री कुमार कृष्ण मोहन, श्री संजय कुमार तिवारी, श्री मो0 नवाज आलम एवं श्री सुधीर कुमार । आज सदन में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए आय-व्ययक पर सम्मिलित अनुदान मांगों पर वाद-विवाद एवं मतदान का कार्यक्रम निर्धारित है, अतएव बिहार विधान सभा की प्रकिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-172(3) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना को अमान्य किया जाता है ।

टर्न-7/सत्येन्द्र-मुकुल/04-03-2020

अध्यक्ष: अब शून्यकाल ।

<u>शून्यकाल</u>

श्री समीर कुमार महासेठ: अध्यक्ष महोदय, जिस चीज के लिए लाया गया है, कम से कम उसको पढ़कर सुना देते हैं।

अध्यक्ष महोदय, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली 97-98 के तहत अत्यंत लोक महत्व के विषय पर सदन का कार्य स्थगित कर बहस की मांग करता हूॅ।

श्री श्रवण कुमार,मंत्री: इसका औचित्य क्या है महोदय?

(व्यवधान)

श्री समीर कुमार महासेठ: सर, कार्यस्थगन प्रस्ताव दिये हैं। सरकार द्वारा आयोजित दिसम्बर, 2019 में दारोगा बहाली हेतु पुलिस अवर सेवा चयन पर्षद द्वारा लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया था..

अध्यक्ष: ठीक है, इसको रख दीजिये, सदन पटल पर रख दीजिये।

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव।

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव: महोदय, दिनांक- 02 जून, 2017 को जहानाबाद प्रखण्ड+जिला के ग्राम अमैन निवासी (1) मान्ती देवी पति सुरेश डोम (2) शर्मिला देवी पति उमेश डोम (3) उर्मिला देवी पति सोना डोम की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। मैं सरकार से पीड़ित परिवारों को सरकारी नियमानुसार चार-चार लाख रुपया मुआवजा की मांग करता हूं।

श्री विनोद प्रसाद यादव: अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा इंटर पास विद्यार्थियों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि गया जिला में वित्तीय वर्ष-2015-16, 2016-17, 2017-18 एवं

2018-19 का अभी तक नहीं दिया गया है। विद्यार्थियों के हित में उक्त वर्णित वित्तीय वर्षों का प्रोत्साहन राशि अविलम्ब देने की माँग करता हूं।

श्री ललन पासवानः अध्यक्ष महोदय, रोहतास जिलान्तर्गत चेनारी प्रखंड के सोन उच्चस्तरीय नहर लाँजी से निकलने वाली तेलारी वितरणी में गाद भर जाने से निचले छोर तक पानी नहीं पहुंच पाता है, पटवन बाधित है। उक्त वितरणी की सफाई हेतु मांग करता हूं।

श्री समीर कुमार महासेठः अध्यक्ष महोदय, मधुबनी जिला मुख्यालय के वार्ड सं0-19 में 1918 में स्थापित गिरिधारी पब्लिक लाईब्रेरी का उपयोग वर्षों से ई.वी.एम. के रखने हेतु किया जा रहा है जबकि ई.वी.एम. के रखने हेतु नये भवन का निर्माण हो चुका है। पठन-पाठन बाधित है। अतः गिरिधारी पब्लिक लाईब्रेरी पुनः चालू किया जाय।

श्री विजय कुमार खेमकाः अध्यक्ष महोदय, पूर्णिया नगर-निगम वार्ड पन्द्रह मुर्गीफार्म लंकाटोला में वर्षों से बसे हुए सरकारी योजना प्राप्त लाभुकों को बगैर वैकल्पिक व्यवस्था किए बेघर कर खुले आसमान में छोड़ दिया गया है। अतः मैं विस्थापित किए गए सैकड़ों भूमिहीन गरीब परिवारों का पुनर्वास शीघ्र करने की मांग करता हूं।

श्री मदन मोहन तिवारीः अध्यक्ष महोदय, पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत नगर परिषद् बेतिया क्षेत्र के सागर पोखरा स्थित नवनिर्मित पार्क का नामकरण महारानी जानकी कुंअर पार्क करने की मांग करता हूं।

श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारीः अध्यक्ष महोदय, बक्सर जिला के सदन प्रखण्ड में जाम की स्थिति बनी रहती है। लेकिन आई.टी.आई. फील्ड के बगल से निकलने वाली सड़क जो कटहिया पुल तक जाती है। उक्त सड़क का पुनर्निर्माण कराकर बाईपास के रूप में इस्तेमाल कराने की मांग करता हूं।

श्रीमती पूनम देवी यादवः अध्यक्ष महोदय, गंगा देवी लगभग 20 वर्षों से अधिक खगड़िया प्रखण्ड में राजस्व कर्मचारी के पद पर पदस्थापित हैं। जबकि सरकार के नियमानुसार किसी भी पदाधिकारी को एक ही जिले में 3 वर्ष से अधिक नहीं रहना है। सरकार गंगा देवी को अविलम्ब खगड़िया जिले से स्थानांतरित करावें।

डॉ0 मो0 नवाज आलमः अध्यक्ष महोदय, भोजपुर जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का कार्यालय निर्माण हेतु प्रधान सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग पटना के पत्रांक-4503, दिनांक-01.03.2018 के अनुसार जिला पदाधिकारी, भोजपुर को निदेशित किया था। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं उक्त कार्यालय के निर्माण की मांग करता हूं।

डॉ0 शमीम अहमदः अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चम्पारण जिला के छौड़ादानों प्रखंड अन्तर्गत गोलापकड़िया घाट में बने लोहे का पुल वर्ष 2017 में आये भयंकर बाढ़ के कारण

क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण आवागमन बाधित है। उक्त स्थान पर नया आर.सी.सी. पुल का निर्माण कराया जाय।

श्री सुधीर कुमार उर्फ बंटी चौधरी: अध्यक्ष महोदय, जमूई जिलान्तर्गत खैरा प्रखंड के पंचायत-गोली से निमनवादा पंचायत को जोड़ने वाली कसोईया से ओझवाडीह गांव के पास अरघोति नदी पर पुल का निर्माण करवों।

श्री राजेन्द्र कुमार: अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2018 में हरसिद्धि प्रखण्ड अन्तर्गत पान्नापुर रंजीता पंचायत निवासी विन्दा प्रसाद यादव घर में आग लगने से तीन जरसी गाय जलकर मर गई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सहित अंचलाधिकारी द्वारा सरकार को मुआवजा हेतु भेजी गई है। परन्तु अभी तक अनुदान नहीं मिला। अत: अविलम्ब मुआवजा दें।

श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव: अध्यक्ष महोदय, पूर्वीचम्पारण जिला के चकिया प्रखंडान्तर्गत चिन्तामनपुर पंचायत के सीताकुंड से टिकुलिया जानेवाली पथ में लखना नहर में अवस्थित पुल क्षतिग्रस्त है। जिससे बड़े गाड़ियों का संचालन बन्द है एवं आवागमन बाधित है। किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है। उक्त पुल के जगह नया आर.सी.सी. पुल का निर्माण करावें।

श्री संजय सरावगी: अध्यक्ष महोदय, दरभंगा शहर में ''कबीर अंत्येष्ठि योजना'' (गरीबी रेखा से नीचे के सदस्यों की मौत पर मिलने वाली 3000/- की राशि) की राशि निगम पार्षदों के बैंक खाता में नहीं रहने के कारण दरभंगा शहर के गरीब लोगों को इस योजना से वंचित रहना पड़ रहा है। अत: राशि भेजवाने की कृपा करें।

श्री नरेन्द्र कुमार नीरज: अध्यक्ष महोदय, भागलपुर से गंगा नदी के विक्रमशीला सेतु पर पदाधिकारियों की मिली-भगत से ओभर लोडेड ट्रकों के परिचालन एवं बीच सेतु पर ट्रकों का गुल्ला टूट जाने के कारण हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है। अतएव सरकार ओवरलोडेड ट्रक के परिचालन पर रोक लगाये।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, राज्य के सैकड़ों उच्च प्राथमिक शिक्षकों (6 से 8) को बिहार विश्वविद्यालय के दूरस्त शिक्षा निदेशालय द्वारा बी.ई.डी. कोर्स की परीक्षा नहीं लेने से अप्रशिक्षित होने के कारण सेवा मुक्ति का सरकार ने आदेश दिया है। शीघ्र परीक्षा आयोजित करने तथा सेवा मुक्ति आदेश को निरस्त करने हेतु सरकार से मांग करता हूं।

श्री विद्या सागर केसरी: अध्यक्ष महोदय, फारबिसगंज विधान सभा अन्तर्गत कुसमाहा पंचायत के आमगाछी महादलित टोला जाने वाली सड़क जो बॉर्डर रोड से चलकर नेपाल सीमा तक जाती है। बॉर्डर रोड से सटे उच्चस्तरीय पुल नहीं रहने से महादलित टोला के 2000 आबादी वाले गांव को बाढ़ का दंश झेलना पड़ता है। मैं पुल निर्माण की मांग करता हूं।

श्री शत्रुघन तिवारी: अध्यक्ष महोदय, सारण जिलान्तर्गत सोनहो से अमनौर के बीच एस.एच.-73 पर अक्सर वाहन दुर्घटनाएं होती हैं। इस क्षेत्र में ट्रामा सेंटर नहीं होने के कारण घायलों की तत्काल चिकित्सा के अभाव में मृत्यु हो जाती है। मैं अमनौर में ट्रामा सेन्टर स्थापित करने की मांग करता हूं।

श्री सुदामा प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, 2 नवम्बर, 2017 को छात्र आकाश कुमार उर्फ छोटू, पिता-रविशंकर सिंह उर्फ भूपेन्द्र सिंह, ग्राम-पोस्ट-थाना अगिआंव बाजार, जिला-भोजपुर की दर्दनाक मौत पीरो-अगिआंव बाजार पथ पर बिजली प्रवाहित कदम के पेड़ में सटकर हो गई थी। मैं मृतक के परिवार को पर्याप्त मुआवजा की मांग करता हूं।

श्री रामदेव राय: अध्यक्ष महोदय, बेगूसराय जिला के मंसूरचक प्रखंड अन्तर्गत गणपतौल पंचायत वार्ड-13 के मधुर कुमार, पिता दिलीप पासवान, आर्यन कुमार, पिता मनोज पासवान की मृत्यु 11.11.2019 को बलान नदी में एक साथ डूबने से हो गई। परन्तु अब तक इस गरीब परिवार को कोई सरकारी अनुदान नहीं दिया गया है।

अध्यक्ष: अब ध्यानाकर्षण सूचना।

टर्न-8/मधुप-हेमंत/04.03.2020

ध्यानाकर्षण सूचनाएँ तथा उसपर सरकारी वक्तव्य

सर्वश्री रत्नेश सादा, रामप्रीत पासवान एवं अन्य पॉच सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार [जल संसाधन विभाग] की ओर से वक्तव्य ।

श्री रत्नेश सादा : अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य के कोसी बराज नदी में वर्ष 1965 से कोसी नदी से कुरसैला तक नेपाल के तराई क्षेत्र से काफी मात्रा में बालू जमाव के कारण कोसी नदी के पूर्वी एवं पश्चिमी तटबंध पर खतरा मंडराता रहता है । वर्ष 1965 में गंडौल के निकट, वर्ष 1984 में नौहट्टा के निकट एवं वर्ष 1987 में घोंघेपुर के निकट पूर्वी एवं पश्चिमी तटबंध टूट गया था, जिसके कारण काफी जान-माल का नुकसान हुआ था । कोसी नदी के बीच की उपजाऊ बसावट योग्य जमीन कोसी की धार में बह जाती है, जिसके चलते कोसी के बीच में बसे लोगों को एक जगह से दूसरी जगह झोपड़ी बनाकर जीवन-यापन करना पड़ता है ।

अत: कोसी बराज नदी से कुरसैला तक नदी में गाद की सफाई हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, कोसी नदी नेपाल से निकलकर बिहार के कुरसैला में गंगा नदी से मिलती है । प्रतिवर्ष कोसी बराज के 52 कि0मी0 अप-स्ट्रीम एवं 125 कि0मी0 डाउन-स्ट्रीम में सर्वेक्षण कराया जा रहा है । प्राप्त सर्वेक्षण आंकड़ों के आधार पर सी0डब्लू0पी0आर0एस0 सेन्ट्रल वाटर पावर रिसर्च इंस्टीच्यूट सर्वे, पुणे में संधारित कोसी नदी एवं बराज के भौतिक प्रतिमान को अद्यतन किया जाता है । भौतिक प्रतिमान के आधार पर विश्व बैंक सम्पोषित योजना के तहत वृहद स्तर पर रिवर-स्ट्रिमिंग कार्य कराया जाता है तथा कोसी उच्चस्तरीय समिति की अनुशंसा के आलोक में आवश्यकतानुसार कोसी बराज के अप-स्ट्रीम एवं डाउन-स्ट्रीम में चैनल के सक्रियन का कार्य कराकर नदी के बहाव को केन्द्रीकृत रखा जाता है ।

साथ-ही-साथ, कोसी उच्चस्तरीय समिति की अनुशंसा के आलोक में प्रतिवर्ष राज्य योजना, केन्द्र क्षेत्र योजना के तहत कटाव निरोधक कार्य, बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य कराकर तटबंधों को सुरक्षित रखा जाता है ।

उपरोक्त खंडों के अन्तर्गत वर्णित कार्यों के कार्यान्वयन से विगत 10 वर्षों में तटबंध क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है । कोसी नदी अपने प्रवाह के साथ प्राकृतिक रूप से अत्यधिक गाद का संवहन करती है, जो औसतन प्रतिवर्ष लगभग 950 लाख घनमीटर है।

अत: कोसी बराज से कुरसैला तक नदी गाद सफाई तकनीकी, आर्थिक दृष्टिकोण से संभव नहीं है । वर्तमान में कोसी नदी की गाद सफाई का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

श्री रत्नेश सादा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि 1955 में कोसी बाँध का निर्माण किया गया था । कोसी नदी पूर्णियां, कटिहार, कुरसैला की तरफ बहती थी, महानंदा की तरफ बहती थी और 1955 में कोसी नदी को सीमित करके, 10 कि0मी0 के अंतराल में बाँधकर, जिससे कोसी वासियों को, कोसी नदी के बीच में रहने वाले लोगों का घर कट जाता है, खेती योग्य जमीन कट जाती है । मैं माननीय मंत्री से कहना चाहूंगा कि कबतक कोसी नदी में सिल्टेशन की उड़ाही का काम करायेंगे ?

अध्यक्ष : मंत्री जी ने बताया है कि कोसी नदी का सिल्ट निकालने की प्रक्रिया कैसे कर सकते हैं, उसके लिए जो उसके प्रबंधन की व्यवस्था होती है, वह कर रहे हैं ।

श्री रत्नेश सादा : इसके लिए तो अध्यक्ष महोदय, ये प्रस्ताव भेजकर, केन्द्र सरकार से राशि माँगकर, उसके बाद कोसी नदी सिल्टेशन की उड़ाही करावें ।

अध्यक्ष : उसको देखेंगे ।

सर्वश्री मोहम्मद नवाज आलम, यदुवंश कुमार यादव एवं भोला यादव, स0वि0स0 से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (वित्त विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्री मोहम्मद नवाज आलम : अध्यक्ष महोदय, पूरे बिहार में किसानों को कृषि ऋण देने में बैंक आनाकानी कर रहा है । लक्ष्य से काफी कम इस वर्ष ऋण का वितरण किया गया है। वर्ष 2019-20 में कृषि ऋण का लाभ जो किसानों को मिलना था, उससे काफी कम कृषि ऋण का वितरण किया गया । के0सी0सी0 की संख्या में भी लगातार कमी हो रही है ।

अत: किसानों को कृषि ऋण उपलब्ध कराने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।

अध्यक्ष : मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उपमुख्यमंत्री : महोदय, उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है । बैंकों द्वारा राज्य में कृषि ऋण वितरण करने में आनाकानी करने की शिकायतें समय-समय पर प्राप्त होती रहती हैं । प्राप्त शिकायतों पर त्वरित संज्ञान लेकर संबंधित बैंकों को कार्रवाई हेतु निदेश दिया जाता है । उसकी समीक्षा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठकों में की जाती है । वित्तीय वर्ष 2019-20 में 31 दिसम्बर, 2019 तक वार्षिक साख योजना के अंतर्गत बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र में 28,764 करोड़ रुपये ऋण वितरित किया गया है, जो कि निर्धारित लक्ष्य 60,000 करोड़ रुपये का 47.17 प्रतिशत है । पिछले वित्तीय वर्ष 2018-19 में वार्षिक साख योजना के अंतर्गत बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र में 43,621 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया गया था, जो कि निर्धारित लक्ष्य 60,000 करोड़ रुपये का 72.70 प्रतिशत था । इस वित्तीय वर्ष दिसम्बर, 2019 तक कृषि टर्म लोन के निर्धारित लक्ष्य 15,752 करोड़ के विरुद्ध 11,101 करोड़ रुपये किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत 13,393 करोड़ रुपये, कृषि यांत्रिकरण में लक्ष्य 3,755 करोड़ रुपये के विरुद्ध 270 करोड़ रुपये, कृषि आधारभूत संरचना में 4,390 के विरुद्ध 113 करोड़ रुपये, भंडारण सुविधा में निर्धारित लक्ष्य 3,144 करोड़ रुपये के विरुद्ध 14 करोड़ रुपये, खाद्य एवं कृषि प्रसंस्करण में निर्धारित लक्ष्य 3,347 करोड़ रुपये के विरुद्ध 694 करोड़ रुपये, डेयरी में लक्ष्य 4,029 करोड़ के विरुद्ध 861 करोड़ रुपये, मत्स्य में लक्ष्य 960 करोड़ रुपये के विरुद्ध 19 करोड़ रुपये, मुर्गी पालन में 1671 करोड़ रुपये के विरुद्ध 102 करोड़ रुपये का साख वितरित किया गया है । अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2019-20 में दिसम्बर, 2019 तक 1,20,372 नये तथा 14,36,400 नवीकृत सहित कुल 15,56,772 किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण बैंकों के द्वारा किया गया है । किसान क्रेडिट कार्ड निर्गत करने हेतु फसल बीमा की अनिवार्यता पर जोर दिये जाने के कारण विगत कुछ वर्षों में नये किसान

क्रेडिट कार्ड की उपलब्धता कुछ कम रही है । सरकार द्वारा इस मुद्दे को वित्त विभाग, भारत सरकार के साथ उठाया गया था । जिसके बाद के0सी0सी0 ऋण हेतु फसल बीमा की अनिवार्यता को आर.बी.आई द्वारा समाप्त कर दिया गया है । कृषि क्षेत्र में ऋण बढ़ाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड में बगैर सम पार्श्विक प्रतिभूति के ऋण की सीमा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 लाख 60 हजार कर दी गयी है । साथ ही कृषि से संबंधित डेयरी, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन आदि को भी के0सी0सी0 के दायरे में शामिल किया गया है । किसानों को क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ दिलाने के उद्देश्य से कृषि विभाग द्वारा 12 फरवरी से 17 फरवरी, 2020 तक, 15 दिनों के लिए विशेष अभियान चलाया गया है । इस अभियान के अंतर्गत 3 मार्च तक 3,02,626 आवेदन किसानों से प्राप्त कर बैंकों में जमा करा दिया गया है । इनमें से 29,041 किसानों को बैंकों के द्वारा क्रेडिट कार्ड स्वीकृत कर दिया गया है । बिहार राज्य बैंकर्स समिति तथा इसकी उप समितियों में लगातार कृषि तथा कृषि से सम्बद्ध क्षेत्रों में ऋण वितरण की समीक्षा की जाती है तथा बैंकों को आवश्यक निर्देश दिये जाते हैं ।

श्री मो0 नवाज आलम : महोदय, माननीय वित्तमंत्री जी ने....

अध्यक्ष : बहुत विस्तार से जवाब दिया है ।

श्री मोहम्मद नवाज आलम : बहुत विस्तार से आंकड़ों की कलाबाजी करने का काम किया है। महोदय, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, मैं जिस जिले से आता हूं वहां अभी हाल में, मेरे पास उस पेपर की कटिंग है, किसानों ने वहां पर पूरी तरह से धरना-प्रदर्शन किया और कृषि लोन के मामले में, यही नहीं किसानों ने पूरे रोड को जाम किया जिसमें लाठीचार्ज भी हुई....

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री मोहम्मद नवाज आलम : महोदय, इसलिए हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं, आपने लक्ष्य की प्राप्ति करने में कहीं न कहीं चूक की है । इसलिए इस वित्तीय वर्ष 2019-20 में क्या आप उन तमाम बैंकों को निर्देश देने का विचार रखते हैं ? जो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो रही है, जो किसान आक्रोशित होकर कहीं न कहीं रोड पर धरना-प्रदर्शन दे रहे हैं, ऐसे लोगों के निदान के लिए आप कौन-सा कदम उठाना चाहते हैं ?

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री मोहम्मद नवाज आलम : नहीं महोदय, लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकी है ।

अध्यक्ष : वह तो कहे ही । खुद वे कह रहे हैं, आप कोई नई बात तो नहीं कह रहे हैं ।

टर्न-9/आजाद:अंजली/04.03.2020

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, प्रत्येक तीन माह पर राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक होती है । इसके अतिरिक्त एक एग्रीकल्चर की सब कमिटी बनी हुई है । जिसकी अलग से बैठक होती है । हम विस्तार से समीक्षा करते हैं कि बैंकों को आवश्यक निर्देश भी दिया जाता है और मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि पिछले 6 साल में 50 लाख से ज्यादा किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किया गया है और करीब एक करोड़ किसानों का किसान क्रेडिट कार्ड रिन्यूवल किया गया है । अब बैंकों का कहना है कि बिहार में बहुत कम किसान बचे हैं जिनको किसान क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता है । इसलिए हमारा काम है बैठक कर के उनसे आग्रह करना, ऋण वितरण करना बैंकों को, इसके लिए जो भी प्रयास करना संभव है, वे सारे प्रयास राज्य सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं और इसलिए अभी भारत सरकार का निर्देश था कि पी0एम0 किसान निधि का लाभ जिन किसानों को मिल रहा है, उन सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ दिलवाया जाए और उसी अभियान के तहत जो है तीन लाख से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए हैं और जिसमें से बैंकों से करीब 25 हजार किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड निर्गत कर दिया है ।

श्री भोला यादव : महोदय, माननीय मंत्री जी बता रहे हैं कि जिन अधिकांश किसानों को क्रेडिट कार्ड दे दिया गया है जबकि वास्तविकता यह है कि हमलोग भी गांव के रहने वाले हैं, गांव में रहते हैं, किसानों के बीच में रहते हैं तो हमने जो देखा है, एक गांव में 10 प्रतिशत लोगों को भी किसान क्रेडिट कार्ड अभी तक नहीं दिया गया है । क्या माननीय मंत्री जी बताएंगे कि किसान की संख्या कितना है और कितने लोगों को अभी तक इन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड वितरण किया ?

अध्यक्ष : संख्या बताये हैं न अभी ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने तो अभी बताया, पिछले 6 साल में 49 लाख 65 हजार नए किसान क्रेडिट कार्ड निर्गत किए गए यानी लगभग 50 लाख नए किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिया गया और एक करोड़ 6 साल में..

श्री भोला यादव : अध्यक्ष महोदय, कितना के विरुद्ध, कितने किसान हैं, उसके विरुद्ध इतना.....

श्री सुशील कुमार मोदी, उपमुख्यमंत्री : बात सुन लीजिए न, और 1 करोड़ 7 लाख किसान क्रेडिट कार्ड का रिन्यूवल किया गया, इसका मतलब है कि बिहार में करीब एक करोड़ किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिया जा चुका है । बैंकों का यह कहना है कि एन0पी0ए0 बहुत ज्यादा है । करीब 24 प्रतिशत से ज्यादा एन0पी0ए0 है

फिर भी हमलोगों के दबाव में बैंक किसानों को ऋण दे रहे हैं और कोई भी आवेदन अगर आयेगा, इसलिए किसान सलाहकारों को लगाकर और पूरे बिहार में आवेदन संग्रह किया गया है और 15 दिन के अभियान में 3 लाख नए आवेदन आये हैं तो आप आवेदन दीजिए और जो आवेदन आयेंगे उनको हम दिलवाने का काम करेंगे । बैंकों का कहना है कि आवेदन उस मात्रा में नहीं आ रहे हैं, चूँकि अधिकांश किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिया जा चुका है, फिर भी जो बचे हुए किसान हैं, उन किसानों को आवेदन आप भेजवाइए । हमलोग दिलवाने का काम करेंगे ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री भोला यादव : महोदय, माननीय मंत्री जी जो कह रहे हैं अधिकांश किसानों को दिया जा चुका है, हम अपने क्षेत्र में तो देखते हैं कि 10 प्रतिशत लोगों के पास भी नहीं है किसान क्रेडिट कार्ड और कह रहे हैं कि अधिकांश को दे दिया गया है, ये केवल आंकड़ा विभाग के द्वारा माननीय मंत्री जी को दिया जा रहा है, वास्तविकता जमीन पर नहीं है ।

अध्यक्ष : उन्होंने अधिकांश ही नहीं कहा है, फीगर भी दिया है, लगभग 1 करोड़ का रिन्यूवल भी हुआ है, 49 लाख को नया दिया गया है ।

अब सभा की कार्यवाही 2.00 बजे दिन के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न-10/शंभु-धिरेन्द्र/04.03.20

(अंतराल के बाद)

(इस अवसर पर अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । अब वित्तीय कार्य लिये जायेंगे और इसके पहले मुझे एक सूचना देनी है कि आज ही 3 बजे कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक अध्यक्षीय कार्यालय में बुलाई गई है । जितने भी हमारे कार्य-मंत्रणा समिति के सदस्य हैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध होगा कि उस बैठक में भाग लेने की कृपा करें।

माननीय सदस्यगण, जल संसाधन विभाग के अनुदान की मांग पर वाद-विवाद, सरकार का उत्तर एवं मतदान होगा । इसके लिए 3 घंटे का समय उपलब्ध है । विभिन्न दलों को उनकी सदस्य संख्या के आधार पर समय का आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है । इसी समय में से सरकार को उत्तर के लिए भी समय दिया जाएगा ।

राष्ट्रीय जनता दल	- 60 मिनट,
जनता दल यूनाइटेड	- 51 मिनट,
भारतीय जनता पार्टी	- 40 मिनट,
इंडियन नेशनल कांग्रेस	- 19 मिनट,
सी0पी0आई0एम0एल0	- 2 मिनट,
लोक जनशक्ति पार्टी	- 2 मिनट,
हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा	- 1 मिनट,
ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादूल मुस्लमीन	- 1 मिनट,
निर्दलीय	- 4 मिनट ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग अपनी मांग प्रस्तुत करें ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''जल संसाधन विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 40,53,61,19,000 (चालीस अरब तिरपन करोड़ एकसठ लाख उन्नीस हजार) रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाए ''

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

अध्यक्ष : इस मांग पर माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव, श्री समीर कुमार महासेठ, श्री रामदेव राय, श्री मो0 नेमतुल्लाह एवं श्री कुमार सर्वजीत से कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए

हैं । ये सभी व्यापक हैं, जिनपर सभी माननीय सदस्य विचार विमर्श कर सकते हैं। माननीय सदस्य,श्री ललित कुमार यादव का प्रस्ताव प्रथम है । अतएव माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''इस शीर्षक की मांग 10 रूपये से घटाई जाय ।''

महोदय, मेरे दल की तरफ से नाम दिया हुआ है ।

अध्यक्ष : श्री यदुवंश कुमार यादव ।

श्री यदुवंश कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष की तरफ से प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । अध्यक्ष महोदय, बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है और कृषि प्रधान राज्य होने के नाते बिहार का विकास जल संपदा के प्रबंधन पर निर्भर करता है । मेरा मानना है कि बिना कृषि एवं किसान के विकास हुए राज्य का विकास नहीं हो सकता है । महोदय, जल संसाधान विभाग, लघु जल संसाधान विभाग आम लोगों के किसान से और मानव से संबंधित विभाग है और इस विभाग के माध्यम से जल का प्रबंधन, किसान खेती के लिए सिंचाई और व्यवस्था प्रबंधन करना और बाढ़ के समय में बाढ़ से आम आवाम की रक्षा करना मुख्य उद्देश्य है। अध्यक्ष महोदय, बाढ़ बिहार के लिए वरदान है या बिहार के लिए अभिशाप है। नेपाल से गुजरने वाली सारी नदियॉं, बिहार के मैदानी इलाके में आकर के तबाही मचाने का काम करती है और बिहार के क्षेत्रफल का 68.80 लाख हेक्टेयर में जो बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का 73.6 प्रतिशत है में तबाही मचाने का काम करती है। इसमें जो हमारी व्यवस्था है, सरकार की तरफ से जो बजट प्रस्तुत किया गया है, उसमें उन्होंने बतलाया है कि हम 8 गुना बजट में हमने वृद्धि की है । जिस अनुपात में यह बजट में वृद्धि करते जा रहे हैं, उसी अनुपात में राज्य में बाढ़ की स्थिति भी बढ़ती जा रही है । जिन जिलों में, जिन क्षेत्रों में बाढ़ का पानी नहीं जाता था, आज उन क्षेत्रों में भी बाढ़ का पानी जा कर के लोगों के जन-जीवन को प्रभावित करता है । इससे बिहार के लोगों की तबाही होती है जो प्रबंधन की बात इन्होंने कही है या बजटीय प्रावधान इन्होंने किया है यह विडंबना है कि हमारी सरकार बाढ़ रोकने या जल के प्रबंधन की सफलता के लिए पीठ भले ही थप-थपा दें, लेकिन आज तक इन्होंने चूहों की और गिलहरी, गीदड़, खिखिर और शाही जैसे पशु से भी सुरक्षा की व्यवस्था सरकार के द्वारा नहीं की जा सकी हैं ।

क्रमशः

टर्न-11/04-03-2020/ज्योति-पुलकित

क्रमशः

श्री यदुवंश कुमार यादव : आज अस्पताल में चूहा स्लाईन पी जाता है । थाने में चूहा दारू पी जाता है और चूहा वहीं नहीं रूकता, बांध को कुरेदकर के उद्घाटन से पूर्व अपना उद्घाटन कर देता है और उस बांध को बर्बाद कर देता है । ये ऐसी व्यवस्था हमारे राज्य में जल प्रबंधन और बाढ़ से सुरक्षा के लिए है । इन चूहों के बारे में हम लोगों को या सरकार को चाहिए कि इसकी जांच करावें और इतना शक्तिशाली अगर चूहा है तो उनको रोक लगाने की व्यवस्था करें लेकिन आज तक ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकी है । महोदय, जल ही जीवन है, जल के बिना हमारा कोई भी काम चल नहीं सकता । जल की ओर आज एक तरफ जल से तबाही है और दूसरी तरफ जल का संकट है और आने वाले समय में ये संकट और भी बढ़ने वाला है इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि पुराने इतिहास में भी या हम लोगों के शास्त्र में ऐसी चर्चा है कि बाढ़ से जो हमारे पुर्खे या ऋषि-मुनि थे, उन्होंने समुद्र को उठाकर के पी लिया और इस बार ये इसका इतिहास रहा है कि जल संसाधन मंत्री जो भी आये, वे या तो यहॉं से दिल्ली चले गए या उस घर चले गए और व्यवस्था हम लोगों का यूँ ही पड़ा रहा और लगा रहा, बना रहा । मैं माननीय मंत्री जी से भी कहना चाहता हूँ कि आप अगस्त मुनि के ही वंशज संतान है । इस कोसी इस बाढ़ की त्रासदी से बिहार को मुक्ति दिलाने के लिए और आपको अच्छा मौका मिला है माननीय मंत्री जी ने आपको दिया है । आप इस बाढ़ को उठाकर के ग्रहण कर लें और पी लें और बिहार को मुक्ति दिलाने का काम किया है । आज तक तो लोगों ने बजट का जो अंश है हिस्सा है, राशि है उसको ही पीने का काम किया है आप कम से कम बाढ़ को पी करके इस राज्य को मुक्ति दिलाने का काम करेंगे । अध्यक्ष महोदय, नेपाल से जो नदियाँ निकलती है, वे बिहार में अपना तांडव मचाने का काम करती है, चाहे कोसी हो, महानंदा हो, गंडक हो, बाघमती हो तमाम नदियों के ऊपर सरकार ने बड़ी-बड़ी योजनाएँ चलाने का काम किया है । डैम बनाने की बात कही है, कोसी योजना के विषय में जैसी हमको जानकारी है कि कोसी योजना को बहुदेशीय योजना के रूप में लिया गया था इस योजना से सिंचाई, बिजली और सुरक्षा की बात की गई थी तो विचार धारा थी । एक बांध के पक्ष में और एक विपक्ष में, उस समय भी विपक्ष में रहते हुए जब राज्य में प्रजातंत्र आया देश में तो जनप्रतिनिधि के दबाव में आकर के बांध की योजना की स्वीकृति दी गई । हमारे जो पुराने

इंजीनियर थे, उस समय, उन्होंने विभिन्न-विभिन्न बैठकें करके बांध को स्थाई निदान नहीं माना था लेकिन उस समय में भी दबाव में आकर के ये बांध बनाया गया, कोसी के दोनों तरफ में और सबसे दुखद बात है । अध्यक्ष महोदय, जिस योजना की जहां से शुरूआत की गई थी उस योजना को जिस रूट में जाना था उसका दिशा बदल दिया गया और जो ऐलाइन्मेंट था उसका कोसी का, तटबंध बनाने का, उस ऐलाइन्मेंट को बदल करके दूसरे ऐलाइन्मेंट से कोसी के बांध को बनाने का काम किया गया और एक बात इसमें सत्य है कि इसका सर्वे करा लें कि जो भाग चुना गया उस भाग में बसने वाले तमाम पिछड़े दलित और अति पिछड़े वर्ग के लोग ही बसे हुए हैं जिनको बाढ़ की तबाही ने पूरे जीवन खानदान-दर-खानदान, पुस्त-दर-पुस्त तक रहने के लिए मजबूर किया गया । उसके बाद भी जो तटबंध बना उस तटबंध से लोगों के कल्याण होने की बात नहीं है । आज जो कोसी की स्थिति है कोसी नदी जब बिहार के भूभाग में प्रवेश करती है तो अपने साथ लाने वाली गाद से पूरे नदी तल को भरने का काम किया है और उस नदी से आज स्थिति यह है कि जो माननीय मंत्री जी या विभाग का है जो कोसी प्रतिवर्ष अपने साथ 3 इंच गाद लाने का काम करती है 1955 ई0 में श्री बाबू के हाथ से कोसी तटबंध का निर्माण का कार्य प्रारम्भ हुआ और 1954 में यह तटबंध बन करके तैयार हुआ । अगर इस एक वर्ष को हम जोड़ते हैं और 2 इंच के दर से ही अगर प्रति वर्ष गाद जमने की बात होती है तो 65 दुना 70 इंच लगभग 11-12 फीट की ऊंचाई पर आज नदी तल की ऊंचाई 11 से 12 फीट हो गया है और 11 से 12 फीट आज बांध की भी ऊंचाई नहीं है । इसमें दिया गया है कि बांध की योजना को...

अध्यक्ष : अब आपको एक मिनट में समाप्त करना होगा ।

श्री यदुवंश कुमार यादव : कितना मिनट दिए हैं ?

अध्यक्ष : जितना मिनट दिए हैं उसी में एक मिनट बचा हुआ है ।

श्री यदुवंश कुमार यादव : तो मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ कि आज के रत्नेश जी के द्वारा ध्यानाकर्षण भी लाया गया था । बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यानाकर्षण था इस बीच में लोगों के साथ प्रारम्भ में जो अन्याय हुआ था उस अन्याय से अगर मुक्ति दिलाने की बात अगर सरकार सोचती है तो आज बांध की चौड़ाई एक बांध से दूसरे बांध की दूरी 7 से लेकर 27 कि.मी. है और 125 कि.मी. लम्बाई में है इतने बड़े भू-भाग में कोसी आज अपनी लीला चलाती है और इसकी लीला जब बढ़ती है तो पूर्वी एवं पश्चिमी तटबंध को समय-समय पर ये आज तक चार बार तोड़ चुकी है । दो बार पूर्वी तटबंध को, दो बार पश्चिमी तटबंध को और

एक बार पूर्वी को तोड़ती है तो दूसरी बार में पश्चिमी को तोड़ती है । आने वाले समय में जो नदी तल की ऊंचाई है और पानी की जो स्थिति है और तटबंध की जो स्थिति है इसमें दो कल्याणकारी योजना चलायी गयी है । हमने देखा है इस बजट में है और यह योजना है बाबू ललन सिंह योजना ।

अध्यक्ष : अब आप समाप्त करिये ।

श्री यदुवंश कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, उस योजना के तहत जो योजना चली जो दक्षिण भारत के सभी ब्लैक लिस्टेड कंपनी के ठेकेदार द्वारा किया गया और वह पौने दो सौ करोड़ की योजना ज्यों की त्यों पड़ी हुई है ।

अध्यक्ष : ठीक है, समाप्त हुआ । श्री निरंजन कुमार मेहता ।

श्री निरंजन कुमार मेहता : माननीय अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र के इस पवित्र सदन में वर्ष 2020-21 के अनुपूरक व्यय विवरणी पर सरकार द्वारा प्रस्तुत अनुदान की मांग संख्या 49 के समर्थन पर बोलने का अवसर दिया । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ । महोदय, मैं आपके माध्यम से आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने...

अध्यक्ष : निरंजन जी आपको 10 मिनट में समाप्त करना होगा इसलिए उसी अनुपात से प्राथमिकता कर लीजिये ।

टर्न-12/कृष्ण/04.03.2020

श्री निरंजन कुमार मेहता : महोदय, मैं आपके माध्यम से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने न्याय के साथ विकास करने के लिये दृढ संकल्प को धरातल पर उतार दिया, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू का एवं उप मुख्यमंत्री महोदय का, माननीय जल संसाधन मंत्री महोदय का, माननीय संसदीय कार्य मंत्री महोदय का, माननीय लघु जल संसाधन एवं विधि विभाग मंत्री महोदय का तथा माननीय मंत्री महोदय का, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मंत्री महोदय का भी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय, जल संसाधन विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है । हम भी कोसी इलाके से आते हैं और जितनी भी नहरें हमारे कोसी इलाके में निकली हैं, जल संसाधन विभाग ही उसको देखती है ।

(इस अवसर पर माननीय सभापति,श्री मो0 नेमतुल्लाह ने आसन ग्रहण किया)

और उस नहर प्रणाली के द्वारा सबों के खेतों तक पानी पहुंचाने का काम जल संसाधन विभाग द्वारा किया जाता है । बस, 2008 के त्रासदी में जितने भी नहर प्रणाली डैमेज हुये थे जल संसाधन विभाग द्वारा माननीय मुख्यमंत्री की

कृपा से आज सब नहर प्रणाली लंबे अरसे से काम करना शुरू कर दिया है और रब्बी का फसल हो, खरीफ का फसल हो, सबों के खेतों में पानी समय पर दी जाती है । जल संसाधन विभाग की जो उपलब्धियां हैं, मैं उन्हें बताने जा रहा हूं ।

महोदय, राज्य के विकास में सिंचाई का महत्वपूर्ण योगदान है । इसकी सुविधा बढ़ाने हेतु बड़ी योजनाओं के साथ-साथ छोटी-छोटी योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर कार्यान्वयन कराया जा रहा है । वर्ष 2019-20 में कुल 78000 हेक्टेअर क्षेत्र में नये सिंचाई सृजन एवं 1 लाख 12 हजार हेक्टेअर क्षेत्र में ह्रासित सिंचाई क्षमता को पुनर्स्थापित करने का लक्ष्य है और इसके लिये आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं ।

महोदय, सामान्य से कम वर्षापात होने पर वर्ष 2019-20 की खरीफ में 19.12 लाख हेक्टेअर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है । इससे राज्य में किसानों को धान की खेती में बड़ी सुविधा हुई । हरेक मौसमी फसल में चाहे वह रब्बी का हो, खरीफ का हो, समयानुसार जल संसाधन विभाग द्वारा नहर प्रणाली के द्वारा खेतों में ससमय पानी पहुचाया जाता है ।

सभापति महोदय, राज्य की फ्लैकशीप योजना जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत जो अभी माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा 19 जुलाई,2019 को जो इसी विस्तारित भवन में बहुत बड़ा अभियान चलाकर बहुत ही नई योजना का और जल जीवन-हरियाली अभियान का पूरे बिहार राज्य का दौरा करके धरातल पर उतार दिया गया है । अभियान के तहत गंगा जल उद्वह योजना प्रारंभ किया जा रहा है। यह राज्य सरकार की अत्यंत ही महत्वकांक्षी बहुदेशीय योजना है । इसका उद्देश्य गया, राजगीर एवं नवादा को पेयजल उपलब्ध कराना है ।

महोदय, फल्गु नदी के तट पर बसा हुआ गया शहर पर्यटन के दृष्टिकोण से विश्व के मानचित्र पर है । सभापति महोदय, गंगा नदी के जल को मॉनसून अवधि में मोकामा के पास मराची से उद्वह कर लगभग 140 किलोमीटर पाईप लाईन के द्वारा गया, बोध गया, राजगीर एवं नवादा भेज दिया जायेगा । इसका भण्डारण घोडाकटोरा झील एवं राजगीर तथा गया में प्रस्तावित दो अन्य जलाशयों में किया जायेगा । यह जब चालू हो जायेगा तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि इस विभाग की होगी । योजना के तहत जल शोधन संयंत्र भी स्थापित किया जायेगा । सभापति महोदय, फल्गु नदी का विशेष धार्मिक एवं पौराणिक महत्व है । पितृ पक्ष मे देश-विदेश के श्रधालु पिंडदान हेतु यहां पहुंचते हैं । इस दृष्टिकोण से यह आवश्ययक है कि फल्गु नदी में हमेशा कम से कम 0.60 मीटर जल उपलब्ध रहे। इसके लिये विभाग एक महत्वपूर्ण योजना का तकनीकी अध्ययन करा रही है ।

इसके कार्यान्वयन के उपरांत गया शहर के विष्णुपद मंदिर के पास फल्गु नदी में हमेशा जल की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी ।

सभापति महोदय, जल-जीवन-हरियाली योजना के अन्तर्गत बांका जिला के चंदन जलाश्रय क्षेत्र में वाटिका एवं निरीक्षण भवन के जिणोद्धार एवं सौंदर्यीकरण कार्य का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 09 जनवरी, 2020 को ही किया गया है ।

सभापति महोदय, कमाण्ड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम के अन्तर्गत योजनाओं के कुल कृषि योग्य का 10 प्रतिशत सुक्ष्म सिंचाई से आच्छादित करने का भी कार्यक्रम है । बाढ़ प्रबंधन की नयी योजना का उद्घाटन इस वर्ष पश्चिम चम्पारण में गंडक बराज बाल्मिकीनगर के अपस्ट्रीम भाग में इसके बायां तट पर 1080 मीटर की लंबाई में सुरक्षात्मक कार्य एवं बाल्मिकीनगर में नवनिर्मित ईको पार्क तथा ईको हाट का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा नवबर,2019 में भी संपन्न होने का भी काम हुआ है । इन कार्यों से बाल्मिकीनगर बराज एवं बाल्मिकीनगर टाईगर रिजर्व के अन्य क्षेत्र को भी सुरक्षा मिलेगी । इसके पूर्व बचाव की तैयारी प्रत्येक वर्ष बाढ़ से सुरक्षा हेतु वर्षा ऋतु के पूर्व तटबंधों की सुरक्षा हेतु आवश्यक तैयारी की जाती है । अगले वर्ष 2020 में संभावित बाढ़ के पूर्व पूरा करने हेतु 115 अदद योजनाओं की स्वीकृति दी जा चुकी है । सभापति महोदय, बाढ़ प्रबंधन हेतु गैर संरचनात्मक उपाय में भी बाढ़ पूर्वानुमान के लिये स्थापित गणीतीय प्रतिमान केन्द्र से मॉनसून की अवधि में आगामी 72 घंटे के लिये बाढ़ पूर्वानुमान मिलना शुरू हो जाता है । इसका लाभ बागमती, अधवारा, गंडक, कोसी एवं महानन्दा बेसीन के लोगों को भी मिल रहा है । गणीतीय प्रतिमान केन्द्र से तटबंधन सुरक्षात्मक योजनाओं को भी लाभ मिल रहा है ।

महोदय, पटना में जल ज्ञान केन्द्र की भी स्थापना की जा रही है ।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि लघु जल संसाधन विभाग के माननीय मंत्री भी बहुत ही लगनशील हो कर अपने विभाग में कार्य कर रहे हैं । आम जनता के कार्यो को भी मूर्त्त रूप देने का काम कर रहे हैं । अभी-अभी जो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 13 जुलाई, 2019 को जल-जीवन-हरियाली का जो आविष्कार करके धरातल पर उतारा गया है, उसमें लघु जल संसाधन विभाग द्वारा वर्ष 2019-20 में 202 पईन, तालाब एव बीयर योजनाओं में 189 योजनायें पूर्ण की गयी है ।

सभापति (श्री मो0 नेमतुल्लाह) : आप 2 मिनट में समाप्त कीजिये ।

श्री निरंजन कुमार मेहता : शेष योजना 90 प्रतिशत तक पूर्ण हो चुकी है । लघु जल संसाधन विभाग के द्वारा भी माननीय मंत्री महोदय काम कर रहे हैं । अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के माननीय मंत्री द्वारा भी बहुत अच्छे तरीक से काम कर रहे है ।

महोदय, दो मिनट बचा है, सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान थोड़ा आपके माध्यम से अपने क्षेत्र की तरफ आकृष्ट करना चाहूंगा । मैंने इनसे मांग किया था कि 30.07.2019 को, कि झिटकिया क्लोंधा एक पंचायत है, वहां एक छोटी-सी पुल की जरूरत है । दोनों तरफ पी0सी0सी0 सड़क बनी हुई है, बीच में कैनाल है और उस पार महादलित का टोला है और इस पार भी महादलित का टोला है, वहां पर एक छोटा पुल की मांग किये थे लेकिन माननीय मंत्री के द्वारा हुआ कि अब हमलोग पुल नहीं बनाते हैं, ग्रामीण कार्य विभाग पुल बनाता है, हम एन0ओ0सी0 दे देंगे । इसके अलावे और दो मांग किये थे जिसकी ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करेंगे, बिहारीगंज विधान सभा के अन्तर्गत कुमारखांड प्रखंड के चण्डी थान से बेंगा नदी मुरलीगंज प्रखंड होते हुये तिलकोरा एवं ग्वालपाड़ा प्रखंड के बीरगांव चतरा तक गाद है, थोड़ा-सी वर्षा होती है तो मुरलीगंज नगर पंचायत है, वार्ड नंबर-1, 2, 8 एवं 12, रहिका टोला तुरंत जलप्लावित हो जाता है, ओवरफ्लो हो जाता है । अगर उसके गाद की सफाई हो जाती है तो उससे इतना होगा कि अनेक गांव रतनपट्टी, भेलाही, रघुनाथपुर, गंगापुर, रमनी, तिलकोरा, ग्वालपाड़ा वीरगांव, चतरा तक गाद की पूरी सफाई हो जायेगी तो इन सबों को लाभ मिलेगा ।

महोदय, एक और मांग किये थे कि बार-बार पानी से कटाव होता है और विभाग को परेशानी होती है । हरेक साल इमरजेंसी वर्क वहां पर किया जाता है, विभाग द्वारा हम धन्यवाद देंगे और जब-जब टोला का कटाव होता है, हमने बोल्डर पीचिंग की मांग की थी, अपने क्षेत्र में चार जगहों के लिये मुरलीगंज प्रखंड के वीरापट्टी, सखुआ पंचायत के अन्तर्गत रमेश यादव के घर से पूरब सुरसर नदी में कटाव जारी है, इस टोला पर मांग किये थे । मुरंलीगंज प्रखंड के दिनापट्टी के सखुआ पंचायत के वृंदावन में भी हम मांग किये थे । तीसरा है, ग्वालपाड़ा प्रखंड में मधेपूरा सुखासन पंचायत के अंदर बभनगामा बिंदटोली में कटाव होता है, उसका रास्ता भी नहीं रहता है, टोला पर जाने के लिये ।

सभापति (श्री मे0 नेमतुल्लाह) : अब आप समाप्त कीजिये ।

टर्न-13/अंजनी/04.03.2020

श्रीमती गायत्री देवी : सभापति महोदय, मैं वर्ष 2020-21 के लिए पेश जल संसाधन विभाग की मांग पर लाये गये कटौती प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं ।

महोदय, जल, नदी और मानव सभ्यता का अटूट संबंध रहा है और यही वजह है कि मानव सभ्यता का विकास नदी किनारे हुआ । आधुनिकता की अंधी दौर में हाल के वर्षों में जल श्रोत का तेजी से दोहन किया जा रहा है, जिसके कारण आज जल संकट की स्थिति है। महोदय, बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जल संकट से बचाने के लिए पूरे देश में सबसे पहले जल-जीवन-हरियाली योजना के तहत बड़े पैमाने पर काम करने का काम किया है, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देती हूँ । महोदय, जल संसाधन विभाग अपने कार्य क्षेत्र में विकसित सिंचाई क्षमता को सतत् बनाये रखने, सिंचाई क्षेत्र में लगातार वृद्धि करने एवं बाढ़ से होने वाली क्षति को कम करने हेतु भी काम कर रही ाहै ।

सभापति महोदय, सरकार द्वारा बाढ़ से बचाव हेतु 4हजार किलोमीटर तटबंध का निर्माण कराया गया है, जिसके फलस्वरूप 40 लाख हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़ से सुरक्षित हो गया है । साथ-ही-साथ आगामी पांच वर्षों में दो हजार किलोमीटर अतिरिक्त तटबंध का निर्माण कराने का लक्ष्य है, जिससे 23 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को बाढ़ से सुरक्षा प्रदान किया जायेगा ।

महोदय, राज्य सरकार लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्म स्थल सितावदियारा ग्राम की सुरक्षा हेतु 86 करोड़ की लागत से तटबंध का निर्माण कार्य कराने का काम किया है । बाढ़ वर्ष 2019 के पूर्व 196 अदद कटाव निरोधक कार्य को पूर्ण किया है, बाढ़ वर्ष 2020 के पूर्व 120 अदद बाढ़ सुरक्षा योजनाओं को 606 करोड़ रूपया की लागत से पूरा किया जायेगा । महोदय, सीतामढ़ी जिला में 19 करोड़ 90 लाख रूपया की लागत से लखनदेई नदी के नई धार को पुरानी धार से मिलाने एवं पुराने धार की उड़ाही का कार्य जोर-शोर से कराया जा रहा है, जिसके पूरा हो जाने से सोनवर्षा, बथनाहा, सीतामढ़ी, रून्नीसैदपुर प्रखंडों में कुल 2,540 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि भी रीक्लेम हो जायेगी । इस योजना को बाढ़ वर्ष 2020 से पहले पूरा हो जायेगा, इसके लिए मुख्यमंत्री जी को सीतामढ़ी की जनता की ओर से बधाई देती हूँ । सभापति महोदय, 111 करोड़ रूपये की लागत से सीतामढ़ी जिला के रातो नदी के तट पर बाढ़ प्रबंधन येजना के तहत नो मैंस लेंड से निशा रोड तक तटबंध का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसे वर्ष 2021 तक पूरा कर लिया जायेगा । सीतामढ़ी जिला के परिहार प्रखंड के रजवाड़ा गांव में 10 करोड़ रूपया की लागत से वियर का निर्माण कराया जा रहा है । सोनवर्षा प्रखंड के रजवाड़ा गांव में स्लुईस गेट का क्रेस्ट बढ़ाकर किसानों के खेत में पानी जाने का प्रबंध सरकार के द्वारा किया जा रहा है ।

सभापति महोदय, 167 करोड़ रूपये की लागत से सीतामढ़ी, मधुबनी एवं दरभंगा जिला के अधवारा नदी के बायें एवं दायें, दोनों ओर के तटबंध को ऊंचा एवं मजबूत बनाया जा रहा है, जो वर्ष 2020 में पूरा हो जायेगा ।

सभापति महोदय, 150 करोड़ रूपये की लागत से कमला बलान तटबंध का विस्तारीकरण, ईंट सोलिंग एवं सुरक्षा का कार्य पूरा करा लिया गया है ।

सभापति महोदय, राज्य सरकार किसानों के खेत में पानी पहुंचाने के लिए जोर-शोर से प्रयास कर रही है, जिससे बिहार के किसान भाई खुशहाल हों । 1310 करोड़ रूपया की लागत से सीतामढ़ी, शिवहर, समस्तीपुर एवं दरभंगा जिलान्तर्गत बागमती बाढ़ प्रबंधन फेज-2 के तहत एवं 943 करोड़ रूपया की लागत से समस्तीपुर, दरभंगा एवं खगड़िया जिला बाढ़ प्रबंधन योजना फेज-3ए के तहत 107 किलोमीटर तटबंध का पुनर्निर्माण 2020 तक पूरा करने का संकल्प है ।

महोदय, नलकूप सिंचाई योजना के तहत राज्य के 10,240 नलकूपों में से 4984 चालू है, शेष नलकूपों को वर्ष 2020 तक 8हजार नलकूप को चालू करा दिया जायेगा । बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना से वर्ष 2019 एवं 2020 में 39 करोड़ रूपया के व्यय से किसानों द्वारा लगाये गये नलकूप 15,572 निजी नलकूप से 43,600 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का सृजन हुआ है । इस योजना से गाड़े गये 31,468 किसानों का 67 करोड़ 44 लाख रूपया के अनुदान का भुगतान हो चुका है ।

सभापति महोदय, आगे आनेवाली पीढ़ी को जीवन प्रदान करने के लिए हमारे आदरणीय नेता बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी एवं उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी ने जल-जीवन-हरियाली के लिए भी लघु सिंचाई विभाग को 500 करोड़ रूपया तालाबों, पोखरों, आहरों, पईनों का जीर्णोद्धार एवं चेक डैम वियर के निर्माण के लिए देने का काम किये हैं । इसके लिए मैं उनको बहुत बधाई देती हूँ । जल-जीवन-हरियाली योजना से सीतामढ़ी जिला में भी अच्छा काम हो रहा है। सीतामढ़ी की डी0एम0 महिला हैं, गांव-गांव जाकर जल-जीवन-हरियाली योजना का काम करा रही है । बहुत मेहनत करती है, उनको भी मैं धन्यवाद देती हूँ ।

सभापति महोदय, सीतामढ़ी जिला में लघु जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियन्ता, रजवाड़ा गांव में बन रहे वियर के निर्माण में घटिया सामग्री लगा रहे हैं, इसकी जांच करायी जाय और मंत्री जी से आग्रह करती हूँ कि सीतामढ़ी जिला के परिहार विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत परिहार प्रखंड के मानिकपुर

मुशहरनियां एवं परिहार में हरदी एवं अधवारा नदी पर वियर का निर्माण करा दें, जिससे वहां के किसानों को सिंचाई में सुविधा हो सके ।

सभापति महोदय, राज्य सरकार का जल संसाधन विभाग किसानों के सिंचाई, बाढ़ की विभिषिका से बचाव हेतु कई बेहतर काम कर रही है । विपक्ष के माननीय सदस्यगण जो बोल रहे हैं, उस संबंध में कहना चाहती हूँ कि बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सिर्फ काम ही काम हुआ है और विपक्ष के लोगों को कुछ काम ही नहीं दिखायी पड़ता है । हमारे मुख्यमंत्री जी का जो लक्ष्य था, उसको वे पूरा किये हैं और आनेवाले पीढ़ी में भी जनता उनको भारी मतों से जीतकर फिर उनको मुख्यमंत्री बनायेंगे । आपलोग निश्चित रहिए । आपलोगों ने जो कार्य किया है, उससे जनता अवगत हो चुकी है । माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार विकास की ओर बढ़ रहा है, इसके लिए मैं उनको बधाई देती हूँ । मेरा कुछ समय बचा हुआ है महोदय ।

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) : माननीय सदस्या, आप एक मिनट में आप अपनी बात को समाप्त करिए ।

श्रीमती गायत्री देवी : महोदय, मैं आग्रह करती हूँ कि एक मिनट और दे दिया जाय । विपक्ष के साथी जरा पीछे मुड़कर देखिए कि क्या हुआ था और आगे मुड़कर भी देखिए । आज हमलोगों के क्षेत्र में हर जगह गली नली बन गया है । कोई ऐसा क्षेत्र नहीं हैं, जहां नली गली नहीं बना हो । यह माननीय मुख्यमंत्री जी का ही देन है । जिस समय खेत में पानी नहीं रहता था, खेत सूख जाते थे, उस समय खेतों में पानी पहुंचाया जाता था और आज हर गरीब खुशहाल है । हर खेत में पानी दिया जा रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो संकल्प लिया था, उसको पूरा करने का काम किया गया है ।

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह): अब आपका समय समाप्त हो गया ।

श्रीमती गायत्री देवी : सभापति महोदय, इसके पहले भी जब हमलोगों को बोलने का समय आया, आप उस समय भी सभापति के रूप में आसन पर थे तो उस समय भी समय से पहले घंटी बजा देते थे ।

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह): आप अपना समय देखिए ।

श्रीमती गायत्री देवी : जब हम आपको आसन पर देखे तो मेरा दिल धड़कने लगा कि आप क्या करने वाले हैं ? जनता सब देख रही है । आगे भी वर्ष 2020 में भारी मतों से आदरणीय नीतीश कुमार जी एवं सुशील कुमार मोदी को पद पर बैठायेंगे । जनता सब देख रही है कि सरकार क्या काम कर रही है । आपने मुझे बोलने का

समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ । परिहार विधान सभा क्षेत्र की पूरी जनता को मैं धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने मुझे यहां बोलने के लिए भेजा ।

टर्न-14/राजेश-राहुल/4.3.20

सभापति (श्री मो0नेमतुल्लाह): आपका 10 मिनट का समय था, अभी समय कितना हो रहा है, 12 मिनट हो रहा है । अब आपको बहुत-बहुत धन्यवाद । अब इंडियन नेशनल कॉग्रेस के माननीय सदस्य श्री विनय वर्मा जी, 9 मिनट का समय है आपका ।

श्री अवधेश कुमार सिंह: सभापति महोदय, जल संसाधन विभाग एवं लघु जल संसाधन विभाग, जल जीवन हरियाली पर आज डिबेट हो रहा है, विजेन्द्र बाबू सिनियर लीडर बैठे है, सिंचाई मंत्री एवं लघु सिंचाई मंत्री जी भी बैठे हैं लेकिन अभी सदन की स्थिति को देखिये, अगर सदन से विपक्ष निकल जाय तो कोरम भी इनके पास नहीं है, तो क्या सिंचाई करना है, संजय झा जी को समझना चाहिए ।

सभापति (श्री मो0नेमतुल्लाह): शांति-शांति । माननीय सदस्य श्री विनय वर्मा जी, आप बोलिये।

श्री विनय वर्मा: सभापति महोदय, मुझे कहना है कि मैं पश्चिमी चंपारण जिला से आता हूँ और गंडक नदी पर सन् 1901 में अंग्रेज सरकार द्वारा वहां पर एक त्रिवेणी नहर की खुदाई करवाई गई थी, जो त्रिवेणी नहर 7 जुलाई, 1907 से चालू हुई थी, इसका निर्माण ब्रिटिश सरकार द्वारा करवाया गया था और ब्रिटिश सरकार अपने किसानों की खुशहाली के लिए उसको मेन्टेन करता था, उसको सुचारु रूप से चलाता था, उनके समय में नहर में हमेशा पानी रहता था, नहर की वितरणी में पानी रहता था लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि अभी की परिस्थिति यह है कि 2017 की बाढ़ हमारे यहां इस तरह से आई कि नहर को पूरी तरह से डैमेज कर दिया और महोदय नहर अभी तक उसी तरह से पड़ी हुई है, उसकी कोई मरम्मती अभी तक नहीं करवाई गई है और न ही इसकी मरम्मती का कोई निश्चित समय है, यदि इस नहर की मरम्मती नहीं होने के चलते मेरे क्षेत्र की जल वितरणी जो है, जैसे गोखुली है, शिकारपुर है, भसुरारी है, बेलवासाठी है, धवली रमोली है, विसनपुरवा-महुआ माइनर है, मरिया-चतुर्भुजवा है, बरबिरोलिपनी है, रामनगर-बगई है, गनौली-डुमरा पंचायत के उप-वितरणी साढ़े तीन साल से बंद है । आज मैंने इस पर जब प्रश्न किया था, तो प्रश्न का जवाब माननीय मंत्री जी ने दिया कि इसका रिपेयर हो गया है । मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे एक टीम के साथ उसमें माननीय मंत्री जी खुद चलें और मैं भी साथ में चलता हूं, अगर कोई भी पईन का रिपेयर हुआ होगा या साफ-सफाई हुई होगी, तो वे जो कहेंगे, मैं मानने के लिए तैयार हूं । मेरा अनुरोध है आपसे कि इसपर जरा सा गहन चिन्तन करके, इसपर ध्यान दिया जाय,

प्रधान सचिव महोदय भी यहां पर हैं और आप भी हैं, ये आपका जो जवाब आता है, वह बेकार का है, हम लोगों को प्रश्न ही नहीं करना चाहिए विधान सभा में, आप लोगों का जूनियर ऑफिसर जो बैठे हुए है, वह अपना वाहवाही के लिए, अपना पैसा खर्च करने के लिए झूठा रिपोर्ट बनाकर भेजते हैं । हम लोग इस पर बातचीत भी करते रहते हैं, उसको सुधारने का कोशिश किया जाए । इसके अलावा मैं ये कहूँगा कि नहर खराब होने के बाद से वहां की सड़कें खत्म हो गई, वहां के जो भी वृक्ष थे, वो काट लिए गए, जो कैनाल के उपर ब्रिजेज थे, वे सब टूट गए हैं, क्या आपके पास इस बजट में, इसके रखरखाव का, मेंटेनेंस का कोई प्रावधान है, अगर है तो मेरा अनुरोध है कि मैं अपनी विधान सभा ही नहीं, इस पूरे क्षेत्र के लिए, यह त्रिवेणी कैनाल केवल मेरे विधान सभा से होकर ही नहीं बहती है, वह उस इलाके में पूरे चंपारण को सिंचाई देती है, मैं चाहूंगा कि कृपया उसको दिखवा लें और उसके ऊपर कार्रवाई करे और शीघ्र उनकी मरम्मत करवाये, जिससे किसानों के खेतों में सिंचाई हो सके । आपसे मेरा अनुरोध है कि अगर यह जल, जीवन, हरियाली की आपकी जो स्कीम चल रही है या जल, जीवन, हरियाली का जो भी स्कीम है, अगर आपका सिंचाई का पानी चलता है, तो किसान को जो एक कट्टा, दो कट्टा, जिसके पास जमीन है, उसको बोरिंग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी । बोरिंग अगर लगेगा, तो जल का स्तर भी नीचे होगा और आपका नदी का जो पानी है, उससे किसानों के खेतों की सिंचाई सही होगी, जल स्तर नीचा नहीं होगा ।

दूसरी सबसे बड़ी बात है कि 2017 की बाढ़ के अलावा, 2018 में भी बाढ़ आई, 2019 में भी बाढ़ आई और इस साल भी बाढ़ आयेगी, क्योंकि बाढ़ का भी आपके विभाग द्वारा कोई उपाय नहीं किया जा रहा है हमारे यहां, हमारे विधान सभा क्षेत्र में 8 नदियां बहती हैं, 8 नदियां जैसे-करताह है, मनिहारी है, पंडई है, हरबोरा है, बलोर है, रामरेखा है, मसान और वीरान है । ये नदियां बरसात के समय में तूफान की तरह आती हैं, ये नदियां नेपाल से बहती हैं और इससे हमारे यहां के गांवों का कटाव हो रहा है, उस संबंध में मैं प्रश्न करता हूं, तो उत्तर आता है कि इसकी चौकसी की जायगी, तो हम कहना चाहते हैं कि लाठी लेकर पानी का चौकसी नहीं करना है उसके लिए आपको या तो जमीन को डिसिल्टिंग कराने के लिए या सफाई करानी चाहिए, कम से कम गांव के आस-पास में बोरा या पत्थर रखकर उसको चैनेलाइज करने का कोशिश किया जाय, जिससे जितना पैसा आप देते हैं आपदा को या आपदा द्वारा बाढ़ पीड़ितों को, उससे कम पैसे में ये आठ-दस गांव जो हैं, ये बच जाएगें । माननीय मंत्री महोदय जी, मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया बाढ़ के लिए वहां पर नदियों को डिसिल्टिंग कराने की व्यवस्था की

जाय या उसको चैनेलाइज कराने के लिए बालू या पत्थर द्वारा भरवाया जाय, ये लाठी लेकर निगरानी करने से बाढ़ का पानी रूकने वाला नहीं है, आपका लिखित प्रश्न है मेरे पास में कि इसकी निगरानी की जाएगी, आपका उत्तर है । मैं एक बात और यह कहना चाहता हूं कि लघु सिंचाई के बारे में मैं माननीय मंत्री जी से भी मिला था, हम तो 2015 में चुन कर आए और मैं पहले ही साल प्रश्न किया था कि सहुंवाटाड़ में एक स्लूईस गेट है, जो क्षतिग्रस्त है, उसका निर्माण कराया जाय, सहुंवाटाड़ में माननीय मंत्री जी ने अपने विभाग में भी लिखा था लेकिन आज तक साढ़े चार साल हो गए, आज तक वह स्लूईस गेट रिपेयर नहीं हो रहा है, इसके लिए मैं बहुत प्रयासरत हूं, मैं चाहूंगा कि उसको रिपेयर कराया जाय । देखा जाए सहुंवाटाड़ जो है, इसके चलते कम से कम तीन से चार हजार एकड़ जमीन का पटवन होता था और जब मैं विभाग में जाता हूं, तो बेतिया जिला में एक्सक्यूटीव इंजीनियर का पद है लेकिन वहां कोई इंजीनियर नहीं है बेतिया में कोई इंजीनियर नहीं है, जब यहां से कॉन्ट्रेक्ट करता हूं, तो मालूम होता है कि इंजीनियर है लेकिन वह गया में बैठते हैं और मैं जब उनसे कॉन्ट्रेक्ट करता हूं, उनसे मिलता हूं, तो कहते हैं कि आपका स्टीमेट बनने के लिए मधेपुरा गया हुआ है, अब बताइये जरा, आपके विभाग की तो ये हालात है, इसलिए कृपया विभाग को सुधारा जाय । एक प्रॉपर एक्सक्यूटीव इंजीनियर दिया जाय या जो भी एक विभाग, जहां हम लोगों को जाना है, वहां उसकी सुनवाई हो, इस पर ध्यान दिलवाया जाय । अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि सिंचाई हो और सिंचाई मंत्री जी कृपया आप नहरों को और वितरणियों, उप-वितरणियों को सही करवायें, आप उनका जीर्णोद्धार करवायें, बोरिंग द्वारा मैंने कहा कि सिंचाई से जलस्तर नीचे होता है । सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में यह भी बताना चाहता हूँ कि मेरे यहां दो-दो चीनी मीलें हैं और मेरे यहां गन्ने की फसल ज्यादा होती है, गन्ने की फसल के लिए पानी की आवश्यकता है और पानी के लिए तथा चीनी मील को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी आपसे अनुरोध है कि सिंचाई की व्यवस्था के लिए नहरों को, कैनालों को, त्रिवेणी कैनाल, जो एक बहुत पुराना कैनाल है, तो वहीं पर धुवन कैनाल है, जो आपका सही रूप से चल रहा है, मैं ये भी चाहूंगा और मेरा गन्ना मंत्री से भी निवेदन है कि हमारे यहां गन्ने की जो खेती होती है, जो फसल होती है, चीनी जो बनती है, उसमें लोगों को भुगतान होने में साल-साल, डेढ़-डेढ़ साल लग जाता है । इसलिए मैं निवेदन यह कर रहा हूं गन्ना विभाग से या माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि गन्ना विभाग के जो भी मील मालिक हों, वे एक महीने के अन्दर-अन्दर अगर भुगतान नहीं करते हैं, तो किसानों को सूद समेत उनका पैसा

चीनी मील द्वारा दिया जाय, ये मेरी मांग है और अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि गया में एक मानपुर प्रखण्ड में मोराटाल पईन सिंचाई विभाग द्वारा स्वीकृत भी है ।

क्रमशः

टर्न-15/सत्येन्द्र-मुकुल/04-03-20

क्रमशः

श्री विनय वर्मा: और उसका टेंडर कम्प्लीट होने में बहुत समय लगेगा चूंकि कान्ट्रेक्टर बहुत धीमी गति से काम कर रहा है। मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि उसको शीघ्र करवायें जिससे कि बरसात के समय या उसके पहले किसानों को पानी मिल सके। बस यही बात है माननीय मंत्री महोदय, कृपया इस पर जरूर ध्यान दें । चूंकि तिरहुत ये जो त्रिवेणी कैनाल है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण कैनाल है, आप खुद पता लगा लें कि वह कैनाल अभी चालू नहीं है अभी बंद है। धन्यवाद।

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) बहुत बहुत धन्यवाद, समय पर आपने समाप्त किया। अब राष्ट्रीय जनता दल के माननीय सदस्य श्री अखतरूल इस्लाम शाहीन।

श्री अखतरूल इस्लाम शाहीन: सभापति महोदय, मैं कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ अक्सर जब विपक्ष में बैठा रहता हूँ कि हमारे सामने किनकी सरकार है, सरकार महागठबंधन की सरकार है या एन0डी0ए0 की सरकार है । इसको मुझे समझने में कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है कि अगर यह एन0डी0ए0 की सरकार है तो एन0डी0ए0 सरकार ने चुनाव से पहले कुछ जनता के सामने जो मैनिफैस्टो लाया था और उस मैनिफैस्टो के तहत ये चार साल, तीन साल या साढ़े तीन साल से सत्ता में है, उस मैनिफैस्टो पर कोई भी बात नहीं करते हैं, कोई भी काम नहीं करते हैं। जो भी सरकार की योजना हम देख रहे हैं, अभी भी बजट जो पेश हुआ है वह तो महागठबंधन का बजट है, जो हमलोगों ने जनता के सामने कमिटमेंट किया था महागठबंधन ने, उसी पर इम्प्लीमेंट का काम हो रहा है तो आखिर यह सरकार महागठबंधन की है उसके मुख्यमंत्री हैं या फिर एन.डी.ए. के मुख्यमंत्री हैं, यह मुझे अभी तक समझ में नहीं आया और दूसरी वजह यह भी है कि अभी मैं तमाम पहली पंक्ति में बैठे मंत्रिमंडल सदस्य को देख रहा हूं। एक भी भारतीय जनता पार्टी के कोई भी मंत्री परिषद् के सदस्य नजर नहीं आ रहे हैं सामने देख रहा हूं जो 10-15 नजर आ रहे हैं उसमें एक भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं नजर आ रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों बनी हुई है। गठबंधन है भी कि गठबंधन नहीं है, यह एक प्रश्न है। इधर सामने में एक-दो सदस्य कहीं बैठे हैं तो समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी

स्थिति क्यों बनी हुई है। दूसरी बात यह है कि आखिर ये जो एन.डी.ए की सरकार है, एन.डी.ए. ने जनता से जो कमिटमेंट किया था कि हम सत्ता में आयेंगे तो यह-यह काम करेंगे। आज सत्ता में ये साढ़े तीन वर्षों से हैं लेकिन जनता से कमिटमेंट किये हुए एक भी वायदे पर ये बोल भी नहीं पा रहे हैं, उस पर चर्चा भी नहीं कर पा रहे हैं, यह जनता के साथ धोखा नहीं है तो क्या है? दूसरी तरफ जो महागठबंधन के हमारे मुख्यमंत्री हैं उन्होंने जनता से कमिटमेंट किया था और जनता से यह कहा था और भारतीय जनता पार्टी का डिफिनेशन देते थे कि सबसे बड़का झूठा पार्टी मतलब बी.जे.पी. होता है, यह भारत जलाओ पार्टी बी.जे.पी. है और आज वह उसमें चले गये। ठीक है, अगर आप उसमें चले भी गये तो आपने यह कमिटमेंट करके उसमें गये, आपने कहा कि हम बिहार के हित में एन.डी.ए. में जा रहे हैं। ठीक है, आप यह करके दोबारा आप एक वायदा करके एन.डी.ए. में गये तो बिहार का क्या हित किया आपने, पिछले तीन वर्षों या साढ़े तीन वर्षों में, बिहार को स्पेशल स्टेट्स देने की बात की थी क्या वह प्रधानमंत्री जी ने या नीति आयोग ने आपको स्टेटस दिया या आपको स्पेशल पैकेज की बात कही गयी थी ऐसा कुछ किया या बिहार को विशेष राज्यांश कुछ अधिक दिया है। अभी हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री जी लगातार पत्र लिखते हैं नीति आयोग को और देश के केन्द्र की सरकार को कि बिहार की बदहाल स्थिति के लिए स्पेशल ध्यान दिया जाय, स्पेशल पैकेज दिया जाय, स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया जाय। मुख्यमंत्री जी की चिट्ठी को लगता है कि उठाकर फेंक दिया जाता है। आपने दोबारा कमिटमेंट किया था कि एन.डी.ए. में जाने से बिहार का हित होगा तो मैं जानना चाहता हूं कि अन्य राज्यों को केन्द्र सरकार ने डेढ़-डेढ़ लाख करोड़ रुपया देने का काम किया है और अभी जो हम देख रहे हैं बिहार को जो मिला है वह 55 हजार करोड़, 60 हजार करोड़, इस तरह से पैसा दिया जा रहा है तो ऐसा लग रहा है और वह भी बोला गया है तो राज्यांश जो राज्य को मिलता है उस मामले में प्राथमिकता देने की कोशिश नहीं की गई है और हम यह देखते हैं कि भाई आप 15 साल शासन कर लिये हैं, एक लम्बा समय शासन कर लिये और आज किस पॉजिशन में बिहार है ? हम देश के 10 विकसित राज्यों को देखते हैं तो कहीं बिहार नजर नहीं आता है, 20 राज्यों को आप अध्ययन करें, कहीं भी आप जब तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो बिहार आज भी 2-3 फिसड्डी राज्यों में है। आपका नीति आयोग कहता है, इनकी भारत सरकार की तमाम संस्थायें यह कहती हैं, जो यू.एन.ओ. है उसने भी अध्ययन किया है वह भी बताया है कि बिहार तमाम क्षेत्रों में फिसड्डी साबित हुआ है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का रिपोर्ट आया उसमें भी बिहार

फिसड्डी साबित हुआ है। आप देखेंगे कि स्वास्थ्य सुविधाएं और चिकित्सा सुविधााएं जो हैं उसके बारे में भी कहा गया है कि उसमें भी बिहार सबसे फिसड्डी साबित हुआ है, रोजगार देने के मामले में फिसड्डी साबित हुआ, गरीबी उन्मूलन के मामले में फिसड्डी साबित हुआ और बी.पी.एल. रेखा से सबसे नीचे रहने वाले लोगों के उत्थान करने में सबसे फिसड्डी साबित हुआ, कल-कारखाने लगाने में फिसड्डी साबित हुआ और तमाम चीजों में बिहार जो अंतिम पायदान पर एक दो राज्यों में था, इन 15 सालों के शासनकाल में एक भी काम इन्होंने ऐसा नहीं किया जिससे कि बिहार का अपग्रेड हुआ हो और जहां तक जल संसाधन विभाग की बात है। हम जल की महत्ता को समझते हैं और जल की क्या आवश्यकता, अनिवार्यता है उसको राष्ट्रीय जनता दल समझती है कि जल इस धरती के अलावा दुनिया में कहीं नहीं है बल्कि किसी ग्रह पर भी जल का कोई विकल्प नहीं है और इसके लिए इसकी आवश्यकता सुरक्षा का प्रबंधन जिस तरह से आवश्यकता थी उसमें काम करना चाहिए वह विभाग में कहीं देखने को नहीं मिलता है। हम यह देख रहे हैं कि आज बिहार में जो आबादी है और 94 लाख हे0 बिहार की भूमि है उसमें से हम कह सकते हैं कि 54 लाख हे0 जमीन ही कृषि के योग्य है और उसमें भी देखते हैं कि 78 प्रतिशत हमारा जो भूभाग है बिहार का उसमें 78 प्रतिशत मतलब लगभग 73 प्रतिशत मतलब कि लगभग 68 लाख हे0 जो भूमि है वह बाढ़ प्रभावित है । पूरे भारत वर्ष में सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित भूमि कहीं है तो वह बिहार में है । पूरे देश का औसत निकालेंगे तो लगभग 13 से अधिक 17 प्रतिशत, 17 प्रतिशत भूभाग जो बाढ़ प्रभावित है आपने 15 साल के शासन में जो बाढ़ प्रभावित एरिया था उसको कंट्रोल करने में क्या किया, आप 15 साल पहले भी जाकर देखियेगा तो हमारा उतना ही प्रतिशत था और आज भी उतना ही है । आज भी लाखों लोग हमारा जो गलत व्यवस्था प्रबंधन के कारण मारे जा रहे हैं बाढ़ में, हम यह भी देख रहे हैं कितने करोड़ लोग हमारे बाढ़ से प्रभावित हो रहे हैं, तबाह और बर्बाद हो रहे हैं। इनके 15 साल के शासन में कोई ऐसा काम नहीं हुआ, कोई ऐसा उल्लेखनीय काम नहीं किया जिससे कि कैसे इसे बाढ़ से बचा सकें। जब बाढ़ आती है तो चूहे पर इसकी जिम्मेदारी दे देते हैं, इसी तरह का काम इनके तमाम लोग करते जाते हैं इसीलिए मैं समझता हूं कि 15 साल के शासन काल में कुछ नहीं किया। जिस तरह से इन्होंने एक मोटी रकम, मैंने बजट पढ़ा था जो इनका बजट था वह 4 हजार करोड़ रू0 का था और अभी जो करेंट आया है उसको नहीं पढ़ पाया हूॅ लेकिन बजट को देखा है तो इस तरह से तमाम क्षेत्रों में इनके द्वारा जो किया जा रहा कार्य है वह निश्चित रूप से

कहीं भी उल्लेखनीय नहीं है इसीलिए इनके विभाग के कई ऐसे मामले हैं जो हम इनको बता सकते हैं और देख सकते हैं कि इनका विभाग किस तरह काम कर रहा है । हमारे क्षेत्र समस्तीपुर का ही हम एक-दो उदाहरण देकर आपको बताना चाहेंगे कि समस्तीपुर जिला में एक बिरौली पूसा, बिरौली समस्तीपुर के लिए एक रोड है जिसको बनाने का काम करना था विभाग को और ढाई साल पहले उसका टेंडर होता है, ढाई साल पहले टेंडर हो जाता है लेकिन उसमें अभी तक एक ईंच सड़क नहीं बन सका। आखिर आपका विभाग क्या कर रहा है, किस तरह से आप मॉनिटरिंग करते हैं कि ढाई साल पहले टेंडर किये गये और एक ईंच सड़क नहीं बना, अभी जाकर दोबारा टेंडर हो रहा है, इस तरह से इनका विभाग चलता है । दूसरा मैं उदाहरण दूंगा और मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय अपने उत्तर में इसका जवाब दें। बिरौली से लेकर समस्तीपुर तक की सड़क ढाई साल में एक ईंच भी नहीं बना अब जाकर उसका रि-टेंडर आप करने जा रहे हैं। दूसरी सड़क है अंगार से लेकर समस्तीपुर तक इसमें पूरी तरह से पब्लिक कम्प्लेन आ रहा था कि आप पहले एक रोड बनाये थे, जहां बनता था वहीं धंस जाता था उसी तरह दूसरा रोड भी बन रहा है अंगार से लेकर समस्तीपुर तक का, तमाम लोगों ने आवेदन दिया, तमाम पदाधिकारी ने हमको भी आवेदन दिया और मैंने उसे विधान सभा में भी उठाया था, पता नहीं विभागीय विजिलेंस उस पर काम भी किया लेकिन कहीं कोई सुधार नहीं हुआ और जिस तरह मिट्टी का फिलिंग करना था या तमाम तरह से जो कंप्रेसर का काम होना चाहिए, किसी तरह का काम नहीं किया गया तो स्पष्ट रूप से इस विभाग में कहीं भी कुछ नहीं हो रहा है और मुझे लगता है कि 2-4 विभाग जो सबसे ज्यादा बदनाम विभाग है जिसे लूट-खसोट विभाग कहा जाता है, इस विभाग की बदनामी पूर्व से होती आयी है। अभी हमारे नये मंत्री आये हैं हमलोगों के क्षेत्र के हैं, हमारे प्रमंडल के मंत्री हैं, हमलोगों को लगा कि ये कुछ उल्लेखनीय बदलाव लायेंगे लेकिन अभी तक कितना बदलाव लाये हैं, मैं दो उदाहरण दिया हूं इसका मैं नतीजा देखूंगा कि किस तरह ये इम्प्लीमेंट करते हैं तो समझ में आयेगा कि हां इनके रीजन में कुछ उल्लेखनीय बदलाव हुआ है। माननीय मंत्री महोदय बैठे हुए हैं, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमारे यहां अल्पसंख्यक लोग हैं और हमारे यहां अल्पसख्यंक छात्रावास की सारी प्रक्रिया पूर्ण कर के रखी हुई है और वहां अल्पसंख्यक के मंत्री बैठे हुए हैं, पता नहीं लोग मॉनिटरिंग भी करते हैं कि नहीं करते हैं, 15 साल पहले मुख्यमंत्री जी ने उसका शिलान्यास किया, सारी प्रक्रिया पूर्ण हो गयी, शिक्षा विभाग ने अनुमति भी दे दी, जमीन स्थानांतरण की सारी प्रक्रिया हो गयी लेकिन टेंडर नहीं कर पा रहे हैं तो किस तरह

से यह सरकार चल रही है। मुझे लगता है कि इन सब कारणों से 15 साल में आप सबसे पिछड़े राज्यों की श्रेणी में आये हैं तो इन्हीं कारणों से आये हैं । जमुई जिला में जाकर देखा जायेगा तो जमुई जिला में खैरा प्रखंड है, उसमें बेला मानपुर का लघु जल संसाधन विभाग का मामला है वहां मानपुर वियर है यहां कई वर्षों से योजना अधूरी है, मानपुर वियर का जीर्णोद्धार अभी तक नहीं कराया गया है इसीलिए हम चाहेंगे कि इस कार्य को भी पूर्ण कराया जाय। इन्हीं सब क्षेत्रों के बारे में मैं कुछ और बात को रखना चाहता था मुंगेर का एक मामला है जिस पर हमारे सदस्य बतला रहे थे मुंगेर जिला के सदर प्रखंड के तिरक पंचायत में गंगा नदी के कटाव से सुरक्षा हेतु निर्माण कार्य कराना था, वह काम होना था लेकिन नहीं हुआ। इसी तरह से समस्तीपुर जिला मुख्यालय है और जिला मुख्यालय में बूढ़ी गंडक नदी है (क्रमशः)

टर्न-16/मधुप-हेमंत/04.03.2020

...क्रमशः...

श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन : उसमें लगातार कटाव बढ़ता जा रहा है । वहॉ एक कब्रिस्तान है, धर्मपुर में श्मशान भी है, वहॉ गंगा स्नान मेला भी चकनूर में लगता है, लगातार कटाव समस्तीपुर शहर की तरफ, क्योंकि शहर के किनारे बूढ़ी गंडक नदी है, लगातार कटाव बढ़ता जा रहा है, उसके प्रोटेक्शन की आवश्यकता है । मुझे लगता है कि विभाग गंभीरता से इन तमाम चीजों को देखेगा । जिस तरह से लापरवाही इनके पदाधिकारी करते हैं और तमाम तरह की जॉच जो लिखी जाती है, उसपर कोई कारगर कदम उठाते नहीं हैं, इसलिये मैं चाहूंगा कि मंत्री जी अगर संवेदनशील हैं, तो समस्तीपुर के मैंने दो-चार मामले उठाये हैं, इन तमाम मामलों को निष्पादित करें ताकि मुझे भी लगे कि जो इस विभाग की बदनामी लगातार पिछले कई वर्षों से देखी जा रही है, नये मंत्रिमंडल में कुछ बदलाव हुआ है । इन्हीं आशा और विश्वास के साथ कि हमारी तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए जो बाढ़ से प्रभावित बड़ी संख्या में लोग हैं, लगातार बाढ़ आ रही है और सिंचाई का भी समुचित प्रबंध नहीं हो पा रहा है ।

महोदय, एक व्यापक योजना बनाकर काम करेंगे, मुझे लगता है कि अब समय नहीं है, अब 15 साल का लम्बा वक्त गुजरा है, एक युग परिवर्तन हुआ है इसलिए सत्ता भी परिवर्तन हो और नया ऊर्जावान किसी इंसान पर विश्वास बिहार की जनता करे और नई जिम्मेदारी के साथ नए बिहार की कल्पना की जाय । इसी आशा और विश्वास के साथ कि जो भी समस्याएँ हैं, सदन उसपर ध्यान देगा और

बिहार की समस्याओं का निदान करने में कोई उल्लेखनीय कार्य किया जायेगा । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

सभापति (श्री मो0 नेमतुल्लाह) : आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद । ससमय आपने अपने भाषण को समाप्त किया ।

अब जनता दल यूनाइटेड के माननीय सदस्य श्री रणधीर कुमार सोनी जी।

श्री रणधीर कुमार सोनी : सभापति महोदय, आज जल संसाधन विभाग की जो 40 अरब 53 करोड़ की माँग रखी गई है, इसमें जो कटौती प्रस्ताव दिया गया है, इसके विपक्ष में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ...

सभापति (श्री मो0 नेमतुल्लाह) : 10 मिनट समय आपका है ।

श्री रणधीर कुमार सोनी : चूंकि यह जो कटौती प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा दिया गया है, हम तो इसमें माँग करेंगे कि इससे ज्यादा पैसा विभाग को दिया जाय । दोनों सदन के सदस्यों ने 13 जुलाई को, विश्व में पर्यावरण का जो खतरा है, विश्व में जो पर्यावरण का संकट आ गया है, इसपर माननीय विधान सभाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी, बिहार विधान सभा और बिहार विधान परिषद् दोनों सदन के सदस्यों ने अपनी-अपनी राय दी थी और उन सारी राय का निचोड़ करके बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री ने उसको जल-जीवन-हरियाली के तहत जोड़कर, पूरे बिहार में जितने भी परम्परागत हमारे जल स्त्रोत हैं, जैसे पूर्वज जो आज से पहले खेती करते थे, जितने हमारे आहर हैं, जितने हमारे पईन हैं, जितने तालाब हैं, सभी के जीर्णोद्धार के लिए जल-जीवन-हरियाली के तहत सर्वेक्षण किया गया है और पूरे बिहार का चाहे वह सरकार के पक्ष के माननीय विधायक का क्षेत्र हो या विपक्ष के माननीय विधायक का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्र में सारे का सर्वेक्षण किया गया है और उसका जिम्मा जल संसाधन विभाग के द्वारा किया गया है । निश्चित रूप से विभाग को और पैसे की आवश्यकता पड़ेगी । आज इस जल-जीवन-हरियाली के तहत मुख्यमंत्री इतने संजीदा हैं कि जब बैठक हुई जुलाई में और अगस्त में इसकी शुरुआत हो गई । जन-जागरण की शुरुआत हुई, उसके बाद विधिवत अक्टूबर में इसकी शुरुआत हुई । निश्चित रूप से विश्व के संकट को बिहार के मुख्यमंत्री ने समझा, निश्चित रूप से आने वाले समय में पर्यावरण के मामले में यह मील का पत्थर साबित होगा और बिहार के किसानों के लिए, बिहार के जो खेत मजदूर हैं, जो खेती पर निर्भर करते हैं, जितने हमारे आहर, पईन और तालाब का जीर्णोद्धार हो जायेगा तो बिहार की खेती की परिस्थिति ही बदल जायेगी ।

महोदय, सभी लोग जानते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार की सरकार ने गंगा के पानी को, हमारे भारत में आने वाले विदेशी सैलानियों को गया, नवादा

और नालंदा तीन जिले जहाँ पेयजल का संकट है, वहाँ के लिए गंगा का पानी पहुंचाने के काम के लिए एक परियोजना बनी है । निश्चित रूप से आप तमाम लोग जानते हैं कि हमारे गया में विश्वस्तर पर पितृपक्ष मेला लगता है जहाँ फल्गू नदी में आये दिन हमलोग अखबार में पढ़ते हैं कि पानी नहीं है, पानी का संकट है। निश्चित रूप से यह गंगा का पानी जायेगा तो जो सैलानी आयेंगे, जो वहाँ पितृपक्ष का मेला लगता है खास करके हिन्दू समाज के लिए अब वहाँ गंगाजल का पानी मिलेगा और उससे मोक्ष की प्राप्ति होगी । यह बिहार सरकार का बहुत ही ऐतिहासिक कदम है । पेयजल के लिए भी, जो पेयजल की समस्या है, राजगीर पहाड़ पर बसा हुआ है, वह पूरा इलाका चाहे लखीसराय का इलाका हो, शेखपुरा का इलाका हो, नालंदा का इलाका हो, गया का इलाका हो, नवादा का इलाका हो, माननीय सभापति महोदय, वह पहाड़ पर बसा हुआ है । हमलोगों के यहाँ चाहे लखीसराय जिला हो, शेखपुरा जिला हो, नवादा हो, नालंदा हो या गया हो, पेयजल का संकट रहता है । खास करके शहर में संकट रहता है खास करके हमारे शेखपुरा की आबादी पहाड़ के ही चारो तरफ बसी हुई है । उसी तरह से राजगीर की भी स्थिति है । तो पेयजल के लिए पानी मिलेगा और हम तो मंत्री जी से यह भी माँग करेंगे कि अगले फेज में शेखपुरा को भी शामिल कर लिया जाय चूंकि शेखपुरा भी पहाड़ पर ही बसा हुआ है और वहाँ पेयजल का भी संकट है । सरकार हर दो-तीन साल पर योजना लाती है लेकिन योजना फेल हो जाती है, पानी का संकट बना रहता है । इसलिए अनुरोध है कि अगले फेज में शेखपुरा को भी जोड़ा जाय । निश्चित रूप से जो सरकार का काम है, वह सराहनीय है ।

जहाँ तक टाल की योजना है, जब जल संसाधन विभाग द्वारा मोकामा टाल, बड़हिया टाल, घाट कुसंबा टाल, सभी का सर्वेक्षण हुआ, वहाँ एक ही फसल होती थी, चूंकि पानी आ जाता था, पानी का उचित प्रबंधन नहीं था लेकिन इस बार दो-तीन सालों में मोकामा टाल और बड़हिया टाल का तो विकास कार्य हुआ उससे अब दो-फसला खेती ज्यादा शुरू हुई है लेकिन हमारा जो शेखपुरा का घाट कुसुम्बा टाल है, वहाँ की तीन हिस्सा जगह, जल संचयन प्रबंधन नहीं हुआ है । चूंकि लखीसराय जिला का हो गया, पटना जिला का हो गया, बीच में शेखपुरा का कुछ पार्ट जो घाट कुसुम्बा प्रखण्ड के अन्दर पड़ता है वहां जल संचयन की, सिंचाई की व्यवस्था में थोड़ी कमी है उसको भी पूरी करने की ओर हम माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करेंगे ।

महोदय, 2007 में जब बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार आयी तो हमारे यहां तीन योजना हुई थी सिंचाई के लिए चूंकि

हमारा जिला पूरी तरह से झारखंड और नवादा का जो कौवाकोल का पहाड़ है उस पर जो वर्षा होती है उस पर डिपेंड है । 2007 में हमारा कोरिहारी नदी सिंचाई योजना का पुनर्स्थापन कार्य हुआ था, कोरिहारी नदी में छः छिलका है उसका पुनर्स्थापन कार्य हुआ था, जो 2007 में हुआ था । आज 13 साल बीत गये । 13 साल में गाद जम गयी है और गाद के साथ-साथ जो स्ट्रक्चर है और उसकी जहां-तहां क्षति हुई है, हम अनुरोध करेंगे कि जो कोरिहारी नदी सिंचाई परियोजना है और छः छिलका का निर्माण है, इसके साथ-साथ रतोइया नदी सिंचाई योजना जो कि 12-13 साल पूर्व उसमें कार्य हुआ था, उस कार्य को फिर से कराया जाय ताकि शेखपुरा में सिंचाई के लिए हम जो सिर्फ आहर, पईन और नदी पर डिपेंडेड हैं, फिर से किसानों को फायदा मिल सके और उनके खेत तक पानी पहुंच सके । हमारे यहां करीब 110 आहर और पइन हैं, करीब 117 तालाब हैं । हम निश्चित रूप से मांग करेंगे कि हमने तो दिया है जल-जीवन-हरियाली के तहत, हमारे यहां स्टेट ट्यूबवेल नहीं है हमारी सिंचाई का एकमात्र रास्ता है आहर, पईन और तालाब। निश्चित रूप से माननीय मंत्री जी हमारे शेखपुरा छोटे जिले की तरफ भी जरूर ध्यान देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद ।

सभापति : आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद । ससमय आपने समाप्त किया ।

अब भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य श्री राजीव नन्दन जी ।

टर्न-17/आजाद:अंजली/04.03.2020

श्री राजीव नन्दन : महोदय, विपक्ष द्वारा जल संसाधन विभाग द्वारा पेश बजट पर लाये गये कटौती प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हूँ । महोदय, ...

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) : माननीय सदस्य श्री अवधेश बाबू चले गये, गिनती गिना रहे थे, विपक्ष की गिनती गिनिए और कोरम देखिए । अवधेश बाबू, कांग्रेस पार्टी आज देश और बिहार कृषि प्रधान राज्य पहले से रहा है । आजादी के बाद आपने 70 सालों में देश में खेतों तक पानी पहुँचाने का कोई काम नहीं किया और देश की 99 ऐसी परियोजनायें, सिंचाई परियोजनायें जिसको लूट का संसाधन बनाया और देश में भ्रष्टाचार किसानों को उनसे मिलने वाली सुविधा से दूर रखा । हमारे यहां करीब 50 साल से ऊपर से उत्तर कोयल परियोजना प्रारम्भ हुआ था और कुछ करोड़ रू0 की परियोजना आज हजारों करोड़ रू0 में पहुँच गयी है । खेत तक पानी नहीं आया है, हजारों एकड़ जमीन नहर में चला गया है । किसानों के खेत में पानी नहीं पहुँच रहा है, लोहिया जी ने तो सदन में बोले थे, आप उस दिन कहां थे कांग्रेस वाले लोग, आज गठबंधन करके कह रहे हैं कि लोग दिखाई नहीं पड़ रहे

हैं । जिस दिन काम करने के लिए समय मिला, उस दिन आप आहर, पोखर सब कब्जा करवा रहे थे, आज जल, जीवन, हरियाली के तहत उन कब्जा किये पोखर, तालाबों को जिन्होंने कब्जा किया है, उनको खाली कराया जा रहा है । आज उन लोगों का नाम आ रहा है । माफिया, भू-माफिया लोगों का नाम आ रहा है, जिन्होंने खरीद-खरीद कर बेचा है । गया शहर में दर्जनों ऐसे तालाब हैं, जिनको भरकर बेच दिया गया है । इसमें कौन सम्मिलित है, सम्मिलित आप सब हैं, जॉंच हो रहा है, समझिए । अभी बोल रहे थे, अभी रवीन्द्र भाई बोल रहे थे, जल, जीवन, हरियाली में काम नहीं हो रहा है । आप देखिए सब जगह कार्य में प्रगति है और माननीय सदस्य जी, 15 सालों में तो परियोजना बनेगा ही बनेगा, हम तो आपके किये गये गड्ढ़े को भर रहे हैं । ......

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) **:** आप इधर मुखातिब होकर बोलिए ।

श्री राजीव नन्दन **:** आपने जितने गड्ढ़े किये थे, उस गड्ढ़े को भरकर हमने समतल जमीन बनाया है और समतल जमीन बनाने के लिए हर खेत को पहुॅंचाने के लिए लक्ष्य तय किया है । अगले दो-तीन वर्षों में 2022 तक हम हर खेत को जल पहुॅंचायेंगे। आज हमने इस दिशा में काम करना प्रारम्भ कर दिया है । जल, जीवन, हरियाली के तहत, मिशन के तहत छोटे-छोट आहर, पईन, तालाबों का जीर्णोद्धार प्रारम्भ कर दिया है । आज जल संचय का काम करने जा रहे हैं । आपने तो पानी रोकने का काम किया, जब आपको मौका मिला तो आप क्या कर रहे थे ? आपके पास इसका कोई जवाब नहीं । आप अगर जवाब देते कि हम आयेंगे तो ये काम करेंगे, हम जो अच्छा काम कर रहे हैं, उसमें भी नुकसान निकाल रहे हैं । आपने किया क्या ? आप एकाध काम बता दे कि हम आयेंगे तो ये काम करेंगे, हम आयेंगे तो ऐसे पानी देंगे । आपको जब करने का मौका मिला तो किये नहीं । आज आपके जितने भी लंबित परियोजना है, उत्तर कोयल, पुनपुन परियोजना, कोशी परियोजना सभी परियोजनाओं में काम चल रहा है और उन परियोजनाओं से किसानों को लाभ मिलने वाला है । उन किसानों को जब लाभ पहुॅंचेगा अगले एकाध-दो साल में तो आने वाले चुनाव में उस लाभ का जवाब आपको मिलेगा, आप ध्यान से इसको नोट कर लीजिए कि इस जवाब का भी लाभ आपको किसानों के द्वारा दिया जायेगा।

(व्यवधान)

कितना दिन से लटकाये हुए हैं यह तो पता ही है, आज एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, किसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं भाई साहेब, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है । आज हमलोगों को कोई ऐसा सूत्र

बता दीजिए कि हम करोड़ों का मालिक बिना काम किये हुए बन जाएं, अभी बजट का पत्र दिखा रहे थे, अभी उसमें जो लिखा हुआ है पीछे में, आपको नहीं दिखायी दे रहा है, सात, सामाजिक, पापकर्म, यह किसलिए दिया हुआ है, हम राजनीतिक करने वाले लोगों को शिक्षा देने के लिए किया हुआ है कि आप शिक्षा को ग्रहण करें और उसके बाद काम करें, आप कंफ्यूज मत होईए, इसको पढ़िए और बिना काम का सम्पत्ति अर्जित करना भी एक पाप है । आप नहीं तो सूत्र बता दीजिए, वह सूत्र क्या है, हम बिहार की जनता को बता देंगे कि बिना काम किये हुए सम्पत्ति अर्जित हो जायेगा । इसलिए बजट के किताब में पीछे दिया हुआ है कि अंतिम में देखकर आप पढ़िए तो याद रहे ।

आज हम अपने क्षेत्र के कुछ योजनाओं के बारे में चर्चा करना चाहेंगे, महोदय, लघु सिंचाई विभाग से हथियादह नाला है, जिसके बारे में मैंने माननीय मंत्री जी को लिखकर भी दिया है, वहां पर डी0एम0 साहेब का और एजक्यूटिव इंजीनियर का भ्रमण हो चुका है, नाम वगैरह हो चुका है, इस वित्तीय वर्ष में उसका शिलान्यास कराया जाय, चूँकि वहां पर 8 वर्ग किलोमीटर का पानी बह जाता है बारिश के समय में, इसी तरह से नाला से बह जाता है । अगर हम वहां पर एक छोटा सा बांध बना देंगे 10 फीट का बांध बना देंगे तो कम से 3-4-5 पंचायत या पूरे प्रखंड को भी पानी दे सकते हैं । आपको जब समय मिला तो आपने चालो पहाड़ को बना दिया....

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) : चलिए आप अपनी बात कहिए, इधर मुखातिब होकर बोलिए ।

श्री राजीव नन्दन : आपने चालो को चम्बल बना दिया, आपने नक्सली एरिया बना दिया, हम उस पहाड़, चालो पहाड़ में बांध बनाकर विकास करने जा रहे हैं और वहां के लोग आपको जवाब देंगे, अपने मत से जवाब देंगे और यह बात मत सोचिए, बिहार में एन0डी0ए0 की सरकार बनेगी और यह मत समझिए कि ये जो नक्सली हैं, वह कहीं न कहीं आपसे ही सम्पर्क रखे हुए हैं .....

(व्यवधान)

तो इतने लहर में यह भगवा लहरा रहे हैं, इतना बात तो याद रखिए । आपसे आग्रह रहेगा कि अमीर हेलेड पईन है, आज अंग्रेजों के जमाने से वो पईन चल रहा था । आज वो पईन अतिक्रमण का शिकार हो चुका है । हम चाहेंगे गुरूआ बाजार में जो पईन गुजरता है । उस पईन का पक्कीकरण कराया जाए जो वह दो-तीन सौ वर्षों से अमीर हेलेड पईन काम कर रहा है । आज भी किसानों को पानी दे रहा है । हम चाहेंगे सरकार से कि उसमें प्रावधान किया जाए और जो गुरूआ बाजार के अंदर से जो पईन गुजरता है, उसका दोनों किनारा पक्कीकरण

किया जाए ताकि वह अतिक्रमण से बच सके और नाला जो किसानों को पानी उपलब्ध कराता है अमीर हेलेड पईन वह हमेशा रहे । उसी प्रकार महोदय, हाड़ा नाला है, हाड़ा नाला पईन, हाड़ा नाला का पईन, वर्षों से अंग्रेज के समय से पईन है, उसका भी जीर्णोधार के लिए मैं आग्रह करूंगा । महोदय, घोड़ा घाट, घोड़ा घाट अपने झारखंड और बिहार के बॉडर पर पड़ता है, वहां से हमारा निलाजन नहर का सिस्टम निकलता है, हमारे उत्तर घाटी के माननीय विधायक पूर्व मंत्री जी के क्षेत्र से भी वह क्षेत्र पटवन करता है । मैं चाहूंगा कि उस निलाजन नहर में जल्द से जल्द उसको जीर्णोधार कराया जाए ताकि किसानों को अधिक से अधिक उसके टे-लैंड तक पानी पहुंचाने के लक्ष्य को हम हासिल कर सकें । महोदय, आज लोअर मोरहर के ऊपर पिछले दो सौ वर्षों से अंग्रेजों के समय से क्रॉस ड्रेन नाला बना हुआ है । अंग्रेजों की सोच से उस समय बना था, जिस समय डिहा पहाड़ का वर्षा का पानी पीछे पांच गांवों में ले जाया जाता था क्रॉस ड्रेन नाला को क्रास करवाकर के, आज वो नाला क्षतिग्रस्त हो चुका है ओवर ड्रेन नाला, आज उसको नए सिरे से बनवाने की जरूरत है, आवश्यकता है । महोदय, हमने मउ पईन की सफाई करवाई है, टेकारी प्रखंड के अंदर आता है, मउ पईन की सफाई में सवा तीन करोड़ रुपया हमने खर्च किया है, लेकिन करीब उसमें 100 फीट में अतिक्रमण रहने के कारण आज तक पईन का सही उपयोग नहीं हो पा रहा है । हाईकोर्ट भी आदेश दे चुके हैं, हम चाहते हैं कि उसमें जो पईन पर अतिक्रमण है उसको अतिक्रमण मुक्त कराकर उस शहरी क्षेत्र में पईन का पक्कीकरण करा दिया जाए ताकि अतिक्रमण होने से वह बच सके और किसानों को पानी मिल सके ।

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह): ठीक है, अब आप समाप्त कीजिए ।

टर्न-18/शंभु-धिरेन्द्र/04.03.20

श्री राजीव नन्दन : क्रमशः....एक मिनट सर, बस खत्म ही हो रहा है । एक है लोअर मोरहर नहर है हमारे पास वर्षों से बना हुआ है । उसके मुहाने पर गाद जम जाने के कारण पानी वहां पर ठीक से स्टॉक नहीं हो पा रहा है । मैं चाहूंगा कि उस नहर की भी सफाई हो सके और अभी बात कर रहे थे ऊर्जावान सत्ता परिवर्तन का ख्वाब देख रहे थे । आप ख्वाब देखिए आपको जनता जवाब देगी ।

सभापति(श्री मो0नेमतुल्लाह) : अब आप समाप्त कीजिए । अब इंडियन नेशनल कांग्रेस के श्री आनन्द शंकर सिंह जी, प्रारंभ करें । आपका टाइम 5 मिनट है ।

श्री आनन्द शंकर सिंह : महोदय, कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने का मौका मिला है, धन्यवाद। महोदय, 5 मिनट टाइम अब दूसरे लोग ज्यादा बोलें और उसका खामियाजा हम भुगतें, यह उचित नहीं है ।

सभापति(श्री मो0नेमतुल्लाह) : 9 मिनट आपके विनय बाबू बोले 5 मिनट आपका टाइम । जो टाइम इसमें दिया गया है उसी हिसाब से बोलिये । सबलोग अपने समय पर बोले आप भी बोलिये । बोलिये, समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं ?

श्री आनन्द शंकर सिंह : महोदय, एक पुरानी शायरी है वो जो प्यासा लगता तथा सैलाब जगा था, वो जो प्यासा लगता था सैलाब जगा था पानी-पानी कहते डुब गया, अभी उसका शेर का उलटा मतलब अगर देखे हम तो उसमें ये होगा कि उसमें सैलाब जगा था प्यासा लगता था, पानी-पानी कहते मर गया और यही हालत है आज के किसानों की । महोदय, आज भी देश में बिहार की जो आबादी है वो आबादी कृषि पर निर्भर करती है और 61 परसेंट खेतों में तो सिंचाई की व्यवस्था है जो पुराने समय से चली आ रही है लेकिन 40 प्रतिशत खेत आज भी असंचित हैं । महोदय, जिस प्रकार से जनसंख्या का घनत्व है बिहार का और जिस प्रकार से रोजगार में कमी आयी है, अभी कल एक रिपोर्ट पढ़ रहा था महोदय, ये 10.5 लाख करोड़ कॉरपोरेट डेब्ट है महोदय, नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या सब लेकर भाग गया और सरकार जो है वो रेलवे के निजीकरण में लगी है, बी0एस0एन0एल0 को बेचने में लगी है, ऑयल कंपनियों को बेचने में लगी है, एयर इंडिया की बोली लगा रही है और पुनः लौट कर महोदय हम लोगों को कृषि पर निर्भरता ही एक रास्ता निकलेगी जिससे रोजगार जनरेट होगा और रोजगार की व्यवस्था होगी । आज के समय में तो ये स्थिति है ''खोल चेहरे पर चढ़ाने नहीं आते हमको, हम गाँव के लोग हैं हम तेरे शहर में आते है'' शहरीकरण के दौर में ये हो गया, जो मेरे गाँव के खेतों में एक भूख उगने लगी तो, मेरे गाँव के किसानों ने शहरों में नौकरी कर ली, शहरीकरण का ये नमुना पुनः फिर गाँव की ओर लौटने के लिए लोग अग्रसर है लेकिन स्थिति क्या है आज के डेट में 40 प्रतिशत खेत सूखे हैं, उनके लिए कोई सिंचाई की व्यवस्था नहीं है । 2018 का एक सर्वेक्षण है आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार जलवायु एवं पर्यावरण परिवर्तन से सिंचाई से वंचित इलाकों के किसानों की आय 20-25 प्रतिशत कमी होने की आशंका व्यक्त की गई है। महोदय क्या स्थिति है ? कृषि विभाग का बजट आ जाता है जल संसाधान विभाग का बजट आज आया है, स्थिति ये है कि गाँव के लोग सबकुछ लगा के उपर वाले से दुआ माँगते रहते हैं कि भगवान इस बार पानी अच्छा बरसा देना, कम से कम जो बीज लगाया है उस फसल को काट लें, और काट के बेच दें, आज तो स्थिति ये है कि कृषि

विभाग जब बीज बो देते हैं तो आपको बीज देती है, जब सिंचाई मर जाता है तो डिजल अनुदान देता है, डिजल अनुदान के बाद नहर का पानी पहुँच नहीं पाता, तो स्थिति ये बनती है कि तब किसान काट लेता है फसल तो पैक्स का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है और पैक्स खरीदारी नहीं कर पाती है नतीजा ये होता है कि बिचौलियों का पौ-बारह हो जाता है, बिचौलिया लोग इसमें कमाते हैं और सरकार के सारे सिस्टम एक तरीके से देखा जाए तो फेल हो जाता है । महोदय, आज स्थिति यह है हम लोगों के औरंगाबाद, मदनपुर, देव, कुटुंबा, नवीनगर उत्तर कोयल परियोजना है, 1972 ई से प्रोजेक्ट लंबित है और आज के डेट में भी प्रधानमंत्री महोदय ने शिलान्यास किया 2018 में और 2014 में ही गया की धरती से बोले थे कि लाल-पानी पहुँचा देंगे, तब 2019 में वोट मांगने आयेंगे । लाल पानी तो नहीं पहुँचा महोदय लेकिन विडंबना देंखिये 2019 में पुनः बहुमत है, चलिए अब हम लोग आशान्वित हैं कि उत्तर कोयल परियोजना अब पूर्ण हो जायेगी और हम लोगों को कम से कम हमारे खेतों में सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था हो पायेगी । मोहम्मदगंज बैराज है महोदय, जिसमें यह एग्रीमेंट किया हुआ है, झारखंड सरकार से कि 2750 क्यूसेक पानी बिहार को मिलना है ।

सभापति(श्री मो0नेमतुल्लाह) : एक मिनट में समाप्त कीजिए ।

श्री आनंद शंकर सिंह : आज स्थिति ये है कि अनधिकृत ऑउटलेट बनने के चलते जो कि झारखंड सरकार द्वारा बनाए गये, आज सरकारी ऑकडा है कि 1000-1200 क्यूसेक पानी मिलता है लेकिन आज स्थिति यह है कि 500-600 क्यूसेक पानी औरंगाबाद के लोगों को, बिहार के लोगों को पानी मिलता है, आज वास्तविकता यह है । महोदय, पटाने नदी पर छोटी-छोटी नदियॉ है बरसाती नदियॉ हैं, हमलोगों को चेकडेम बनाने की आवश्यकता है आज स्थिति ये है कि बरसाती नदियों के किनारे जो गॉव हैं उन भारी जलस्तर के कारण आज पेयजल के संकट से रूबरू हो रहे है और सिंचाई की तो बात छोड़ दीजिए । पटाने नदी में औरंगाबाद जिला के अंतर्गत औरंगा प्रखंड में खैराबीन पंचायत रायपुरा ग्राम में चेकडेम का निर्माण कराए तो कम से कम जलस्तर भी मेंटेन हो और लोगों को सिंचाई की व्यवस्था भी मिले । स्थिति महोदय, खैरा मिर्जा पंचायत में खैरा आहर है चाहका का निर्माण हो जाता, बरियांवा बड़की आड़ में चाहका का निर्माण हो जाता तो वहॉ के किसानों को फायदा होता, अगर ग्राम परस्ती में करंजा है, टेकारी नदी है बरसाती नदी है और इतनी तेज से बहती है बरसात के बाद पानी वहॉ नहीं रहता ।

सभापति(श्री मो0नेमतुल्लाह) : अब खत्म कीजिए ।

श्री आनंद शंकर सिंह : 2 मिनट में महोदय खत्म करता हूॅ मैं ।

सभापति(श्री मो0नेमतुल्लाह) : बाकी सब लिख कर दे दीजिए ।

श्री आनंद शंकर सिंह : खैरा सालेम परस्ती में है ढिंगवा नाला पर चहका का निर्माण होगा तो वहॉं के गॉंव चातर, दोसमा, मदनपुरा.............

सभापति(श्री मो0नेमतुल्लाह) : सी0पी0आई0एम0एल0 के माननीय सदस्य श्री सुदामा प्रसाद जी।

श्री सुदामा प्रसाद जी : महोदय, आपका आभार की आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलूॅंगा, तो सरकार गंगा जल उद्योग योजना चलायेगी।

सभापति(श्री मो0नेमतुल्लाह) : 2 मिनट टाइम है आपका सुदामा जी ।

श्री सुदामा प्रसाद जी : ये ओरी का पानी पानी जो है बनेरी पर जायेगा, मोकामा 58 मीटर ऊचॉंई पर है समुद्र तल से और गया है 111 मीटर, 53 मीटर सरकार पानी ले जाएगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूॅं कि जिस तरह से 7 निश्चय में हर घर नल योजना का हस्र हुआ, उसी ढंग का इसका होगा । ये लूटपाट की योजना है महोदय, ये नहीं चलेगी सिंचाई के पक्ष में है । आते हैं मध्य बिहार में सोन नहर प्रणाली अपनी बरवादी पर 8-8 आंसु बहा रही है, उस पर ध्यान है आपका । 8-8 ऑंसु बहा रही है नहर के किनारे डिमला गये है । तमाम फाटक गायब है, मेठ पेट्रोल गायब है, नहरों का आधुनिकीकरण कराइये । 8 जिलों का मामला है महोदय, अगर वास्तव में आप पैसा खर्च करना चाहते हैं तो यहॉं खर्च कीजिए, अनाप-सनाप में नहीं कीजिए । अनाप-सनाप में पैसा खर्च हो रहा है, इसीलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं । गंडक नहर परियोजना, कोसी नहर परियोजना, सोन नहर परियोजना सारी परियोजनाऍं जरजर है जाकर उसको देख लीजिए । नहर की स्थिति देखिये और उसका आधुनिकीकरण कराइये, पैसा अगर खर्च करना है तब । किसानों की भलाई चाहते है तब । हम पैसा आपको क्यों दें, इसलिए दें कि तटबंध जो है उद्घाटन के पहले ही चुहा उसको खा जाये । इसलिए पैसा दिया जाए आपको, तटबंधा की राजनीति बंद किया जाए महोदय । वास्तव में अगर बाढ़ पर आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो भारत सरकार, नेपाल सरकार के साथ वार्ता करे और इसका एक स्थायी हल निकाले । एक रास्ता छोड़कर नहीं रखीये लूटपाट का। तीसरी बात की हर बार के बजट में इतने सरकारी नलकूप बंद पड़े हैं कितना चालू किया एक साल में, ये तो बता दीजिए । इसलिए आपको पैसा दिया जाए ।

क्रमशः

टर्न-19/04-03-2020/ज्योति-पुलकित

क्रमशः

श्री सुदामा प्रसाद : अभी यहॉं पर एक रिव्यू कमिटी बनी थी आपको बागमती नदी में वहॉं बांध बन रहा है वहॉं के किसानों के विरोध के कारण वह काम रुका लेकिन

बिना रिव्यू कमिटी की रिपोर्ट आए फिर ठेकेदार लोग चले गए हैं काम करने इसलिए इसपर रोक लगनी चाहिए । रोक लगाइये नहीं तो इसी तरह से पैसा अनाप-शनाप खर्च होता रहा है । जल जीवन हरियाली की सबसे बड़ी योजना है सोन नहर आपको याद होगा दोनों तरफ ऊंचे-ऊंचे शीशम के वृक्ष थे, महुआ के वृक्ष थे, सुंदर सड़कें थीं, व्यापार होता था, नहरों से । आज हेहर जमा हुआ है नहरों में 1973 में वाणसागर समझौते के अनुसार हमें पानी जो 40 लाख एकड़ फीट मिलना चाहिए, क्या सरकार के पास ये रिव्यू है कि हर साल पानी कितना मिलता है ? पानी नहीं मिलता है । पानी हम लोगों को रोपनी के टाईम में नहीं मिलता है, पानी मिलता है कटनी के टाईम में किसानों को बर्बाद करने के लिए पानी आता है और किसान मर रहे हैं, किसान बर्बाद हो रहे हैं, किसानों की खेती चौपट है इसलिए आप बिहारी स्वाभिमान की बात करते हैं तो मुख्यमंत्री जी बात करें केन्द्र के देख रेख में तीनों राज्यों की बैठक हो और हमें अपने हिस्से का पानी चाहिए । तो आपने बोलने का मौका दिया धन्यवाद और एक अनुरोध करना चाहेंगे कि हमारे सहार प्रखंड में तरारी विधान सभा में नहर पर एक पुल बनौटी में बना दिया जाय ।

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह): और कुछ हो तो लिखकर दे दीजिये मंत्री जी को । बहुत बहुत धन्यवाद आपका । अब राष्ट्रीय जनता दल की माननीय सदस्य श्रीमती समता देवी जी ।

श्रीमती समता देवी : सभापति महोदय, बोलने का मौका दिए अपनी ओर से आपको आभार प्रकट करती हूँ और अपने जितने भी राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं उनको भी धन्यवाद देती हूँ और विरोधी दल के नेता को भी धन्यवाद देती हूँ । महोदय, आज मैं सरकार के द्वारा लाये गए सिंचाई एवं अन्य विभागों को अनुदान मांग पर विपक्ष द्वारा लाये गए कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ी हूँ । महोदय, आज सिंचाई विभाग के अनुदान, महोदय, मंत्री जी द्वारा जो बजट पेश किया गया है उसमें से पूरी गहनता से पढ़ने पर स्वत: स्पष्ट होता है कि यह बजट सिंचाई के लिए कौन-से पूरे राज्य का नहीं है, केवल मधुबनी और दरभंगा जिला के लिए है । राज्य के ज्यादातर जिला सुखाड़ पर प्रभावित है जैसे गया, नवादा, जहानाबाद, दक्षिण बिहार लगभग सभी जिलों लेकिन बजट में पूरे दक्षिण बिहार में कुछ भी नहीं दिया गया है, लगता है कि मंत्री जी केवल मधुबनी के लिए ही सोचते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए । महोदय, सिंचाई की जरूरत दक्षिण बिहार में बहुत ज्यादा है । उत्तर बिहार दरभंगा मधुबनी में तो बोरिंग का पानी 50 फीट में मिल जाता है, लेकिन दक्षिण बिहार में 300 फीट

से नीचे पानी मिलता है । लेकिन इस बजट में केवल उत्तर बिहार के कुछ जिला है लेकिन दक्षिण बिहार की जनता पूरी तरह उपेक्षित महसूस कर रही है । इस मैथिली बजट से यह साबित होता है कि सिंचाई के अलावा बाढ़ नियंत्रण है जो कि प्राकृतिक रूप से उत्तर बिहार में आता है उस ओर ध्यान देना चाहिए लेकिन बाढ़ नियंत्रण का कार्य मगध और दक्षिण क्षेत्र में भी जरूरत है जो कि नहीं किया गया है और सिंचाई विभाग के दोनों प्रखंड सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण का पूरा खर्च उत्तर बिहार में ही समाहित किया गया है । अतः पुनः मैं इस मैथिली बजट की संज्ञा देती हूं । महोदय, ऐसा लगता है कि सिंचाई की सभी परियोजना बाढ़ प्रभावित इलाके में इसलिए दिया गया है कि बाढ़ के लिए सभी राशि निकासी कर ली गयी है और बाढ़ का बहाना बना कर कह दिया जायेगा कि बाढ़ एक कैनाल को चूहा काट लिया गया है जिसमें सभी बह गया है और पूरी राशि को बंदरबाट कर दिया गया है क्योंकि सफेद चूहा खा गया है ।

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

महोदय, बिहार में 2005 में जो सिंचाई की सुविधा थी आज 15 वर्षों में कितने एवं लाखों करोड़ो खर्च करने के बावजूद भी सिंचाई की क्षमता का विस्तार नहीं हुआ है । महोदय, बिहार में आज 2020 में सिंचाई क्षमता 2005 की तुलना में कम हुई है जबकि प्रचार प्रसार में ऐसा किया जा रहा है कि लगभग पूरे प्रदेश हरियाणा और पंजाब की तरह पूर्ण रूप से सिंचिंत हो गया है । महोदय, यह सरकार गरीब किसान मजदूर विरोधी है । इसके लिए बजट उसी तरह से पेश किया गया है । महोदय, वर्तमान सरकार की गया जिला की तरफ से ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी कि अगर गया जिला जिलान्तर्गत बाराचट्टी विधान सभा क्षेत्र में जल संसाधन बजट की कुछ राशि खर्च करती है तो सचमुच में किसानों के जीवन में हरियाली छा जायेगी और सरकार की जो योजना है जल जीवन हरियाली का भरपूर लाभ किसानों को मिलेगा । अध्यक्ष महोदय, बाराचट्टी विधान सभा क्षेत्र जंगल एवं पहाड़ से घिरा हुआ है । पानी का संकट है

अध्यक्ष : समता जी एक मिनट आप अपना स्थान ग्रहण कर लीजियेगा । आप बोलियेगा इसके बाद । माननीय नेता प्रतिपक्ष ।

कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:

'' दिनॉक 4 मार्च, 2020 के कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन पर सभा की सहमति हो ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''दिनॉक 04 मार्च, 2020 के कार्य-मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन पर सभा की सहमति हो ।

समिति ने निम्न सिफारिशें की हैं :

1- वृहस्पतिवार, दिनॉक 05 मार्च, 2020 को निर्धारित वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर वाद-विवाद तथा मतदान के उपरान्त, प्राप्त राजकीय विधेयक '' बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2020 '' का व्यवस्थापन हो,

2-शेष कार्य यथावत रहेंगे । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

कार्य-मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन पर सभा की सहमति हुई ।

अध्यक्ष : समता जी आपका 2-3 मिनट बचा हुआ है पूरा कर लीजिये ।

श्रीमती समता देवी : बाराचट्टी विधान सभा क्षेत्र जंगल और पहाड़ से घिरा हुआ है इस इलाके में पानी की कठिनाई इसलिए वर्तमान सरकार से मांग करती हूँ कि इस इलाका में छोटा-छोटा बांध जैसे दारो बांध, मनमझोर बांध, मंजवरी बांध, मंडी बराज बांध बन जाने से पानी ठहराव का केन्द्र बन जायेगा और किसानों की समस्या समाप्त हो जायेगी और जंगली जनवरों के लिए पानी पीने की सुविधा हो जायेगी। अध्यक्ष महोदय, बार-बार हमारे सरकार के द्वारा कहा जाता है कि 15 साल में जंगल राज है आपसे मैं कहना चाहती हूॅं सर कि जब हमारे लालू जी की सरकार थी तो दलितों को, पिछड़ो को, अकलियतों को मान-सम्मान मिलता था । आज मैं कहना चाहती हूॅं कि आज ब्लॉक में जाईये, जिला में जाईये किसी प्रतिनिधि की चाहे डी.एम हो या एस.पी. हो या एस.डी.ओ. या डी.एस.पी. हो किसी से उनकी बात नहीं हो सकती है । जब उन लोगों का मन होता है तो वे बात करते हैं नहीं तो नहीं बात करते हैं । मैं कहना चाहती हूँ सरकार से कि जब लालू जी की सरकार थी तो गांव के गांव इन्दिरा आवास बनता था । आज ऐसे लोगों का इन्दिरा आवास बनता है जिनके पास गाड़ी है, मकान है, पैसा है, उसका इन्दिरा आवास बनता है जो हमारे दलित हैं, पिछड़ा है, अकलियत है, गरीब है, इन्दिरा आवास उन्हें नहीं मिलता है । मैं कहना चाहती हूॅं कि जो पहले 15 साल में जो लालू जी के शासन काल में कानून बनता था उसी तरह से आज भी कानून बनाया जाय । मैं कहना चाहती हूँ, आप चुप्प रहिये जब महिला की बात आती है तो आप बोलियेगा मैं कहना चाहती हूॅं कि बार बार ये लोग 15 साल की बात करते हैं । ये लोग पहले बतायें 15 साल हो गया, क्या

महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ो के लिए, अकलियतों के लिए इन लोगों ने क्या काम किया, आज हम कहना चाहते हैं कि पटना के इलाके में हमारे दलित बसे हुए हैं, लालू जी के टाईम में दलितों के लिए घर बनाकर दिए थे । आज जल जीवन हरियाली के नाम पर दलितों का मकान तोड़ा जाता है ।

(इस अवसर पर मा0 सभापति,श्री मो0 नेमतुल्लाह ने आसन ग्रहण किया)

हमारे नीतीश जी कहते हैं कि दलितों के लिए पहले मकान बनाकर देंगे तब तोड़ेंगे और सबसे पहले उन्होंने तोड़ने का काम किए । 15 साल में लालू जी ने जितना दलित पिछड़ों के लिए काम किए । आप पहले अपने गिरेबान में झांकिए देखिये और सोचिए कि आपका दलित समाज कहाॅं है । आप धैर्य रखिये उसके बाद बोलियेगा ।

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह): समता जी, समाप्त कीजिये ।

श्रीमती समता देवी : मैं कहना चाहती हूॅं कि हमारे तेजस्वी जी आने वाले भविष्य हैं हम इनको कहेंगे हमारे जितने भी लोग हैं दलित समाज से हम कहेंगे कि उनके हाथ को मजबूत कीजिये आने वाला मुख्यमंत्री हैं, आप जाईये विदाई का समय आ गया है आपको लोग समझ गए हैं कि यह झूठा पार्टी हैं और झूठा आश्वासन देते हैं कि दलितों के लिए हम मकान देंगे, दलितों के लिए जमीन देंगे और आज हम पूछना चाहते हैं सरकार से कि कितने हमारे दलितों, मुशहरों भाईयों को इन्होंने जमीन देने का काम किए । इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूॅं। जय लालू, जय राबड़ी ।

टर्न-20/कृष्ण/04.03.2020

श्री राम बालक सिंह : सभापति महोदय, आज जल संसाधन विभाग,लघु जल संसाधन विभाग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के कटौती प्रस्ताव के खिलाफ यानी विपक्ष में बोलने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं ।

महोदय, मुझे बोलने का मौका दिया गया, सबसे पहले हम आपका आभार प्रकट करते हैं । साथ ही अपने माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का और माननीय मंत्री जी का भी हम आभार प्रकट करना चाहते हैं । महोदय, आज जल के बिना जीवन की कल्पना अधूरी है, आप जानते हैं, हम समस्तीपुर जिले के रहनेवाले हैं, जिस जिले में एक तरफ बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बलान और दूसरी तरफ हम गंगा नदी से घिरे हुये हैं । महोदय, हमारा जिला आधे से अधिक बाढ़ प्रभावित रहता है और लगभग आधा सुखाड़ से प्रभावित रहता है । लेकिन हम माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहते हैं कि उन्होंने होनेवाले जलवायु परिवर्त्तन और जल संकट को देखते हुये उन्होंने जल-जीवन-हरियाली जैसे

अतिमहत्वपूर्ण योजना चलाने का काम किया है और आप जानते हैं कि दोनों सदनों के माननीय सदस्यों के साथ मिलकर राय ली गयी और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के शुभ अवसर पर उन्होंने जल-जीवन-हरियाली कार्यक्रम शुभारंभ करने का काम किया है । माननीय मुख्यमंत्री जी इस अभियान को चला करके आनेवाले दुष्परिणामों से पहले बचने के लिये कृतसंकल्पित है । आप जानते हैं कि बिहार सहित पूरे देश और दुनियां में जो जल संकट होनेवाला है, उसमें सबसे पहला राज्य बिहार है, जहां के मुख्यमंत्री जी ने चिन्ता की और इन्होंने जलवायु परिवर्त्तन से बचने के लिये आज जल संचय एवं वृक्षारोपण जैसे महत्वपूर्ण कार्य करके उन्होंने बिहार का नाम देश एवं दुनियां में रौशन करने का काम किया है ।

महोदय, हमारा राज्य कृषि प्रधान राज्य है और यहां के किसानों की चिंता हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं कि जल कैसे हमारे किसानों के लिये सही समय पर और सही तरीके से भारी मात्रा मे उपलब्ध रहे और आज आप देख रहे हैं कि नहर, पईन और तालाबों को जो पूरे बिहार में परम्परागत जल स्रोत थे और उस पर जो अतिक्रमण थे, उसको उन्होंने अतिक्रमणमुक्त कराकर उसका सौंदर्यीकरण एवं जल संचय करने का काम उन्होंने वहां प्रारंभ किया है, उसके लिये हम माननीय मंत्री जी का भी हम आभार प्रकट करना चाहते हैं । पहले बाढ़ से पूर्व जल संसाधन विभाग कोई तैयारी नहीं करता था, लेकिन आज मुख्यमंत्री के निर्देश पर जुलाई से पहले, जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं, जहां बाढ़ आने की संभावना होती है, जल संसाधान विभाग समय से पूर्व बाढ़ निरोधक कार्यक्रम शुरू करता है, वह हमें आज देखने को मिलता है । लेकिन हम एक आग्रह करेंगे और अपना विचार देना चाहते हैं कि जो ऐसी नदियां हैं, जहां हम पहले से जानते हैं कि वहां बाढ़ की संभावना बनी रहती है, वैसे नदियां जैसे बूढ़ी गंडक, कमला जो भी है, वहां पर संभावित जगहों को पहले से चिन्हित कर के बाढ़ से बचने के लिये बांधों का पक्कीकरण एवं उसका ऊंचीकरण करने का काम करते हैं तो हमें बाढ़ से निश्चित रूप से निजात मिलेगी और हम बाढ़ से बच पायेंगे ।

सभापति समहोदय, हम कहना चाहते हैं कि हमारे समस्तीपुर के हमारे बड़े भाई श्री शाहीन जी बोल रहे थे कि 15 साल या जो अभी समय चल रहा है, उसमें जल संसाधन विभाग ने कोई काम ही नहीं किया । लेकिन आपके माध्यम से उनको कहना चाहते हैं कि समस्तीपुर में जल संसाधन विभाग के द्वारा बहुत सारे काम किये गये हैं और उनका घर समस्तीपुर जिला के हेडक्वार्टर में है, अगर वह स्मरण करने का काम करेंगे कि 15 साल पहले समस्तीपुर जिले का और जहां के वे विधायक हैं, 15 साल पहले उस जगह का हाल क्या था और आज समस्तीपुर

जिला का पूरे बिहार में अपना एक स्थान है, जहां विकास के कार्यों में सबसे ज्यादा काम हुआ है । वहां पॉलिटेकनिक कॉलेज बना है, मेडिकल कॉलेज बना है, आई0टी0आई0 की स्थापना हुई है और भारी संख्या में चौड़ी-चौड़ी सड़के बनी हैं ।

महोदय, हम कहना चाहते हैं कि उन सारे जगहों पर बांधों का ऊंचीकरण का कार्य किया गया है, पक्कीकरण का काम किया गया है और उनके क्षेत्र में भी पक्की सड़कों का काम बहुत ज्यादा किया गया है । लेकिन उनको नजर नहीं आता है । हम माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहते हैं और आप यह समझिये कि आप उनके बहुत करीबी हैं, पहले आप बगल में बैठते थे और अब हमारे मुख्यमंत्री जी आपको सामने बैठाते हैं । इसलिये आप उनके बहुत करीबी हैं । आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है ।

सभापति महोदय, हम कहना चाहते हैं कि हमारे विभूतिपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत अंगार घाट से ले कर कनकढाला तक बूढ़ी गंडक का दायां तटबंध है, जिसमें तीन पुल हैं और उस बांध के किनारे बहुत सारे बसावट हैं मतलब वहां बांध के किनारे बहुत भारी संख्या में लोग बसे हुये हैं । माननीय मुख्यमंत्री जी का यह संकल्प भी है कि सब लोगों के घरों तक हम पक्की सड़क बनाने का काम करेंगे । तो हम माननीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि अंगार घाट से लेकर जो कनकढाला है, वहां तक के दायां तटबंध का पक्कीकरण का कार्य कराने का कष्ट करेंगे । साथ ही नरहन से लेकर कनकढाला तक जो बांध है उस पर 20 साल पहले पक्की सड़क बनी थी लेकिन उसकी दोबारा मरम्मत नहीं होने के कारण वह जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हो गयी है । मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि 15 साल पहले जो रोड बना, उसको पुनः सही ढंग से दिखवाकर करके उसको बनाने का काम करेंगे ।

महोदय, लघु जल संसाधन विभाग के जो मंत्री जी हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि हमारे विभूतिपुर विधान सभा क्षेत्र में कुछ लिफ्ट इरीगेशन का बोरिंग है उसको भी ठीक करवाने का काम करेंगे । आज हम देख रहे हैं कि जलवायु परिवर्त्तन की वजह से हमारे देश के कई राज्यों में जल संकट हो गया है, समझ लीजिये कि जिस तरह से हमलोग पेट्रोल पम्प से डीजल, पेट्रोल लाने के लिये जाते हैं, जब जल का संकट हो जायेगा तो हमलोग टैंकर से पानी लेकर अपने घर का काम चलायेंगे तो आप समझ सकते हैं कि कितनी कठिनाई लोगों को होगी। इसलिए हम सभी लोगों से आग्रह करते हैं कि हमको संकल्पित होना है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी की महत्वकांक्षी योजना है जल संचय, जैसे सरकारी संस्थानों में जल संचय के लिये कार्य किये जा रहे हैं ।

क्रमश :

टर्न-21/अंजनी/दि0 04.03.2020

श्री राम बालक सिंह : (क्रमशः) : उसी तरह से गांव स्तर पर भी जल संचय का काम हो रहा है और अगर जलवायु परिवर्त्तन से हम अपने आपको निजात पाना चाहते हैं तो हमको वृक्षारोपण भी करना होगा । आज हमारी सरकार लाखों-लाख में वृक्षारोपण का काम कर रही है । माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे आग्रह करता हूँ और आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों की सुविधा के लिए बहुत काम कर रही है । वे चाहते हैं कि जो नहर है, उसका शुरू से अंत तक जो भी किसान सिंचाई के लिए पानी लेना चाहते हैं,,

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) : आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री राम बालक सिंह : उन किसानों को नहर से अंतिम छोर तक खेतों में पानी पहुंचाना चाहते हैं ।

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) : आपका समय हो गया । भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य श्री विद्या सागर केशरी जी । आपका दस मिनट समय है ।

श्री राम बालक सिंह : महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ ।

श्री विद्या सागर केशरी : सभापति महोदय, मैं आज जल संसाधन विभाग के बजट पर लाये गये कटौती प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । महोदय, मानव जीवन की संरचना ही पांच तत्वों के उपर आधारित है । जिसमें अग्नि, जल, वायु, आकाश और मिट्टी, ये पांच तत्व मूल रूप से मानव के संरचना में जाना जाता है, जिसमें जल तत्व जो है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है । हमारे शरीर का 80 प्रतिशत भाग जल के रूप में देखा जा सकता है । महोदय, भारत में अधिकांश नदियां हिमालय से चलकर और समुद्र तल तक जाकर मिलती है । नदियां कभी भी अभिशाप नहीं बनी है । वन, नदियां, कंदरायें, गुफायें और झरनें कभी भी मानव के लिए अभिशाप नहीं बनी है । उसी के संदर्भ में जो इतना बड़ा क्षेत्र है, नदियों में सबसे ज्यादे खुशनसीब हम हैं और हमारे बिहार के वासी हैं कि गंगा जैसी पवित्र नदी इसी बिहार के क्षेत्र से होकर गुजरती है । महोदय, नदियों का इतना बड़ा क्षेत्र रहने के बावजूद भी हम जल के महत्व को समझते हुए जल संसाधन में जो परेशानी खड़ी होती है जल के लिए, उसके विषय में गंगा का जो स्वरूप है, उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ । बिहार में गंगा की लम्बाई 445 किलोमीटर है और इसका जलग्रहण क्षेत्र 5,473 वर्ग किलोमीटर है । बिहार की अन्य नदियों में घाघरा नदी प्रणाली भी सबसे बड़ी नदी प्रणालियों में से एक है, जिसका क्षेत्र 1.27

लाख वर्ग किलोमीटर है और कुल लम्बाई 1,116 किलोमीटर है । जलग्रहण क्षेत्र के लिहाज से तीन अन्य प्रमुख नदियां कोसी 74.030 वर्ग किलोमीटर, सोन 70.228 वर्ग किलोमीटर और गंडक 40.553 वर्ग किलोमीटर है । पुनपुन, कोसी, बागमती और महानंदा नदियों के बेसिन एरिया में बाढ़ आती है, जिसके कारण जन, धन का काफी नुकसान होता है । महोदय, इतना बड़े भूभाग में नदी रहने के बावजूद हम जल संकट से गुजरते रहे हैं । सबसे प्रमुख बात यह है कि जो हमारा मीठा जल है, उसका अभाव हमें खलते रहता है । दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी को जो मीठा जल प्राप्त होना चाहिए, उसमें 96 प्वाइंट कुछ भाग वह खरा जल के रूप में प्राप्त है, मात्र 3 प्वाइंट कुछ भाग मीठा जल के रूप में प्राप्त है, जिसमें हिम क्षेत्र और कईएक क्षेत्र को मिलाने के बाद जो भूतल और जलवायु में जो मीठा जल प्राप्त है, उसी मीठा जल का एक छोटा-सा हिस्सा हमें प्राप्त होता है । महोदय, हमें जल-जीवन-हरियाली को लेकर इस प्रदेश के मुखिया श्रद्धेय नीतीश कुमार जी और उप मुखिया श्रद्धेय सुशील कुमार मोदी जी के नेतृत्व में जो जल-जीवन-हरियाली का एक कार्यक्रम रखा गया, इसके आलोक में 13 जुलाई, 2019 को विधान सभा के दोनों सदनों की राय के उपरान्त कार्यक्रम की शुरूआत 09 अगस्त, 2019 को किया गया है, जिसका शुभारंभ 02 अक्टूबर, 2019 को किया गया था । इसी के संदर्भ में एक अभियान चलाया गया कि हर घर में जल-नल की प्राप्ति हो और वह शुद्ध जल प्राप्त हो । शुद्ध जल कैसे मिले, उसके लिए हमारे बिहार के मुखिया बहुत चिंतित हैं । अभी हमलोग जल-जीवन-हरियाली के संदर्भ में बात कर रहे थे, उसमें खासतौर पर यह देखा जा रहा है कि जिस संसाधन के माध्यम से हम जल श्रोत को बचाना चाहते है, उसमें नदियों का, जलाशयों का बहुत बड़ा योगदान है । जो नदियां हैं, जो बड़ी-बड़ी नदियां हैं, जिसके बारे में मैंने अभी-अभी बताया है, उसमें काफी सिल्ट, गाद जमा पड़ा है । इस गाद को निकालने का जो सही संचालन है, वह हमें करना ही पड़ेगा ताकि नदियों का जो जल प्रवाह है, वह अविरल बह सके। महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि राज्य सरकार इस मानसून के चार महीने में गंगा का जल पाईप लाईन के माध्यम से नालन्दा, नवादा और गया जिले में जून,2021 तक उपलब्ध कराने पर युद्धस्तर पर कार्य कर रही है ताकि वहां के लोगों को पेय जल की सुविधा उपलबध हो सके । महोदय, राज्य की एन0डी0ए0 सरकार गया जिलान्तर्गत फल्गू नदी के बायें तट पर विष्णुपद मंदिर के निकट पूरे वर्ष कम-से-कम 0.60 मीटर जल उपलब्ध कराने पर भी कार्य कर रही है ताकि इस नदी में सालों भर पानी उपलब्ध हो सके। महोदय, राज्य सरकार किसानों को सिंचाई हेतु निजी नलकूप लगाने हेतु अनुदान दे

रही है । बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजनान्तर्गत वर्ष 2019-20 में किसानों द्वारा 15,572 निजी नलकूप लगाया गया है, जिससे 42 हजार 061 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का सृजन हुआ है । इस योजनान्तर्गत अब तक कुल 31,468 कृषकों द्वारा अधिष्ठापित निजी नलकूपों के विरूद्ध 67.44 करोड़ रूपये के अनुदान का भुगतान सरकार द्वारा किया गया है। महोदय, अभी हमारे माननीय सदस्य सुदामा भाई बोल रहे थे कि सरकार के द्वारा कितने नलकूप लगाये गये और कितने नलकूप बंद पड़े हुए हैं । मैं अपने सुदामा भाई को बताना चाहता हूँ कि सरकार द्वारा नलकूप सिंचाई योजना के तहत 10,240 नलकूपों में से क्रियाशील होने योग्य 9,192 राजकीय नलकूपों के विरूद्ध 4,984 चालू है और शेष नलकूपों की मरम्मति का कार्य किया जा रहा है । महोदय, राज्य सरकार एक एकड़ से अधिक रकवा के तालाबों, पोखरों, आहरों का जीर्णोद्धार कार्य एवं चेक डैम, वियर का निर्माण करा रही है ।

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) : अब आप समाप्त कीजिए ।

श्री विद्या सागर केशरी : ताकि सिंचाई कार्य के अतिरिक्त भूभर्ग जल पुनर्रीक्षण का कार्य किया जा सके । सभापति महोदय, हमारे यहां एक सीताधार है, हमारी अपनी समस्या है, सीताधार में 100 वर्षों से जल का निकास हुआ करता था नगर परिषद फारविसगंज से और आज उसका अतिक्रमण कर लिया गया है और अतिक्रमण के कारण बाढ़ की भयावह स्थिति पैदा हो जाती है । महोदय, हम एक-दो विषय वस्तु पर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहते हैं कि...

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) : आप सब लिखकर माननीय मंत्री जी को दे दें ।

श्री विद्या सागर केशरी : जो हमारे यहां ए0बी0सी0 नहर है, वह बथनाहा से लेकर अररिया तक जाती है, वह काफी जर्जर अवस्था में उसका सड़क है, उसको ठीक कराया जाय ।

टर्न-22/राजेश-राहुल/4.3.20

श्री कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव: आदरणीय सभापति महोदय, आज मैं जल संसाधन विभाग पर विपक्ष द्वारा लाये गये कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । सबसे पहले मैं अपने पिता मुद्रिका सिंह यादव जी का स्मरण करता हूं और आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव, विरोधी दल के नेता, तेजस्वी प्रसाद यादव के प्रति आभार प्रकट करता हूं । महोदय, वित्त मंत्री के द्वारा यहां जो बजट पेश किया गया था, इस किताब में एक पंक्ति है फर्स्ट पृष्ट पर, सरकार की तरफ से कि-

''हर बार चुनौतियों को ऐसे हराते हैं हम,

जख्म जितना गहरा हो, उतना मुस्कुराते हैं हम'' ।

लेकिन बिहार की जनता इसको दूसरे तरह से देखती है । सभापति महोदय, वह कहती है कि:

''हर बार चुनौतियों से ऐसे सरकार हारती है,

लोगों के जख्म जितने गहरे हो, सरकार उतना ही मुस्कुराती है।''

महोदय, हमें जब इस बात की जानकारी हुआ की जल संसाधन विभाग के कटौती प्रस्ताव पर बोलना है, इस किताब में सिंचाई प्रक्षेत्र और बाढ़ प्रक्षेत्र की चर्चा हुई है, हम ढूंढ रहे थे, जिसमें पहले लाईन में ही मध्य बिहार का जो जिला है नालंदा, नवादा, गया, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है कि गंगा के पानी को बोध-गया ले जाना, उसका उल्लेख किया गया है लेकिन इसके बाद हम जिस मध्य बिहार के इलाके से आते हैं जहानाबाद से, उसमें कहीं भी किसी भी जिला का कोई भी जल संसाधन विभाग की योजना का जिक्र नहीं है महोदय, ऐसे तो मध्य बिहार में प्रमुख नदियां, जिसमें सालों भर पानी प्रवाहित होता है, जैसे- सोन, पुनपुन, मोरहर, दरधा, फल्गु जैसी नदियां, जिसके बारे में इसमें कहीं भी चर्चा नहीं की गई है महोदय, मैं आपको मध्य बिहार के किसानों के लिए एक ज्वलंत समस्या आज इस सदन में पूर्व के मुख्यमंत्री जिनकी सोच बाबा साहेब अम्बेडकर, अमर शहीद जगदेव प्रसाद और संत रविदास जी के आदर्शों को जन-जन तक पहुंचाने का सोच था महोदय, आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के कार्यकाल की हम चर्चा करना चाहते हैं । मेरे पिता जी आज सदन में नहीं हैं लेकिन उस समय इसी सदन में ध्यानाकर्षण के माध्यम से अमर शहीद जगदेव प्रसाद ने जो सपना देखा था मध्य बिहार के किसानों के लिए, मध्य बिहार ही नहीं बल्कि पूरे बिहार की जो जमीन है, वह विश्व में सबसे उपजाऊ जमीन है महोदय, मध्य बिहार का जो पुनपुन नदी है, जिसमें सालों भर जल प्रवाहित होता है महोदय, आपने बताया था कि मुझे आठ मिनट बोलना है............

(व्यवधान)

महोदय, आपको हम बता दें मेरे पिता जी स्वर्गीय मुंद्रिका सिंह यादव जी के ध्यानाकर्षण के सवाल में सरकार ने उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने उस सवाल को गंभीरता से लेते हुए उस योजना की स्वीकृति देने का काम किया था, महोदय । हम सदन के माध्यम से सरकार को बताना चाहते हैं कि आखिर किन परिस्थितियों में सरकार का अरबों रूपया लगा करके वह योजना अधर में है, उस पर किसी भी तरह का काई विचार नहीं होता

है । महोदय, 13 अप्रैल की चर्चा माननीय सदस्य कर रहे थे इस सदन में की माननीय मुख्यमंत्री जी का जो जल, जीवन, हरियाली और बिहार में भूजल स्तर में गिरावट, जलवायु परिवर्तन पर जो चर्चा हुई थी, उस समय भी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराने का काम किया था कि अगर पुनपुन सिंचाई परियोजना को चालू करा करके और मोरहर, दरधा एवं फल्गू में उस पानी को गिरा करके अगर सिंचाई की व्यवस्था की जाय, तो सरकार की जो चिन्ता है जल, जीवन, हरियाली की, वह समाप्त होगी और मध्य बिहार के किसानों के चेहरे पर जो उदासी है, उसमें खुशहाली आने का काम करेगा महोदय । महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लघु सिंचाई विभाग से जल, जीवन, हरियाली के तहत पईन, आहर की उड़ाही हो रही है, हम अपने इलाके जहानाबाद की बात बता रहे हैं कि जिन गरीब के गांव से वह पईन गुजरता है, वह पईन की उड़ाही होने के बाद उसके रहन-सहन का प्रॉब्लम हो रहा है............

(व्यवधान)

सभापति (श्री मो0नेमतुल्लाह): अब आप समाप्त कीजिये ।

श्री कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव: महोदय, एक मिनट । महोदय, हम अपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करते हैं कि उन गरीबों के गांव में पईन को पक्कीकरण करके उसपर ढलान करके रास्ता भी बनाया जाय क्योंकि जहां पईन का लाइन हो रहा है, तो वहां के लोगों का जीवन भी नारकीय हो गया है और वे गरीब आज इस पईन उड़ाही के चलते अपने घर से बेघर हो रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया............

(व्यवधान)

सभापति (श्री मो0 नेमतुल्लाह): अब आपका समय समाप्त हुआ । अब निर्दलीय माननीय सदस्या श्रीमती बेबी कुमारी जी ।

श्रीमती बेबी कुमारी: महोदय, मैं जल संसाधन विभाग के प्रस्तुत माँग के समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं । जिस तरह से जल संसाधन विभाग पर राज्य के सिंचाई क्षेत्र के विकास का दायित्व है उसमें यह सरकार निरंतर सफलता प्राप्त कर रही है । मैं एक ही उदाहरण केवल देना चाहती हूं कि वर्ष 2018-19 में जल संसाधन विभाग का स्कीम मद में 2513 करोड़ रु0 तथा स्कीम स्थापना एवं प्रतिपूर्ति व्यय में 983 करोड़ रु0 का बजट था जो 2019-20 में स्कीम मद में 2662 करोड़ रु0 तथा स्थापना एवं प्रतिपूर्ति व्यय में 989 करोड़ रु0 का बजट हुआ । इस बार जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसमें सकीम मद में तीन हजार करोड़ रु0 तथा स्थापना एवं

प्रतिपूर्ति व्यय में 1053 करोड़ रु0 का बजट का प्रावधान है । महोदय, जल संसाधन विभाग को दो इकाई में विभक्त किया गया है- पहला है सिंचाई प्रक्षेत्र और दूसरा है बाढ़ प्रक्षेत्र । सिंचाई प्रक्षेत्र के जिम्मे नदियों से निकलने वाली जमीन अथवा जो जब जमाव के क्षेत्र हैं उससे मिलने वाली जमीन को कृषि योग्य बनाना है । इसके तहत बहुत सारी योजनाएं ली गई हैं । इन योजनाओं में नवादा, गया एवं नालंदा में पुनः 2021 तक गंगा जल का उद्वह करके पाईप लाईन के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने, विष्णु पद मंदिर के निकट पूरे वर्ष कम से कम आधे मीटर से अधिक जल उपलब्ध रहे, ऐसी व्यवस्था की जा रही है । सामान्य से कम वर्षापात होने की स्थिति में भी 2019 की खरीफ में 19 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी ।

क्रमशः

टर्न-23/सत्येन्द्र-मुकुल/04-03-2020.03.04

क्रमशः

श्रीमती बेबी कुमारी: वर्ष 2019 में 196 कटाव निरोधक कार्य पूर्ण किये गये थे और वर्ष 2020 के पूर्व 120 बाढ़ सुरक्षात्मक योजनाओं को पूर्ण किया जायेगा। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्म स्थल सिताव दियारा गांव की सुरक्षा हेतु रिंग बांध के निर्माण का कार्य 90 प्रतिशत से अधिक पूरा कर लिया गया है। 1309 करोड़ रुपये की लागत से मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर एवं दरभंगा जिलान्तर्गत बाढ़ प्रबंधन परियोजना फेज-2 के तहत तटबंध के सुदृढ़ीकरण एवं तटबंध निर्माण कार्य मार्च, 2020 तक पूरा कर लिया जायेगा। महोदय, आंकड़ों से ज्यादा उल्लेख करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि पुस्तिकाएं पहले से ही वितरित हैं। मुख्य बात यह है कि सरकार और हमारे ऊर्जावान मंत्री लगातार जल संसाधन विभाग की कार्य प्रणाली को तंदुरुस्त करने जा रहे हैं।

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह):अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्रीमती बेबी कुमारी: सभापति महोदय, एक मिनट और समय दिया जाय। मैं कुछ अपने क्षेत्र...

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह): बेबी कुमारी जी, आप अपनी बात समाप्त कीजिए। आपका समय समाप्त हुआ।

श्रीमती बेबी कुमारी: सभापति महोदय, एक मिनट। बूढ़ी गंडक नदी के बांध सड़क पर पाईप लाईन...

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह): माननीय सदस्या, अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्रीमती बेबी कुमारीः सभापति महोदय, आप हमें 2 मिनट और बोलने दीजिए। बूढ़ी गंडक नदी के बांध सड़क के निर्माण की फाईल 5 साल से लंबित है, पूर्व में उसका टेंडर हुआ था लेकिन अभी तक बूढ़ी गंडक नदी का बांध जो अखाड़ाघाट से होकर समस्तीपुर तक जाती है, वह रोड अभी तक पेंडिंग है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि मंत्री जी इसको देखवा लें। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए बहुत-बहुत आभार और बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री लाल बाबू राम : सभापति महोदय, आपने मुझे सदन में बोलने का मौका दिया इसके लिए आभार प्रकट करते हैं और प्रतिपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी पार्टी की तरफ से मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए उनको भी आभार प्रकट करते हैं और मैं कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। सभापति महोदय, जल संसाधन विभाग एक बहुत बड़ा विभाग है। किसान, मजदूर, व्यापारी, जीव-जन्तु सभी के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। जल संसाधन विभाग द्वारा 4053.61 करोड़ रुपये की राशि का आवंटन किया गया है। सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इतनी बड़ी राशि को जो सरकार में बैठे सृजन चोर जैसे लोग हैं जिनकी सरकार में योजनाओं को चूहे खा जाते हैं ऐसे लोगों से इस राशि को बचाने की जरूरत है। जब बाढ़ आती है तो मंत्री जी से पूछा जाता है कि बांध पर आपने इतना पैसा खर्च किया तो बांध कैसे टूट गया तो बेबाक होकर के मंत्री जी बोलते हैं कि यह बांध चूहे के कारण टूट गया और बाढ़ आ गयी इसलिए मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि सृजन चोर जैसे लोगों से इस राशि को बचाने का काम करें जो सरकार में बैठे हुए हैं। सरकार का इसमें बरदहस्त प्राप्त है कि जिस भी घोटाले में सरकार के संबंधित मंत्री हो, विधायक हो उनका नाम आता है तो बड़ी मजबूती के साथ उनको बचाने का काम करते हैं। सभापति महोदय, हम कहना चाहेंगे कि सात निश्चय योजना अन्तर्गत नल-जल योजना है जो बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इसमें नल-जल योजना की राशि को वार्ड सदस्य, मुखिया द्वारा पदाधिकारियों की मिलीभगत से इसमें बहुत बड़ा लूट हो रहा है। सभापति महोदय आज सरकार के द्वारा चलाये जा रहे नल-जल योजना को बिहार के किसी कोने में चले जायं, किसी वार्ड में इसकी जांच करवा लें तो सच्चाई सामने आ जायेगी। सभापति महोदय, हम लोग सदन में देखते हैं कि जब हमारे सत्तापक्ष लोग आते हैं तो वे सबसे पहले अपनी सरकार की उपलब्धि नहीं बता करके, किसानों और मजदूरों के बारे में, जनता के कल्याण के बारे में नहीं बता करके

वे 15 साल, 15 साल, 15 साल बताने का काम करते हैं। हम उन्हें बताना चाहते हैं कि आजादी के बाद भी दलितों-शोषितों के साथ अन्याय हो रहा था उनके साथ राजनीतिक रूप से, धार्मिक रूप से, आर्थिक रूप से शोषण किया जाता था। सभापति महोदय, इस समाज के लोगों के बीच छुआ-छूत का भावना था, भेद-भाव था, असमानता था, जब वर्ष 1990 में जब बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय लालू प्रसाद यादव जी बनें तो इन्होंने दलितो, शोषितों को समानता का अधिकार दिया, बोलने का अधिकार दिया और लोहिया जी के, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के और बाबा साहेब डॉ. भीम राव अम्बेडकर जी के सपनों को साकार करने का काम किया जिसके बल पर आज गरीब मजदूर का बेटा लाल बाबू राम, शिवचन्द्र राम और राजेन्द्र राम जैसे लोग जीतकर के विधान सभा में आने का काम किये हैं । हम सत्तापक्ष के लोगों से बोलना चाहते हैं कि अनुसूचित जाति के लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है जो कट ऑफ मार्क्स समाप्त कर दिया गया, प्रोन्नति में आरक्षण समाप्त कर दिया गया, बैकलॉग समाप्त कर दिया गया, एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट को समाप्त कर दिया गया। महोदय,आज 2 अप्रैल को राष्ट्रीय जनता दल के लोग एकजुट होकर देशबंदी करने का काम नहीं करते तो आज एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट भी नहीं बचता। सभापति महोदय, मैं सत्ता पक्ष के लोगों से कहना चाहता हूँ कि ये समाप्त करने वाले कौन लोग हैं क्योंकि सत्ता में जो बेठे हुए हैं ये मनुवादी विचारधारा के मानने वाले लोग हैं ये अम्बेडकर की विचारधारा के मानने वाले लोग नहीं हैं। सभापति महोदय, हम सकरा विधानसभा के बारे में बताना चाहते हैं कि वहां पर वर्ष 1977 में जब तत्कालीन मुख्यमंत्री जनजनायक कर्पूरी ठाकुर जी थे वहां पर एक तिरहुत नहर जो बगहा से चलकर के आयी है, वहां मुरौल में जब आया तो इस नहर की अनुपयोगिता देखकर विनाशकारी समझकर के वहां के लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले और कहे कि इस नहर को रोक दिया जाय, उन्होंने तत्काल प्रभाव से रोक दिया और आपके तत्कालीन सचिव अरुण कुमार बसु के पत्रांक-923 डी0एल0ए0 1979 के तहत 12-1-79 को तत्काल प्रभाव से आदेश किये कि इस नहर को रोक दिया जाय और इस नहर को बूढ़ी गंडक में मिला भी दिया गया। चालीस वर्षों के बाद महोदय महत्वपूर्ण और बहुत ही गंभीर मामला है सभापति महोदय, चालीस वर्षों के बाद..

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) आप समाप्त कीजिये। अब लोक जनशक्ति पार्टी के माननीय सदस्य श्री राजू तिवारी जी।

श्री राजू तिवारी: सभापति महोदय, मैं सरकार के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

(व्यवधान)

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) आप बोलिये, आपका दो मिनट समय है, सरकार का उत्तर भी होगा।

श्री राजू तिवारी: एकदम सीधे मुद्दे पर ही आ रहा हूँ महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2001 में बहुत जबर्दस्त बाढ़ आयी थी उस समय मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक नहर पर ही रिंग बांध बन गया था। मैं माननीय मंत्री जी और विभाग के सिक्रेटरी से व्यक्तिगत रूप से मिला और मुझे बहुत खुशी के साथ कहना है कि आज वहां ह्यूम पाईप लाईन डालकर के वर्ष 2001 में जो नहर बंद थी, लगभग 50-60 गांव को वहां नहर की सुविधा होते हुए भी पानी नहीं मिलता था और वह चालू हो गया है तो मैं सरकार के मंत्री के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि उनके द्वारा मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक बड़ा काम किया गया। महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र में आदरणीय मंत्री जी से मैं आग्रह किया हूँ, काम भी जल्दी उम्मीद है कि लग जायेगा जिस तरह से अभी मेरे यहां नहर से पटवन चालू हो गया, आउटलेट जिस नहर पर जो 20 साल से 18 साल से नहीं बना पानी बंद था, आउटलेट खराब हो गया तो महोदय आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वह आउटलेट को बनवा दिया जाय ताकि जो पानी कुछ बर्बाद हो रहा है वह भी बर्बाद होने से बचे। महोदय, गंडक नदी के किनारे लगभग 40 कि0मी0 के आसपास मेरा विधानसभा क्षेत्र पड़ता है उस पर विभाग के द्वारा ईंटीकरण का काम कराया गया था कुछ साल पहले, जिसके दोनों तरफ आबादी है, दोनों तरफ कहीं-कहीं लोग बसे हुए हैं तो महोदय आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि उस पर कालीकरण कराने की प्रक्रिया करें जिससे दोनों तरफ मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक नया रोड मिल जाय।

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) अब आप समाप्त कीजिये।

श्री राजू तिवारी: धन्यवाद।

टर्न-24/मधुप-हेमंत/04.03.2020

सभापति (श्री मो0 नेमतुल्लाह) : माननीय सदस्य श्री गुलाब यादव, दो मिनट में आप समाप्त कीजिए क्योंकि अब सरकार का उत्तर होगा ।

श्री गुलाब यादव : महोदय, आज हमें बोलने का मौका दिया, इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ । साथ-ही, हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू जी और राजमाता राबड़ी देवी जी के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ, पार्टी की ओर से जिन्होंने हमें बोलने का मौका दिया, उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ ।

सभापति महोदय, जल संसाधन विभाग पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । (व्यवधान) सही-सही ही बता रहा हूँ कि जल संसाधन विभाग हमारी कमला नदी का बाँध.... (व्यवधान) सुनिए न । कमला नदी का बाँध हर साल टूट जाता है । मधुबनी जिला का सबसे महत्वपूर्ण झंझारपुर है जहाँ हमारे मंत्री जी का घर भी है वहीं पर और किसी साल ऐसा नहीं होता है कि वहाँ बाँध नहीं टूटता है और इस साल भी बहुत सारे बाँध टूटने के कारण बहुत सारे आदमी की डेथ हो गयी है, घर धँस गया है लेकिन मंत्री जी कान में रुई देकर सोये रहते हैं, बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं । झंझारपुर में कहते हैं कि सफेद चूहा बाँध खा गया, हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि सफेद चूहा पकड़ने वाली कोई मशीन उपलब्ध कराये हैं कि नहीं, क्या आगे भी सफेद चूहे ऐसे ही बाँध खाते रहेंगे ?

हमारे यहाँ जो भी नहर का काम चल रहा है, हम पानी नहर में तो नहीं देखे हैं, गरीब किसान, कुशवाहा समाज को मंत्री जी ने उजाड़ दिया है । जो कुछ जमीन बची हुई थी, जो साग-सब्जी लगाने का काम था, साग-सब्जी उजाड़ कर अपने ताकत के बल पर, प्रशासन से लाठी और डंडे चलवाकर पुलिस का, जबर्दस्ती इन्होंने भू-अर्जन के बिना पैसा दिये हुए जबर्दस्ती लाठी-डंडे के बल पर नहर खुदवा रहे हैं । मंत्री जी से यही आग्रह करेंगे कि गरीब किसान है, किसानों को पहले भुगतान करा दीजिए फसल का और जमीन का भू-अर्जन से भुगतान कराकर नहर बनाते, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, सबने कहा है कि मधुबनी जिला में आपने विशेष काम किये हैं, उसके लिए धन्यवाद के पात्र भी आप हैं कि मधुबनी जिला में बिहार के अन्य जिलों से ज्यादा काम किये हैं, उसके लिए कोई आपत्ति नहीं है, मेरा एक ही कहना है कि किसान की जो जमीन बर्बाद हुई कुशवाहा समाज की, बताइये छोटे-छोटे किसान हैं, जिसकी जमीन का आपने अधिग्रहण किया है, उससे ज्यादा जमीन आपने गोभी, बैंगन की क्षति आपने काटकर उनका नुकसान किया है । आगे सही रहेगा कि कम से कम उसके फसल की क्षति की भरपाई दे दें ताकि गरीब किसान की कम से कम रोजी-रोटी चले । किसान बहुत

आहत है । पानी तो जब आयेगा तब आयेगा आपके नहर में, जमीन नहीं बचेगा तो पानी लेकर किसान क्या करेगा ?

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

जमीन वैसे भी बिहार में बहुत कम है । बिहार में ज्यादा से ज्यादा जमीन कोसी में है, कमला नदी में है ।

अध्यक्ष : अब आप समाप्त करें ।

श्री गुलाब यादव : अध्यक्ष महोदय, आप आये हैं तो दो मिनट बोलने का मौका दिया जाय । हमारे माननीय मंत्री जी अभी तक बॉध को जोड़ने का काम नहीं किये हैं । कमला नदी...

अध्यक्ष : भले ही हम यहॉ अभी आये हों लेकिन आप जब से बोल रहे हैं, हम आपको सुन रहे हैं।

श्री गुलाब यादव : मंत्री जी, कमला नदी इतनी बड़ी नदी है कि हमारे महासिंहसौली पंचायत में दर्जिया गॉव पड़ा हुआ है, हम स्वयं गये थे शिलान्यास में, वहॉ गये तो देखा कि नदी पूरे घर के घर काट रही है । मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि वहॉ पर कम से कम बचे हुये घर को कटने से बचायें और सफेद चूहा आगे नहीं लगे, उसके लिए कोई व्यवस्था करें ।

अंत में एक शब्द कहना है, मंत्री जी, आप बाहर के राज्य के लोगों को काम देते हैं, बिहार राज्य को काम मिलेगा तो बिहार के मजदूर को रोजगार मिलेगा, ऐसे भी बिहार बेरोजगारी से गुजर रहा है, कम से कम रोजगार बिहारियों को मिलेगा । जो बाहर वाले आते हैं, बाहर से काम करके चले जाते हैं, इसलिए मंत्री जी से आग्रह है कि बिहार के नौजवानों को काम मिलेगा तो मंत्री जी को दुआ भी मिलेगी, गरीब-गुरबा का घर भी चलेगा । बिहार वैसे भी बेरोजगारी से पूरा त्रस्त है। मंत्री जी से यही आग्रह है कि कमला बॉध, कम से कम जो नदी किनारे हमलोगों का बहुत-सा घर है, भर रात बाढ़ में हमलोग सो नहीं पाते हैं ।

श्री मो0 नेमतुल्लाह : महोदय....

अध्यक्ष : नेमतुल्लाह जी, कुछ कहना चाहते हैं । एक मिनट में आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री मो0 नेमतुल्लाह : महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में गोपालगंज जिला के मांझा प्रखंड में एक नहर पर पुल है, जहॉ पर मध्य विद्यालय है वहॉ पुल नहीं है, इसके पहले जो मंत्री जी थे, उन्होंने आश्वासन दिया था, उसके लिए फाइल भी बढ़ी थी, उस पुल को बनवा दिया जाय । यही मेरा मंत्री जी से आग्रह है ।

अध्यक्ष : अब सरकार का उत्तर होगा । माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग ।

<u>सरकार का उत्तर</u>

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज जल संसाधन विभाग के इस बजट सत्र 2020-21 के दौरान जितने माननीय सदस्यों की बात इस बजट को लेकर के आयी है - भाई यदुवंश यादव जी, निरंजन मेहता जी, गायत्री देवी जी, विनय वर्मा जी, अख्तरूल इस्लाम साहब, रणधीर सोनी जी, राजीव नन्दन जी, आनंद शंकर सिंह जी, समता देवी जी, राम बालक सिंह जी, माननीय विद्यासागर केशरी जी, माननीय सुदय यादव जी, बेबी कुमारी जी, लाल बाबू राम जी, राजू तिवारी जी, गुलाब यादव जी, मैं सबको धन्यवाद देता हूं कि इस बजट के ऊपर जो भी उन्होंने अपने सुझाव दिये हैं, मैंने कोशिश की है कि जो-जो बातें आयी हैं उसको भी बाद में इसमें इनकॉरपोरेट करने का, जोड़ने का.....

श्री मो0 नेमतुल्लाह : हमने भी अपनी बात रखी है ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : हां, आपने भी अपनी बात रखी है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 2020-21 के बजट सत्र के दौरान जल संसाधन विभाग के लिए मॉग संख्या-49 के अंतर्गत विभाग में चल रही योजनाओं एवं गतिविधियों से सदन के माननीय सदस्यों को अवगत कराने का मुझे अवसर मिला है । हम सभी जानते हैं कि जल के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। पर्यावरण की सुरक्षा के साथ-साथ कृषि और औद्योगिक विकास के लिए भी जल की पर्याप्त उपलब्धता जरूरी है, हमारे बिहार के संदर्भ में जल के दूरदर्शितापूर्ण प्रबंधन, संरक्षण तथा सदुपयोग की महत्ता और बढ़ गयी है क्योंकि असामान्य वर्षा जलवायु परिवर्तन के चलते हर साल राज्य के किसी हिस्से में बाढ़ आ जाती है किसी हिस्से में सुखाड़ आ जाता है । विभिन्न अध्ययनों की रिपोर्ट में आया है यदि हमने तुरंत कारगर कदम नहीं उठाये तो वर्ष 2050 तक राज्य के अधिकतर क्षेत्रों में जल की उपलब्धता घटकर अत्यंत ही खतरनाक स्थिति में पहुंच जायेगी । जल संसाधन विभाग ने भी एक अपनी स्टडी करायी थी और उस अध्ययन के अनुसार वर्ष 2001 में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 1594 क्यूबिक मीटर थी 2001 में, जो अनुमान किया जा रहा है उस स्टडी के हिसाब से कि 2025 में वह घटकर 1006 क्यूबिक मीटर प्रति व्यक्ति हो जायेगी और 2050 में वह 633 क्यूबिक मीटर रह जायेगी । तो यह स्थिति जल की है । अब जब 13 जुलाई को दोनों सदन की बैठक करके जल-जीवन-हरियाली अभियान पर एक परिचर्चा हुई, 9 अगस्त को इसकी शुरुआत हुई और 2 अक्टूबर से इसका शुभारंभ हुआ । इस अभियान में बहुत सारा पैरामीटर तय किया गया और इसमें जो जल संसाधन विभाग के जिम्मे एक इम्पोर्टेन्ट काम दिया गया, वह काम था कि जो अधिशेष जल है जो समुद्र में चला जाता है बाढ़ के समय

में जो मानसून सीजन होता है 4 महीने, उस पानी को रोक करके और उसको ट्रीट करके जो साउथ बिहार में गया है, बोधगया है और राजगीर है, फर्स्ट फेज में, क्योंकि उस समय वहां पर टैंकर से पीने का पानी दिया जाता है, देश के बहुत सारे हिस्सों में ऐसा काम शुरू हुआ है और सक्सेसफुली किया गया है । उन सब जगहों में पीने के पानी का प्रबंध किया जाय । अभी 28 फरवरी को भुवनेश्वर में जब ईस्ट रीजन की मीटिंग हुई थी जिसमें चारों स्टेट के, जो ईस्ट रीजन में आते हैं झारखंड के, उड़ीसा के, पश्चिम बंगाल के और बिहार के मुख्यमंत्री वहां थे, वहां पर जो बिहार के मुद्दे थे जल संसाधन विभाग के, खासकर के उन्होंने जो गंगा में गाद की स्थिति रहती है वह मुद्दा वहां पर उठाया कि भारत सरकार को एक नेशनल पॉलिसी सिल्ट पर बनानी चाहिए उसी से संबंधित जब बात आयी उस समय उसी मीटिंग में उन्होंने फरक्का बराज को लेकर जो बार-बार मुख्यमंत्री जी के द्वारा उठाया गया कि फरक्का बराज का जिस समय डिजाइन किया गया था और उसका पानी जिस हिसाब से जाता है..

..क्रमशः..

टर्न-25/आजाद/04.03.2020

..... क्रमशः .....

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : उसका फ्लो ठीक नहीं है, जब तक उसका नेट्रोफीटींग नहीं होता है या उसके डिजाइन को चेंज नहीं किया जाता है तो उसके अपस्ट्रीम में ऊपर के भाग में शिल्ट जमा होता है, विभिन्न स्टडी से यह बात ऊभर कर आयी है और वहां पर उस मीटिंग में 28 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको प्रमुखता से उठाया और जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थीं ममती बनर्जी जी, वह भी इसको लार्जली एग्री की कि यह समस्या वहां पर है । इसी तरह से बिहार के एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट महानन्दा सिंचाई योजना है, जिससे पूरा सीमांचल एरिया का, जिससे सिंचाई होगी करीब 67 हजार एकड़ का और 78 का ट्रिटी है बंगाल और बिहार का, लेकिन बंगाल में 8 कि0मी0 जो उसका बनना है, बंगाल के अन्दर महानन्दा सिंचाई परियोजना के तहत पश्चिम बंगाल में अवस्थित फुलवारी बाजार से किशनगंज के 67 हजार एकड़ भूमि के लिए सिंचाई सुविधा दी जानी थी, इस बाबत उन्होंने बंगाल के मुख्यमंत्री जी से 8 कि0मी0 नहर निर्माण को प्राथमिकता देने की बात कही है । हालांकि वहां की मुख्यमंत्री बार-बार बोल रही थीं कि पानी नहीं है लेकिन इस बात को उठाया गया और यह बात रखी गयी, इसमें दोबारा जॉच होगी, यह बात हुई और इसका कोई न कोई वे-आऊट निकालने का, लेकिन

यह बात वहां पर रखी गयी । एक फरक्का बराज की बात, एक महानन्दा में सिंचाई योजना जो 78 का ट्रिटी को आज तक इम्पलीमेंट नहीं हुआ, वह बात और झारखंड सरकार के साथ जो तिलैया ढ़ाढर योजना है, जो बटाने जलाशय योजना है, जो धनराजे जलाशय योजना है, यह सब जो इन्टर-स्टेट रिलेटेड मुद्दा था, इन सब मुद्दा को वहां पर रखा गया । निश्चित रूप से आने वाले समय में, क्योंकि फरक्का को लेकर के कमिटी भी बना दी गई है और कमिटी का अपना एक स्टडी होता है, उसमें बिहार के जल संसाधन विभाग के लोग रहेंगे और कुछ न कुछ नतीजा, चूँकि जिस हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखा है, निश्चित रूप से आने वाले समय में कुछ न कुछ नतीजा निकलना चाहिए ।

अब जो गंगा लिफ्ट योजना की बात कर रहे थे, इस योजना के तहत मोकामा के निकट राजेन्द्र सेतु के पास गंगा जल को मौनसून के 4 महीनों में लिफ्ट करके घोसवरी, सरमेरा, बिहारशरीफ नया बाईपास गिरियक के रास्ते गया में मानपुर के पास यह ले जाया जायेगा । यह करीब 148.6 कि0मी0 का है पाईप लाईन और बीच में पूरे वर्ष के आवश्यकता के अनुसार ले जाया जायेगा मौनसून में जुलाई से अक्टूबर तक लेकिन पीने के पानी का इन्तजाम साल भर का होगा । इसमें बीच में पूरे वर्ष की आवश्यकता के अनुसार जल का भंडारण, घोड़ा-कटोरा झील, पंचाने नदी, घोड़ा-कटोरा के बीच प्रस्तावित जलाशय, तेतर पंचायत के वेकेयपुर ग्राम के निकट पहाड़ी के पास प्रस्तावित जलाशय और अबगिला जो मानपुर में प्रस्तावित आर0सी0सी0 टैंक में किया जायेगा । नवादा जिले के मुतनाजे ग्राम में एक डिटेनशन टैंक और राजगीर के लिए एक जलशोधन संयंत्र तथा गया जिले के अबगिला में बोधगया तथा गया के लिए जलशोधन संयंत्र बनाया जायेगा । इस जलशोधन संयंत्रों में शोधित पेयजल को पाईप लाईन के द्वारा घर-घर तक पहुँचाया जायेगा । इस काम को जून 2021 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है, काम शुरू हो चुका है और आपको पता है कि वहां पर बड़ी संख्या में गया जो बोधगया में है, जो यूनेस्को का साईट माना जाता है, इतनी बड़ी संख्या में लगभग दो करोड़ पर्यटक, अभी वहां की जनसंख्या 9 लाख है और 2051 तक 13-14 लाख जनसंख्या होने की संभावना है । अभी जो भी प्लान किया गया है वह 2051 को ध्यान में रखकर के उस समय पानी की क्या जरूरत होगी, पीने के पानी की, इसको ध्यान में रखकर के यह परियोजना बनाया गया है और प्रत्येक व्यक्ति 135 लीटर पानी को प्रतिदिन ध्यान में रखकर उतने पानी को ट्रीट करके पीने का पानी पाईप के द्वारा घर-घर तक इन तीनों शहरों में पहुँचाया जायेगा, यह प्रस्ताव है, इसपर काम चल रहा है । 135 लीटर पानी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से

जोड़कर के, कलकुलेट करके यह स्कीम बनाया गया है और जैसा मैंने कहा कि जून 2021 तक इसका फर्स्ट फेज पूरा हो जायेगा । इसी तरह बहुत अति-महत्वाकांक्षा पूर्ण योजना जो हमेशा आपने देखा होगा, जो गया के हमारे साथी हैं, वे हमेशा उठाते भी रहते थे और इसको माननीय मुख्यमंत्री जी पर्सनली जाकर के जो फल्गू रिवर में इतनी बड़ी संख्या में लोग पिन्ड दान करने आते हैं और देश ही नहीं विदेश से भी वहां लोग आते हैं तो वहां भी पानी नहीं रहता है, बालू खोदकर के पानी निकलाते हैं तो उसपर पर्सनली जाकर के मुख्यमंत्री जी का निदेश हुआ और विभाग ने उसपर काम करना शुरू किया, उसका स्टडी जो डी0पी0आर0 का काम है, उसका जियोलॉजिकल स्टडी, उसका हाइड्रोलॉजिकल स्टडी यह सारा काम लगभग पूरा हो गया है और इसी महीने मार्च के अन्त तक उसपर डी0पी0आर0 का काम पूरा करके हमलोग इसपर काम शुरू कर देंगे और यह प्रयास रहेगा कि 2 फीट पानी फल्गू रिवर में लोग कंफ्यूज करके गंगा जल जा रहा है, वही जा रहा है, ऐसा नहीं है, जो गंगा का पानी है, उसको पीने के लिए हमलोग गया, बोधगया, राजगीर में ले जा रहे हैं लेकिन जो फल्गू रिवर में 2 फीट पानी रखने की बात है, उसमें अपस्ट्रीम में और डाऊनस्ट्रीम में, आधा कि0मी0 अपस्ट्रीम में और आधा कि0मी0 डाऊनस्ट्रीम में परमानेन्ट सालो भर 2 फीट रहे, ऐसी व्यवस्था की योजना बन रही है और निश्चित रूप से इसमें अप्रैल में काम शुरू हो जायेगा । इसके अलावा एक जो महत्वपूर्ण काम, जो इस विभाग द्वारा किया गया और जिसकी चर्चा आज देश में भी हो रही है, जो पुराने हैं क्योंकि जल, जीवन, हरियाली में सारा जो पुराना तालाब, कुँआ इन सब को जीर्णोधार की बात की गई है, उसमें जो लखनदेयी नदी है, सीतामढ़ी में, जिसको लेकर के आज देश में बहुत सारे लोग प्रशंसा कर रहे हैं, विभाग को और बिहार सरकार की, इसको जो दुबारा जीर्णोधार किया गया है और जिसका शिलान्यास मुख्यमंत्री जी के द्वारा 15 फरवरी, 2018 को किया गया और इसके मद्देनजर लखनदेयी नदी की नई धार को पुरानी धार से मिलाने और पुराने धार की उड़ाही का कार्य कराया जा रहा है । आज इस नदी का नया रूप बिल्कुल बदला हुआ है और इस इनोवेटिव जीर्णोधार को राष्टीय स्तर पर सराहा गया है । इस कार्य योजना का 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया गया है और जिसके अन्तर्गत 18 किलोमीटर में रिसेक्शनिंग कार्य, दो डी0एल0आर0 ब्रिज का कार्य पूर्ण हो गया है एवं नेपाल बॉर्डर से बिहार के सीतामढ़ी जिला के दुलारपुर गांव तक 3 किलोमीटर की लंबाई में लिंक चैनल का निर्माण कराया जाना है । जिसके लिए 33 एकड़ भू-अर्जन हेतु प्रकिया भी पूरी कर ली गई है, इस योजना को 2020 बाढ़ से पहले पूर्ण करने का कार्यक्रम है ।

इससे सोनवर्षा, बथनाहा, सीतामढ़ी और रूनीसैदपुर प्रखंड के लगभग 3539.86 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि का पूर्णोधार हो पायेगा, इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण जगह इस साल मैंने देखा कि नए वर्ष में कितने सारे लोग बाल्मिकीनगर गए और बाल्मिकीनगर में जिस हिसाब से विभाग के द्वारा वहां जो इकोपार्क बनाया गया है, वहां जो गेस्टहाउस के ऊपर इकोहर्ट बनाया गया और इसके अलावा बाल्मिकीनगर बराज के अपस्ट्रिम में गंडक नदी के बाएं तट पर आई0बी0 के सामने 1080 मीटर की लंबाई में सुरक्षात्मक कार्य पूरा किया गया, इससे मैकफेरी कॉन्सेप्ट का उपयोग करते हुए पत्थर से रिटेनिंग वॉल बनाया गया जो काफी कॉस्ट अफेक्टिव है । उक्त दोनों कार्यो का उद्घाटन नवंबर, 2019 में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है । इन कार्यों से न केवल बाल्मिकीनगर बराज, बाल्मिकीनगर टाइगर रिजर्व अभयारण्य क्षेत्र को सुरक्षा मिलेगी, बल्कि एक बहुत बड़े पर्यटक स्थल के रूप में बाल्मिकीनगर आज देश में उभरकर के आया है । इसके अतिरिक्त वहां पर 10010 की मीटर की लम्बाई में आगे जो कॉलेश्वर मंदिर तक, वहां तक वॉकिंग ट्रैक लगभग चार किलोमीटर का 2.9 किलोमीटर का पाथवे बन गया है । एक पार्ट बन गया, दूसरा पार्ट जो बन रहा है जिससे पर्यटकों को कॉलेश्वर स्थान पहुंचने में सहायता होगी एवं पर्यटकों को इस पैदल पथ को पेवर ब्लॉक के द्वारा बनाया गया है, जिससे किसी भी मौसम में उपयोग किया जा सकता है ।

...... क्रमशः ......

टर्न-26/शंभु-धिरेन्द्र/04.03.20

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : क्रमशः....जिसे किसी भी मौसम में उपयोग किया जा सकता है । इसी गंडक नदी के दायें भाग में भी तटबंध की सुरक्षा के दृष्टिकोण से 77 करोड़ रूपये की लागत से 3310 मीटर की लंबाई में सुरक्षात्मक कार्य आधुनिक तकनीक का उपयोग कर कराया जा रहा है । माननीय अध्यक्ष महोदय, 2005 से 2006 में माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में नयी सरकार बनने के बाद से राज्य में जल संसाधन तथा जल सिंचाई से जुड़ी योजनाओं को कितनी अहमियत मिली, इसे विभाग की लैंड एक्सपेंडीचर योजनागत व्यय के आंकड़ों से आसानी से समझा जा सकता है । पिछले 15 वर्षों में यानी 2005-06 से 2019-20 तक विभाग के कुल योजनागत व्यय 22055.58 करोड़.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आज सुदामा जी, लगता है आप देर तक सुनियेगा क्योंकि न महबूब जी हैं, न सत्यदेव जी हैं ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : पिछले 15 वर्षों में 2005-06 से 2019-20 तक विभाग का कुल योजनागत व्यय 22055.58 करोड़ रूपया हुआ है । जब इससे पहले के 15 वर्षों में 1990 से 2005 तक कुल योजनागत व्यय सिर्फ 3415 करोड़ रूपये रहा । यानी 2005 से पहले के 15 वर्षों की तुलना में पिछले 15 वर्षों में जल संसाधन विभाग के योजनाओं के सीधे क्रियान्वयन में लगभग सात गुणा ज्यादा राशि खर्च हुई है । यह स्थिति तब है जब दस वर्ष झारखण्ड भी साथ में था । महाशय, मैं सदन का ध्यान इस ओर भी आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि वर्ष 1991 से 2004-05 तक विभाग का स्थापना मद में.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : ललित जी, थोड़ा और सुन लीजिए न, फिर जो करना होगा वह तो कीजियेगा ही ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि वर्ष 1990 से 2005 तक विभाग का स्थापना मद में व्यय 3700 करोड़ था जो इस अवधि की योजना मद से 300 करोड़ रूपया अधिक था । इसके विपरीत 2004-05 से 15 वर्षों में विभाग का स्थापना मद में व्यय योजना मद से लगभग 10 हजार रूपया कम रहा है जो हमारी बदली कार्यशैली और विकास के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है । पिछले वर्षों में जल संसाधन विभाग के इससे सदन के व्यापक संभव इसलिए पाया क्योंकि.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप ठीक कह रहे हैं, जो करना चाहते हैं वह कर लीजिए ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : किसानों को लाभ पहुंचानेवाली योजनाओं में बिहार जैसे कृषि प्रधान राज्य में, सिंचाई सुविधा के विस्तार की कितनी अहमियत है । इससे सदन के माननीय सदस्य भलीभांति परिचित होंगे । आपको यह जानकर खुशी होगी कि राज्य में 2005-06 से 2019-20 तक.....

(व्यवधान)

(इस अवसर पर राजद के माननीय सदस्य ने सदन से बहिर्गमन किया)

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अभी हम किन्हीं को समय नहीं दिये हैं, सबलोग बोलकर चले गये आप उस लाइन पर हैं तो हम क्या करें ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा कई अन्य योजनाओं के सूत्रण का कार्य किया जा रहा है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बोलिये न ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : इसमें दक्षिण बिहार की नदियों में मौनसून की अवधि में प्राप्त अधिशेष जल का चेकडैम वीयर बनाकर संचयन करते हुए उपयोग करने और उत्तर बिहार की नदियों में मानसून की अवधि में प्राप्त अधिशेष जल को पोखर का निर्माण कर एवं नदियों के किनारे कुआं बनाकर संरक्षण करते हुए उपयोग करने की योजनाएं शामिल है ।

श्री अवधेश कुमार सिंह : मुख्यमंत्री जी बैठक किये हैं और ये जब भी सदन में बैठते ही लोग 15 साल बनाम 15 साल बोलने लगते हैं । माननीय मुख्यमंत्री जी का 15वाँ साल जा रहा है । यह जो डबल इंजन की सरकार है ।

अध्यक्ष : अवधेश जी, अगर इतनी महत्वपूर्ण बात थी तो आप ही अपने दल के लिए समय आवंटित करते हैं आपने क्यों नहीं अपने दल के समय अच्छे से कहा । माननीय मंत्री जी।

श्री अवधेश कुमार सिंह : हमने सोचा कि......

(व्यवधान)

(इस अवसर पर कांग्रेस एवं सी0पी0आई0माले के माननीय सदस्य ने सदन से बहिर्गमन किया)

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : इसके अलावा मृतप्राय नदियों को पुनर्जीवित करने पर जोर, बढ़ती जनसंख्या एवं पर्यावरण की कीमत पर जारी विकास कार्यों के कारण प्रकृति प्रदत्त नदियों, झीलों एवं अन्य जल स्रोत सीमित होते जा रहे हैं । यहां तक कि कई नदियां मृतप्राय हो गयी है । बिहार के भागलपुर जिला का चम्पानाला, दरभंगा एवं मधुबनी जिले में जीवछ कमला, पुरानी कमला, सोनी गोहियाम, मोहिनी, सिवान जिला में डाहा एवं नालन्दा जिला के सकरी, जिराइन तथा कुमरी नदी इसके ज्वलंत उदाहरण हैं । माननीय मुख्यमंत्री जी के जल जीवन हरियाली अभियान के तहत सभी जल स्रोतों, तालाबों, आहरों, सार्वजनिक कुओं आदि की पहचान कर इन्हें मुक्त कर पुनरूद्धार का कार्य किया जा रहा है । जल संसाधन विभाग इस बात के प्रति सजगता से कार्य कर रहा है कि हमारी नदियों को पुनर्जीवित करने से पर्यावरण और जल संकट की समस्या से निपटने में अप्रत्याशित सहयोग मिलेगा । माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य के संपूर्ण सिंचाई परिदृश्य में बृहद् एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का महत्वपूर्ण योगदान है । इन परियोजनाओं के विकास, रख-रखाव तथा कुशल संचालन के प्रति विभाग सतत प्रयत्नशील है । माननीय मुख्यमंत्री जी के निदेश के आलोक में विभाग का पुनर्गठन कर सिंचाई कार्य को एक अलग अभियंता प्रमुख के अधीन रखा गया है ताकि हर परिस्थिति में सिंचाई कार्यक्रमों पर उचित ध्यान दिया जा सके । मुख्यमंत्री जी की आकांक्षा रही है जो उन्होंने जाहिर भी किया है कि हर खेत को पानी पहुंचे । इसी प्रेरणा से आगे जल संसाधन विभाग अपनी प्राथमिकता तय करता रहेगा । राज्य में बृहद् एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं से संभावित

इष्टतम सिंचाई क्षमता 53.53 लाख हेक्टेयर के विरूद्ध अब तक 30 लाख 25 हजार हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का सृजन किया जा चुका है । वर्ष 2019-20 के दौरान लखीसराय, जमुई, कैमूर, मधुबनी आदि के जिले में 13 सिंचाई कार्यों को क्रियान्वित कराकर लगभग 21 हजार हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन किया जायेगा । अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजन के साथ-साथ 18 कार्यों के क्रियान्वयन में कुल 32 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में जो लॉस्ट इरीगेशन क्षमता ह्रासित सिंचाई क्षमता को पुनर्स्थापित करने का कार्य किया जा रहा है । इसमें पश्चिमी गंडक नहर प्रणाली का सारण मुख्य नहर और इसके वितरणी प्रणालियों का पुनर्स्थापन महत्वपूर्ण है, जिसमें 18 हजार हेक्टेयर लॉस्ट इरीगेशन पोटेंशियल का पुनर्स्थापन हुआ है । इसमें सारण, सिवान और गोपालगंज जिले के हजारों किसान को सिंचाई की सुविधा प्राप्त होगी । इसके अतिरिक्त लखीसराय, जहानाबाद, बक्सर, रोहतास, पटना, गया, भागलपुर आदि जिलों के योजनाओं में लॉस्ट इरीगेशन पोटेंशियल को पुनर्स्थापित करने का कार्य संपन्न कराया गया है । टाल विकास योजना के लिए बेहतर उपयोग एवं प्रबंधन के लिये विभाग दृढ़संकल्प है । इसके लिए एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार किया गया है । इस योजना का मुख्य अवयव 5 एन्टी फ्लड स्लूइस का निर्माण, उत्तरी एवं दक्षिणी छोर पर दो अदद तटबंध का निर्माण, जमींदारी बांधों का उच्चीकरण, भू-भाग जल के साथ सतही जल का सर्वोत्तम आर्थिक उपयोग के साथ 215 प्रतिशत क्रॉपिंग इन्टेनसिटी प्राप्त करना, टाल क्षेत्र में उपस्थित जलाशयों का गहरा कर, उसमें मछली पालन तथा जलीय उत्पादन को विकसित करना तथा अवस्थित पइनों का डिशिल्टिंग कर ड्रेनेज व्यवस्था को कारगर बनाना है । मोकामा टाल क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण कार्य के अन्तर्गत 4 एन्टी फ्लड स्लूइस, 1 एन्टी फ्लड स्लूइस कम रेगुलेटर का निर्माण कार्य प्रस्तावित है जिसमें 4 एन्टी फ्लड स्लूइस का कार्य पूर्ण है, एक-एक पर काम प्रगति में है । इन योजनाओं के कार्यान्वयन से लगभग 60 हजार हेक्टेयर क्षेत्र को जल जमाव से मुक्त किया जा सकता है ।

क्रमशः

टर्न-27/04-03-2020./ज्योति-पुलकित

क्रमशः

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : इन योजनाओं के कार्यान्वयन से लगभग 60 हजार हेक्टेयर क्षेत्र को जल जमाव से मुक्त किया जा सकता है । वर्ष 2020-21 में जो एडीशनल सिंचाई क्षेत्र का सृजन किया जा रहा है, उसमें कुल 1 लाख 3 हजार हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन होगा । इसमें मधुबनी जिला का पश्चिमी कोशी नहर परियोजना, दरभंगा जिला का अलीनगर प्रखंड में

गरौल वीयर सिंचाई योजना का कार्य, पुरानी कमला नदी के बघेला घाट पर सिंचाई योजना का कार्य, मोहिउद्दीननगर पकड़ी में टिकमा नदी पर सिंचाई योजना का कार्य, बलवाघाट बराज-सह-सिंचाई योजना का कार्य, पूर्वी गण्डक नहर प्रणाली फेज-टू का अवशेष कार्य, पश्चिमी गण्डक नहर प्रणाली में सारण मुख्य नहर एवं इसकी वितरण प्रणालियों के पुनर्स्थापन का अवेशष कार्य, बटेश्वरस्थान गंगा पम्प नहर योजना फेज-टू, दुर्गावती जलाशय परियोजना का अवशेष कार्य और मंडई वियर योजना अति महत्वपूर्ण है । महोदय, अतिरिक्त सिंचाई क्षमता के सृजन में मैं दो योजनाओं की चर्चा विशेष रुप से करना चाहता हूँ यह पश्चिमी कोशी नहर जो मधुबनी और एक पार्ट दरभंगा जिला में आता है । इसका डी.पी.आर. 1962 ई0 में बना हमलोग तो पैदा भी नहीं हुए थे । उस समय इसका डी.पी.आर. बना । इसके पूर्ण होने से दो लाख 34 हजार 800 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हो सकेगी और हमारा मानना है इस परियोजना के पूरा होने से मिथिलाचंल में दूसरी हरित क्रान्ति 100 परसेंट इसी पश्चिमी कोशी नहर परियोजना के आने के बाद आयेगी । इस महत्वपूर्ण परियोजना का डी.पी.आर. 58 साल पहले बना । परियोजना के अवशेष कार्य को शीघ्र पूरा कराने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है । इसी साल नवम्बर में मुख्यमंत्री जी के द्वारा जब यह मधुबनी जिला के मधेपुर में थे उनके हाथ से शिलान्यास किया गया । उसके काम चल रहा है और इसी साल जून में लगभग 68 हजार हेक्टेयर जमीन में हमलोग पानी वहाँ पहुंचा देंगे । इस परियोजना के पूर्ण होने से दरभंगा और मधुबनी जिला के लाखों किसानों को इससे सुविधा मिलेगी । दूसरी योजना जो दुर्गावती जलाशय योजना है । जो रोहतास और कैमूर जिला के इस अति महत्वपूर्ण परियोजना का शिलान्यास 1976 में तत्कालीन उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम जी ने किया था । लेकिन विभिन्न कारणों से यह अधर में लटकी रही । मुझे सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की दृढ़ इच्छा शक्ति और गहरी रुचि के कारण इस मृत प्राय परियोजना को पुनर्जीवित किया गया और इसका कार्य अंतिम चरण में है इसे वर्ष 2020-21 में पूर्ण करने का कार्यक्रम है । वर्ष 2020-21 में लॉस्ट एरीगेशन क्षमता के पुनर्स्थापन का कार्य किया जा रहा है । इस योजना से 1 लाख 41 हजार 862 हेक्टेयर क्षेत्र में लॉस्ट एरीगेशन पोटेन्शियल को दुबारा पुनर्स्थापित किया जायेगा । इसमें गण्डक नहर, खगड़गपुर झील सिंचाई योजना, आंजन जलाशय योजना, उदेरास्थान बराज सिंचाई योजना, नालन्दा जिला अंतर्गत बेन प्रखण्ड में स्थित वीयर योजना, जिराईन नदी पर वीयर निर्माण, मलई बराज

योजना, तियरा पम्प सिंचाई योजना, बदुआ जलाशय योजना आदि महत्वपूर्ण हैं । पश्चिमी गण्डक (सारण मुख्य नहर एवं इसकी वितरण प्रणाली) के 1.47 लाख हेक्टेयर लॉस्ट एरीगेशन पोटेनशियल क्षमता का पुनर्स्थापन एवं 1.58 लाख हेक्टेयर में नई सिंचाई क्षमता का सृजन कार्य 2061.82 करोड़ रूपए की लागत से प्रगति पर है । इसके तहत 0.89 लाख हेक्टेयर लॉस्ट एरीगेशन क्षमता का पुनर्स्थापन एवं 0.72 लाख हेक्टेयर में नई सिंचाई क्षमता का सृजन कार्य कराया जा चुका है । कार्य के कार्यान्वयन के उपरांत गोपालगंज जिले के 14 प्रखण्डों, सारण जिले के 20 प्रखण्डों तथा सिवान जिले के 19 प्रखण्डों के किसानों को सिंचाई सुविधा का लाभ मिलेगा । नहरों के अंतिम छोर तक पानी पहुँचाकर ज्यादा-से-ज्यादा किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना भी विभाग का एक महत्वपूर्ण दायित्व है । वर्ष 2019 में खरीफ के दौरान जब सामान्य से कम वर्षापात होने के कारण किसानों को धान की रोपणी में कठिनाई हो रही थी, तब नहरों के द्वारा सिंचाई उपलब्ध कराकर उन्हें लाभ पहुँचाया गया और कुल 21.3 लाख हेक्टेयर के विरुद्ध 19.12 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई, जो लक्ष्य का लगभग 90 प्रतिशत है । गत वर्ष गरमा सिंचाई के दौरान 28.67 हजार हेक्टेयर के लक्ष्य के विरुद्ध 23.66 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्धा कराई गई । रबी सिंचाई अभी उपलब्ध कराई जा रही है। एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है, नदी योजना को लेकर के जो सरकार की प्राथमिकता भी है और इसमें योजना कोसी मेची लिंक को लेकर के जिसकी अनुमानित राशि 49,00 करोड़ रूपये है । इसके कारण से किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार जिलों के 2.1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में किसानों को सिंचाई का लाभ मिलेगा । यह योजना काफी समय से लम्बित था, यह योजना वन एवं भारत सरकार के पास लम्बित था । मैं भी विभाग में जा करके जलशक्ति मंत्रालय वहाँ से परश्यू किया और भारत सरकार में जा करके इसकी स्वीकृति पिछले दिनों इसकी स्वीकृति इंवायरमेंट एडं फॉरेस्ट मिनिस्ट्री से मिल गई है, अब हम लोगों का प्रयास हैं कि भारत सरकार के राष्ट्रीय योजना में शामिल है क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट है और उससे पूरा सीमांचल क्षेत्र का सारा जमीन इससे सिंचित हो जाएगा । निश्चित रूप से हम लोगों का प्रयास होगा कि भारत सरकार इसको जो अपने राष्ट्रीय योजना है उसमें शामिल करें उसके लिए हम प्रयासरत हैं । इसी तरह नदी जोड़ योजना में दो और महत्वपूर्ण योजना विभाग के जरिए काम किया जा रहा है वो सकरी-नाटा लिंक योजना है और बूढ़ी गंडक-नून-बाया-गंगा लिंक योजना जिसके डी0पी0आर0 अंतिम चरण में है ।

श्री महेश्वर यादव : अध्यक्ष महोदय, भाषण के दौरान बागमती नदी जो उत्तर बिहार में कहर ढाने का काम करती है बागमती बांध परियोजना के अधूरे बांध को पूरा करने की कोई चर्चा इन्होंने नहीं किया । हम माननीय मुख्यमंत्री जी का भी ध्यान आकृष्ट किए हुए हैं ।

अध्यक्ष : आप सारी सूचना दे दीजियेगा, जरुर चर्चा करेंगे ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : बागमती वाला मुख्यमंत्री जी के प्रायरिटी में है । दो बार तो उनके सामने सारा प्रेजेन्टेशन हुआ है, सारा कुछ देखें हैं और बिल्कुल वह फाईनल चरण में है उसमें जल्द ही काम शुरु हो जायेगा । महोदय, वर्ष 2019 में महोदय, भीषण बाढ़ आयी । भीषण बाढ़ में कमला में 8 जगह, दो लेफ्ट साईड में और 6 राईट साईड में 13 जुलाई को बांध टूट गया चूँकि इतना जलस्राव नेपाल की तरफ से आया था इतनी अतिवृष्टि हुई थी उसी दिन मुख्यमंत्री जाकर पर्सनली देख कर सारे बांधों को आए थे और उसके बाद हमलोगों ने वहॉं पर आई.आई.टी. रुड़की को काम दिया कि हरेक साल जो यह टूटता है और इतनी बड़ी क्षति होती है और आई.आई.टी. रुड़की के प्रोफेसर को देकर उनकी रिपोर्ट आ गयी है और जो भी नयी टेक्नोलॉजी उन्होंने रेकोमेंड किया है उसी बेसिस पर कैबिनेट से पास हो करके टेण्डर फाईनल हो गया है और इसपर वहॉं पर काम शुरु हो गया है और 15 मई से पहले यह सारा काम कर लिया जायेगा । मैं दो मिनट केवल और टाईम लूँगा । इसके अलावा जो बातें हैं उसको प्रोसिडिंग्स का पार्ट .. ।

अध्यक्ष : बन जायेगा ।

श्री संजय कुमार सिंह, मंत्री : एक तो हम बनाकर लाए हैं कविता और बाकी को प्रोसिडिंग्स का पार्ट बना दिया जाय ।

अध्यक्ष : ठीक है । वही तो हम देख रहे थे कि भाषण में कविता है जिसको आप पढ़ नहीं रहे हैं ।

(माननीय मंत्री के भाषण का लिखित अंश-परिशिष्ट द्रष्टव्य)

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : महोदय, ‘‘कहीं न हो मृगजल, बस थोड़ी सी कोशिश भर में,
छिपा हुआ है हल, अगर सहेजी आज बूंद तो बचा रहेगा कल ।
बची रहेगी रंगत, रौनक, धरती की हरियाली,
फूल, पांखुरी, डाली, बेलें, तितली रंगों वाली,
बूंद-बूंद संचय करने की, हम सब करें पहल ।
बची रहे मुस्कान अधर की, बची रहे अभिलाषा,
रहे धरा पर इतना पानी, रहे न कोई प्यासा,

नदियाँ भी हो, पोखर भी हो, कहीं न हो मृगजल ।

इसी आशा, विश्वास और संकल्प के साथ सदन से अनुरोध है कि जल संसाधन विभाग के लिए प्रस्तावित बजट उपलब्ध कराया जाए । विभाग सभी जनोपयोगी कार्यक्रमों को ससमय पूरा करने के प्रति दृढ़संकल्पित है ।

धन्यवाद !

टर्न-28/कृष्ण/04.03.2020

अध्यक्ष : आपकी कविता तो जल संसाधन विभाग के साथ-साथ जल-जीवन-हरियाली कार्यक्रम से ज्यादा जुड़ी हुई है । आप माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव जी से अनुरोध कर दीजिये कि वह अपना कटौती प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री संजय कुमार झा,मंत्री : माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव जी से अनुरोध है कि कटौती प्रस्ताव वापस लिया जाय ।

अध्यक्ष : अब सरकार का उत्तर समाप्त हुआ ।

मैं कटौती प्रस्ताव को लेता हूं ।

क्या माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

" इस शीर्षक की मांग 10/-रूपये से घटाई जाय ।"

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अब मैं मूल प्रस्ताव को लेता हूं ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

" जल संसाधन विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्त्ति के लिये 40,53,61,19,000/- (चालीस अरब तिरपन करोड़ एकसठ लाख उन्नीस हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय । "

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मांग स्वीकृत हुई ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 04 मार्च,2020 के लिये स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या 30 (तीस) है । अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाय ।

(सदन की सहमति हुई)

अब सभा की बैठक वृहस्पतिवार, दिनांक 05 मार्च, 2020 के 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिये स्थगित की जाती है ।

माननीय मंत्री के भाषण का अंश

परिशिष्ट

श्री संजय कुमार झा

माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, बिहार

का बजट सत्र 2020–21 के दौरान सदन में अभिभाषण

माननीय अध्यक्ष महोदय,

वर्ष 2020–21 के बजट सत्र के दौरान जल संसाधन विभाग के लिए मांग संख्या–49 के अंतर्गत, विभाग में चल रही योजनाओं एवं अन्य गतिविधियों से सदन के माननीय सदस्यों को अवगत कराने का मुझे अवसर मिला है।

हम सभी जानते हैं कि जल के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। पर्यावरण की सुरक्षा के साथ–साथ कृषि और औद्योगिक विकास के लिए भी जल की पर्याप्त उपलब्धता जरूरी है। हमारे बिहार के संदर्भ में जल के दूरदर्शितापूर्ण प्रबंधन, संरक्षण तथा सदुपयोग की महत्ता और भी बढ़ जाती है, क्योंकि असामान्य वर्षा एवं जलवायु परिवर्तन के चलते हर साल राज्य के किसी हिस्से को भीषण बाढ़, तो किसी हिस्से को सुखाड़ की त्रासदी झेलनी पड़ रही है। असामान्य वर्षा के कारण बिहार में भू–गर्भ जलस्तर तेजी से नीचे जा रहा है। विभिन्न अध्ययनों की रिपोर्ट में बताया गया है कि यदि हमने तुरंत कारगर कदम नहीं उठाया तो वर्ष 2050 तक राज्य के अधिकतर क्षेत्रों में जल की उपलब्धता घटकर अत्यंत ही खतरनाक स्थिति में पहुँच जायेगी। जल संसाधन विभाग में कराए गए एक अध्ययन के अनुसार राज्य में वर्ष 2001 में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 1594 क्यूबिक मीटर थी, जो घटकर वर्ष 2025 में 1006 क्यूबिक मीटर और वर्ष 2050 में 635 क्यूबिक मीटर रह जाएगी।

'जल–जीवन–हरियाली' अभियान

मुझे यह बताते हुए खुशी है कि भविष्य के संभावित गंभीर पर्यावरणीय खतरों से निपटने के प्रति इस सदन के नेता, राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी पूरी तरह सचेत हैं। इसके लिए 13 जुलाई, 2019 को विधानसभा के दोनों सदनों की बैठक बुला कर माननीय सदस्यों की राय ली गई। तदुपरांत माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 'जल–जीवन–हरियाली' नामक एक अति महत्वाकांक्षी अभियान के प्रति जन जागरूकता कार्यक्रम की शुरूआत 9 अगस्त, 2019 को, जबकि इस अभियान का विधिवत शुभारंभ 02 अक्टूबर, 2019 को किया गया।

महोदय, 'जल–जीवन–हरियाली' अभियान बिहार को आसन्न पर्यावरणीय खतरों से बचाने की दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी की एक दूरदर्शितापूर्ण पहल है। इसके तहत् दूरगामी परिणाम देने वाले कई ऐसे कार्य शुरू किये गये हैं। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण कार्य है, नदी के अधिशेष जल जो बह जाता है उसे उन इलाकों में पहुँचाना, जहाँ जल संकट गहरा रहा है। इसके लिए अति महत्वाकांक्षी "Ganga water lift scheme" की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें मॉनसून की अवधि में गंगा के अधिशेष जल को राजगीर, गया, बोधगया और नवादा शहर पहुँचाया जाना है, जहाँ इसे सालों भर पेयजल के रूप में उपयोग किया जायेगा।

गंगा जल उद्वह योजना (Ganga water lift scheme)

यहाँ सभी अवगत हैं कि फल्गू नदी के तट पर बसा गया शहर पर्यटन की दृष्टि से विश्व के मानचित्र पर है। पितृपक्ष के अवसर पर विष्णुपद मंदिर के निकट पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए देश–विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं। ऐतिहासिक एवं धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण राजगीर और बोधगया शहर भी सभी धर्मों के लोगों के लिए आकर्षण का केन्द्र है और हर साल लाखों देशी–विदेशी पर्यटक यहाँ आते हैं। बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर बौद्ध धर्मावलम्बियों के लिए पवित्र स्थल है, जिसे यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया है। इस दृष्टिकोण से राजगीर, बोधगया और गया शहर में सालोंभर पेयजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना अति आवश्यक है।

राजगीर एक अंर्तराष्ट्रीय स्तर का धार्मिक स्थल है जो सम्राट बिम्बिसार की पहली राजधानी भी थी जहाँ हो रहे विकास कार्यों, यथा नालंदा विश्वविधालय, अंर्तराष्ट्रीय स्टेडियम, पुलिस प्रशिक्षण कैम्प, फिल्म सिटी, आई० टी० सिटी, आदि के निर्माण कार्य एवं बढ़ती आबादी के मद्देनजर पानी की अत्यधिक आवश्यकता है। संधारणीय विकास एवं पर्यावरण परिस्थितिकीय तंत्र के संतुलन हेतु जल एक परम आवश्यक घटक है।

इसी के मद्देनज़र "Ganga water lift scheme" शुरू की गई है, जिसमें मोकामा के निकट राजेंद्र सेतु के अधोभाग से गंगा जल को मॉनसून के चार महीने में लिफ्ट किया जाना है और घोसवरी–सरमेरा–बिहारशरीफ नया बाईपास–गिरियक के रास्ते आबगिला (मानपुर) गया तक 148.6 किलोमीटर पाईप लाईन के जरिए ले जाना है। बीच में पूरे वर्ष की आवश्यकता के अनुसार जल का भंडारण घोड़ाकटोरा झील, पंचाने नदी एवं घोड़ाकटोरा झील के बीच प्रस्तावित जलाशय, तेतर पंचायत के बिकैयपुर ग्राम के निकट पहाड़ी के पास प्रस्तावित जलाशय और आबगिला (मानपुर) में प्रस्तावित आर०सी०सी० टैंक में किया जाएगा। नवादा जिले के मोतनाजे ग्राम में एक डिटेन्सन टैंक और राजगीर के लिए जलशोधन संयंत्र तथा गया जिले के आबगिला में बोधगया तथा गया के लिए जलशोधन संयंत्र बनाया जाना है। इन जलशोधन संयंत्रों में शोधित पेयजल को पाईप लाईन के द्वारा घर–घर तक पहुँचाया जाएगा। इस हेतु कार्य आवंटनादेश निर्गत कर दिया गया है। इसके प्रथम चरण को जून, 2021 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

इस योजना से पर्यटन की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण **राजगीर, गया और बोधगया शहरों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 135 लीटर जल की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।** योजना के प्रथम चरण पूर्ण होने के उपरांत इन तीनों शहरों की लगभग नौ लाख की आबादी लाभान्वित होगी, जबकि वर्ष 2051 तक योजना से सीधे तौर पर लाभान्वित स्थानीय आबादी की संख्या बढ़कर लगभग तेरह लाख हो जायेगी। इसके अलावे इन शहरों में प्रत्येक वर्ष आने वाले लगभग दो करोड़ श्रद्धालु एवं पर्यटक भी इस योजना से सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। यह योजना नालंदा, गया और नवादा जिले में गिरते भू–जल स्तर को पुनर्स्थापित करने तथा पर्यावरणीय संतुलन की रक्षा में भी काफी मददगार होगी।

लखनदेई की पुरानी धार का पुनरूद्धार

महोदय, जीवनदायी लखनदेई नदी की धार्मिक प्रयोजन हेतु बहुपयोगी पुरानी धार को पुनर्जीवित करने की माँग लंबे अरसे से की जा रही थी। इसके मद्देनज़र लखनदेई नदी की नई धार को पुरानी धार से मिलाने और पुरानी धार की उड़ाही का कार्य विभाग द्वारा 19.9 करोड़ रुपए की लागत राशि पर कराया जा रहा है।

महोदय, आज इस नदी का नया रूप बिल्कुल बदला हुआ है और इस innovative जिर्णोद्वार को जल शक्ति मंत्रालय सहित राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है। इस योजना का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 15 फरवरी, 2018 को किया गया। इस कार्य योजना का 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है, जिसके अंतर्गत 18.27 किलोमीटर में री–सेक्शनिंग कार्य, दो अदद डी०एल०आर० ब्रीज का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है एवं नेपाल बार्डर से बिहार के सीतामढ़ी जिला के दुलारपुर गाँव तक तीन किलोमीटर की लम्बाई में लिंक चैनल का निर्माण कार्य कराया जाना है जिसके लिए 23.35 एकड़ भू–अर्जन हेतु प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है।

इस योजना को 2020 की बाढ़ से पहले पूर्ण करने का कार्यक्रम है। इससे सोनवर्षा, बथनाहा, सीतामढ़ी और रून्नीसैदपुर प्रखण्डों में कुल 2539.86 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि का पुनरुद्धार हो जाएगा।

फल्गू नदी में विष्णुपद मंदिर के पास सालों भर जल उपलब्ध कराने की योजना

हम सभी जानते हैं कि गया की फल्गू नदी का विशेष धार्मिक एवं पौराणिक महत्व है। पितृपक्ष में देश–विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पिंड दान हेतु यहाँ आते हैं। इस दृष्टिकोण से माननीय मुख्यमंत्री का फल्गू नदी में हमेशा कम से कम 0.60 मी० जल की हरदम उपलब्धता पर विशेष जोर रहा है। इसके लिए विभाग द्वारा फल्गू नदी के तल का भू–तकनीकी अध्ययन कराकर योजना के स्वरूप का निर्धारण कर लिया गया है। मार्च 2020 तक डी०पी०आर० तैयार कर योजना का कार्यान्वयन किया जायेगा। इस योजना के कार्यान्वयन के बाद गया शहर के विष्णुपद मंदिर के पास फल्गू नदी में सालों भर जल की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। इस पूरी योजना की परिकल्पना माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कुछ वर्षों पहले की गयी थी एवं उनकी विशेष अभिरूची व मार्गदर्शन के परिणम स्वरूप आज हम इसे फलीभूत करने की स्थिति में आ पहुँचे हैं।

वाल्मीकिनगर का पर्यटन स्थल के रूप में विकास

महोदय, अगर आप प्रकृति की खूबसूरती का करीब से दीदार करना चाहते हैं, तो पश्चिम चम्पारण जिले का वाल्मीकिनगर एक बेहतरीन जगह है। इसे बिहार के एक अन्य महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है, जिसे पूरा करने के लिए हमारा विभाग तत्परता से कार्य कर रहा है। वाल्मीकिनगर में ईको–पार्क, गेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस की छत पर ईको–हट और गेस्ट हाउस से होटल वाल्मीकि विहार तक सड़क के पुनर्निर्माण का कार्य पूरा कर लिया गया है। वाल्मीकिनगर बराज के अपस्ट्रीम में गंडक नदी के बायें तट पर वाल्मीकिनगर आई०बी० के सामने 24.81 करोड़ रुपए की लागत राशि से 1080 मीटर की लंबाई में सुरक्षात्मक कार्य भी पूर्ण हो चुका है। इसमें Maccaferri Concept का उपयोग करते हुये पत्थर से रिटेनिंग वाल बनाया गया है जो काफी cost effective है। उक्त दोनों कार्यों का

उद्‌घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा नवंबर, 2019 में संपन्न हुआ है। इन कार्यों से न केवल वाल्मीकिनगर बराज और वाल्मीकिनगर टाइगर रिजर्व के अरण्य क्षेत्र को सुरक्षा मिलेगी, बल्कि वाल्मीकिनगर एक पर्यटक स्थल के रूप में अपनी खास पहचान भी बनायेगा।

इसके अतिरिक्त गंडक नदी के अपस्ट्रीम भाग में 25.04 करोड़ की लागत से 1010 मीटर की लम्बाई में भी तटबंध के सुरक्षात्मक कार्य कराये जा रहे हैं, जिसके निर्माण से गंडक नदी के बाँये भाग में नदी के एच०एफ०एल० से लगभग 4 मीटर ऊपर कुल 2.90 किलोमीटर पैदल पथ (Path way) का निर्माण कार्य मुम्बई के **मैरिन ड्राईव** की तर्ज पर कराया जा रहा है जिससे पर्यटकों को कौलेश्वर स्थान तक पहुँचने में सहायता होगी एवं पर्यटकों को प्रातः एवं संध्या काल में टहलने के साथ–साथ प्राकृतिक सौंदर्य का आनन्द लेने के लिए अनुकूल होगा। इस पैदल पथ को Paver Block के द्वारा बनाया गया है जिसे किसी भी मौसम में उपयोग किया जा सकेगा।

गंडक नदी के दाँये भाग में भी तटबंध के सुरक्षा के साथ–साथ सैंदर्य की दृष्टिकोण से 77.16 करोड़ की लागत से 3310 मीटर के लम्बाई में सुरक्षात्मक कार्य आधुनिक तकनीक का उपयोग कर कराया जा रहा है।

आँकड़े खुद गवाह हैं...

महोदय, कुछ चीजों की गवाही खुद आँकड़े देते हैं। वर्ष 2005–06 में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में नई सरकार बनने के बाद से राज्य में जल संसाधन तथा सिंचाई से जुड़ी योजनाओं को कितनी अहमियत मिली है, इसे विभाग के योजनागत व्यय (Plan Expenditure) के आँकड़ों से आसानी से समझा जा सकता है। **पिछले 15 वर्षों में, यानी 2005–06 से 2019–20 तक** (चालू वित्त वर्ष के आँकड़े 26 फरवरी, 2020 तक के हैं) **विभाग का कुल योजनागत व्यय 22,055.58 करोड़ रुपए रहा है।** जबकि, इससे पहले के 15 वर्षों में, यानी 1990–91 से 2005–06 तक, विभाग का कुल योजनागत व्यय सिर्फ 3,415.28 करोड़ रुपए रहा था। यानी 2005 से पहले के 15 वर्षों की तुलना में पिछले 15 वर्षों में जल संसाधन विभाग की योजनाओं के सीधे क्रियान्वयन में लगभग सात गुना ज्यादा राशि खर्च हुई है। यह स्थिति तब है, जबकि पहले के 15 वर्षों में से 10 वर्ष तक झारखंड भी हमारे साथ था।

महाशय, मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि वर्ष 1990–91 से 2004–05 तक विभाग का स्थापना मद में व्यय 3700 करोड़ था जो इस अवधि के योजना मद से लगभग 300 करोड़ अधिक था। इसके विपरीत, वर्ष 2004–05 से अबतक 15 वर्षों में विभाग का स्थापना मद में व्यय योजना मद से 9660 करोड़ कम रहा है, जो हमारी बदली कार्यशैली और विकास के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है।

पिछले वर्षों में जल संसाधन विभाग की कार्यशैली में व्यापक परिवर्त्तन इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि किसानों को लाभ पहुँचानेवाली योजनाओं में माननीय मुख्यमंत्री जी खुद रुचि ले रहे हैं। बिहार जैसे कृषि प्रधान राज्य में सिंचाई सुविधा के विस्तार की कितनी अहमियत है, इससे सदन के माननीय सदस्य भली–भांति परिचित होंगे। आपको यह जानकर खुशी होगी कि राज्य में **2005–06 से 2019–20 तक के पंद्रह वर्षों में 4.06 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन किया जा चुका है।**

नदी जल का सम्यक प्रबंधन एवं सदुपयोग

अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार की ऐतिहासिक भूमि मिथिला से आता हूँ, जो 20वीं सदी के सुप्रसिद्ध जनकवि एवं युग पुरुष बाबा नागार्जुन की भी जन्म एवं कर्मभूमि है। बाबा ने 'फसल' शीर्षक कविता में लिखा है –

"फसल क्या है,
और तो कुछ नहीं है वह,
नदियों के पानी का जादू है वह,
एक के नहीं,
दो के नहीं,
ढेर सारी नदियों के पानी का जादू"

'बाबा' की इन पंक्तियों से प्रेरणा लेकर हमारा विभाग जीवन दायिनी नदियों के पानी का 'जादू' राज्य के ज्यादा–से–ज्यादा इलाकों में पहुँचाने के उद्देश्य एवं संकल्प के साथ नदी जल का सम्यक प्रबंधन एवं सदुपयोग कर रहा है।

इसके लिए विभाग द्वारा कई अन्य योजनाओं के सूत्रण का कार्य किया जा रहा है। इनमें दक्षिण बिहार की नदियों में मॉनसून की अवधि में प्राप्त अधिशेष जल का चेक डैम/वीयर बनाकर संचयन करते हुए उपयोग करने; और उत्तर बिहार की नदियों में मॉनसून अवधि में प्राप्त अधिशेष जल को पोखर का निर्माण कर एवं नदियों के किनारे कुआँ बनाकर संरक्षण करते हुए उपयोग करने की योजनाएँ शामिल है। इसके अलावा मृतप्राय नदियों के गाद की सफाई कर उसे पुनर्जीवित करते हुए प्राकृतिक बहाव को बहाल करने की योजना के सूत्रण पर भी कार्य किया जा रहा है। साथ ही राज्य की कुछ नदियों को जोड़ने की अति महत्वाकांक्षी योजना के सूत्रण पर भी कार्य किया जा रहा है।

मृत प्रायः नदियों को पुनर्जीवित करने पर ज़ोर

बढ़ती जनसंख्या एवं पर्यावरण की कीमत पर जारी विकास कार्यों के कारण प्रकृति प्रदत्त नदियाँ, झीलें एवं अन्य जलश्रोत सीमित होते जा रहे हैं। यहाँ तक कि कई नदियाँ मृतप्राय हो गई हैं। बिहार के भागलपुर जिला का चम्पा नाला, दरभंगा एवं मधुबनी जिले में जीवछ कमला, पुरानी कमला, सोनी, गेहुँआ, मोहिनी तथा सिवान जिला में दाहा एव नालंदा जिला के सकरी, जिराईन तथा कुम्हरी नदी इसके ज्वलंत उदाहरण हैं।

माननीय मुख्यमंत्री जी के "जल–जीवन–हरियाली" अभियान के तहत् सभी जलश्रोतों यथा तलाबों, आहरों, सार्वजनिक कुओं आदि की पहचान कर इन्हें अतिक्रमण मुक्त और इनके पुनरूद्धार का कार्य किया जा रहा है। जल संसाधन विभाग इस बात के प्रति सजगता से कार्य कर रहा है कि हमारी नदियों को पुनर्जीवित करने से पयार्वरण और जल संकट की समस्या से निपटने में अप्रत्याशित सहयोग मिलेगा।

सिंचाई क्षमता का सृजन एवं पुनर्स्थापन

राज्य के संपूर्ण सिंचाई परिदृश्य में वृहद् एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। इन परियोजनाओं के विकास, रख–रखाव तथा कुशल संचालन के प्रति विभाग सतत् प्रयत्नशील है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के आलोक में **विभाग का पुनर्गठन** कर सिंचाई कार्य को एक अलग अभियंता प्रमुख (सिंचाई सृजन) के अधीन रखा गया है, ताकि हर परिस्थिति में सिंचाई कार्यक्रमों पर उचित ध्यान दिया जा सके।

माननीय मुख्यमंत्री जी की आकांक्षा रही है कि हर खेत को पानी पहुँचे। इसी प्रेरणा से विभाग गत वर्षो से सिंचाई सृजन कार्य को प्राथमिकता के साथ कियान्वित कर रहा है।

राज्य में वृहद् एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं से संभावित इष्टतम् सिंचाई क्षमता 53.53 लाख हेक्टेयर के विरुद्ध अब तक 30.253 लाख हेक्टेयर **सिंचाई क्षमता का सृजन** किया जा चुका है। वर्ष 2019–20 के दौरान लखीसराय, मुंगेर, जमुई, कैमूर, मधुबनी आदि जिले में 13 अदद् सिंचाई कार्यों को कार्यान्वित कराकर कुल 21.481 हजार हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया है।

अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजन के साथ–साथ 18 अदद् कार्यो के कार्यान्वयन से कुल 32.612 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में **ह्रासित सिंचाई क्षमता** को पुनर्स्थापित करने का कार्य भी किया गया है। इसमें पश्चिमी गंडक नहर प्रणाली का सारण मुख्य नहर और इसकी वितरण प्रणालियों का पुनर्स्थापन महत्वपूर्ण है, जिससे 18.225 हजार हेक्टेयर ह्रासित सिंचाई क्षमता का पुनर्स्थापन हुआ है। इससे सारण, सिवान और गोपालगंज जिले के हजारों किसानों को सिंचाई की सुविधा प्राप्त होगी।

इसके अतिरिक्त लखीसराय, जहानाबाद, बक्सर, रोहतास, पटना, गया, भागलपुर आदि जिलों की योजनाओं की ह्रासित सिंचाई क्षमता को पुनर्स्थापित करने का कार्य संपन्न कराया गया है।

टाल विकास योजना

टाल क्षेत्र के जल के बेहतर उपयोग एवं प्रबंधन के लिए विभाग दृढ़संकल्प है। इसके लिए एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार किया गया है। इस योजना का मुख्य अवयव 05 अदद Anti Flood Sluice का निर्माण, उत्तरी एवं दक्षिणी छोर पर 02 अदद तटबंध का निर्माण, जमींदारी बांधों का उच्चीकरण सुदृढ़ीकरण, भू–भाग जल के साथ सतही जल का सर्वोत्तम आर्थिक उपयोग के साथ 215 प्रतिशत Cropping Intensity प्राप्त करना, टाल क्षेत्र में उपस्थित जलाशयों का गहरा कर इसमें मछली तथा जलीय उत्पादन को विकसित करना तथा अवस्थित पईनों का डिसिल्टिंग कर ड्रेनेज व्यवस्था को कारगर बनाना है।

मोकामा टाल क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण कार्य के अंतर्गत 4 अदद् AFS एवं 1 अदद् AFS cum Regulator का निर्माण कार्य प्रस्तावित है, जिसमें 4 अदद् AFS का कार्य पूर्ण है तथा 1 अदद् AFS cum Regulator का निर्माण कार्य प्रगति में है। इन योजनाओं के कार्यान्वयन से लगभग 60,097 हेक्टेयर क्षेत्र को जल जमाव से मुक्त किया जा सकेगा।

वर्ष 2020–21 में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता के सृजन का कार्यक्रम

वर्ष 2020–21 में 38 अदद् कार्य कार्यान्वित कराये जाएंगे, जिनसे कुल 103,581 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन हो सकेगा। इसमें पश्चिमी कोसी नहर परियोजना का अवशेष कार्य, दरभंगा जिले के अलीनगर प्रखण्ड में गरौल वीयर सिंचाई योजना का कार्य, पुरानी कमला नदी के बघेला घाट पर सिंचाई योजना का कार्य, मोहिउद्दीननगर पकड़ी में टिकमा नदी पर सिंचाई योजना का कार्य, बलवाघाट बराज–सह–सिंचाई योजना का कार्य, पूर्वी गण्डक नहर प्रणाली फेज–टू का अवशेष कार्य, पश्चिमी गण्डक नहर प्रणाली में सारण मुख्य नहर एवं इसकी वितरण प्रणालियों के पुनर्स्थापन का अवशेष कार्य, बटेश्वरस्थान गंगा पम्प नहर योजना फेज–टू, दुर्गावती जलाशय परियोजना का अवशेष कार्य और मंडई वीयर योजना आदि महत्वपूर्ण हैं।

महोदय, अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत मैं दो परियोजनाओं का खास तौर पर उल्लेख करना चाहूँगा।

1. पश्चिमी कोसी नहर परियोजना : इसके पूर्ण होने से कुल 2,34,800 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हो सकेगी। हमारा मानना है कि यह परियोजना पूरे मिथिलांचल में दूसरी हरित क्रांति लाने के साथ–साथ जीवकोर्पाजन में सहायक सिद्ध होगी। इस अति महत्वपूर्ण परियोजना का डी०पी०आर० 1962 ई० में ही तैयार हुआ था, लेकिन 58 साल बाद भी यह पूर्ण नहीं हो सकी है। परियोजना के अवशेष कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए बाधाओं को तेजी से दूर किया जा रहा है। इसके निमित्त 64.43 करोड़ रुपए की लागत राशि से 7 अदद् कार्यों का शिलान्यास नवंबर, 2019 में माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ है।

इस परियोजना के पूर्ण होने पर मधुबनी और दरभंगा जिले के लाखों किसानों को सिंचाई की सुविधा मिलेगी, जिसे तत्परता से पूर्ण करने के लिए विभाग प्रतिबद्ध है।

2. दुर्गावती जलाशय परियोजना : रोहतास और कैमूर जिले के लिए अति महत्वपूर्ण इस परियोजना का शिलान्यास 1976 में ही तत्कालीन उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम ने किया था, लेकिन विभिन्न कारणों से यह अधर में लटकी हुई थी। मुझे सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की दृढ़ इच्छाशक्ति और गहरी रुचि के कारण इस मृतप्राय परियोजना को पुनर्जीवित किया गया और इसका कार्य अंतिम चरण में है, जिसे वर्ष 2020–21 में पूर्ण करने का कार्यक्रम है।

वर्ष 2020–21 में ह्रासित सिंचाई क्षमता के पुनर्स्थापन का कार्यक्रम

अतिरिक्त सिंचाई क्षमता के सृजन के साथ–साथ, वर्ष 2020–21 में पुरानी सिंचाई योजनाओं की 141,862 हेक्टेयर क्षेत्र में ह्रासित सिंचाई क्षमता को पुनर्स्थापित करने का भी कार्यक्रम है। इसमें पश्चिमी कोसी नहर, पश्चिमी गण्डक नहर, खड़गपुर झील सिंचाई योजना, आंजन जलाशय योजना, उदेरास्थान बराज सिंचाई योजना, नालंदा जिला अंतर्गत बेन प्रखण्ड में स्थित वीयर योजना, जिराईन नदी पर वीयर निर्माण, मलई बराज योजना, तियरा पम्प सिंचाई योजना, बदुआ जलाशय योजना आदि महत्वपूर्ण है।

पश्चिमी गंडक (सारण मुख्य नहर एवं इसकी वितरण प्रणाली) के 1.47 लाख हेक्टेयर ह्रासित सिंचाई क्षमता का पुनर्स्थापन एवं 1.58 लाख हेक्टेयर में नई सिंचाई क्षमता का सृजन कार्य 2061.82 करोड़ रुपए की लागत से प्रगति पर है। इसके तहत् 0.89 लाख हेक्टेयर ह्रासित सिंचाई क्षमता का पुनर्स्थापन एवं 0.72 लाख हेक्टयर में नई सिंचाई क्षमता का सृजन कार्य कराया जा चुका है। कार्य के कार्यान्वयन के उपरांत गोपालगंज जिले के 14 प्रखण्डों, सारण जिले के 20 प्रखण्डों तथा सिवान जिले के 19 प्रखण्डों के किसानों को सिंचाई सुविधा का लाभ मिलेगा।

नहरों के अंतिम छोर तक सिंचाई सुविधा

नहरों के अंतिम छोर तक पानी पहुँचाकर ज्यादा–से–ज्यादा किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना भी विभाग का दायित्व है। वर्ष 2019 खरीफ के दौरान जब सामान्य से कम वर्षापात होने के कारण किसानों को धान की रोपणी में कठिनाई हो रही थी, तब नहरों के द्वारा सिंचाई उपलब्ध कराकर उन्हें लाभ पहुँचाया गया और कुल 21.3 लाख हेक्टेयर के विरुद्ध 19.12 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई, जो लक्ष्य का 90 प्रतिशत है। गत् वर्ष गरमा सिंचाई के दौरान 28.67 हजार हेक्टेयर के लक्ष्य के विरुद्ध 23.66 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई। रब्बी सिंचाई अभी उपलब्ध कराई जा रही है।

नदी जोड़ योजना पर तेजी से काम

नदी जोड़ योजना के तहत् कोसी–मेची लिंक योजना हमारी प्राथमिकता सूची में है, जिसकी अनुमानित लागत राशि 4,900 करोड़ रुपये है। इसके कार्यान्वयन से किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार जिलों के 2.1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में किसानों को सिंचाई का लाभ मिलेगा। यह योजना वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय में स्वीकृति हेतु लंबित थी। गत् वर्ष, 17 जून, 2019 को मैंने स्वयं केंद्रीय जलशक्ति मंत्रालय, भारत सरकार में जाकर इसकी स्वीकृति के लिए पहल की। इसके फलस्वरूप योजना को वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त हो गई है। अब हमारा प्रयास है कि यह राष्ट्रीय योजना घोषित की जाए।

नदी जोड़ योजना के तहत् अन्य योजनाओं, जैसे सकरी–नाटा लिंक योजना और बूढ़ी गंडक–नून–बाया–गंगा लिंक योजना के डी०पी०आर० को अंतिम रूप देने का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है।

नालंदा जिलान्तर्गत चण्डी प्रखंड में मुहाने नदी पर पूर्व से एक बराज निर्मित है। मोहाने नदी के 1.5 किलोमीटर की दूरी से चिरैया नदी बहती है, जिसमें पूर्व से निर्मित चेक डैम के स्थान पर बराज का निर्माण तथा मोहाने एवं चिरैया नदी को लिंक चैनल के माध्यम से जोड़ने हेतु लिंक चैनल का पुनर्स्थापन कार्य 1999.63 लाख रुपये की लागत से कराया जा रहा है।

इस योजना के कार्यान्वयन से आवश्यकतानुसार दोनों नदियों के पानी को लिंक चैनल के माध्यम से आपस में एक दूसरे में भेजा जा सकेगा जिससे नालन्दा जिला के चण्डी प्रखंड में 1270 हे० क्षेत्र में सिंचाई सुविधा

का पुनर्स्थापन होगा। योजना की अद्यतन प्रगति 70 प्रतिशत है। योजना को अप्रैल 2020 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

2019 की भीषण बाढ़ से निपटने में कामयाबी

महोदय, वर्ष 2019 में दक्षिण बिहार में जहाँ सामान्य से कम वर्षा की स्थिति थी और किसान कृषि कार्य के लिए आवश्यक पानी की कमी से परेशान थे, वहीं उत्तर बिहार में अप्रत्याशित बाढ़ का संकट था। मुझे यह बताते हुए संतोष का अनुभव हो रहा है कि 2019 में अचानक आई भीषण बाढ़ से निपटने में हमारे विभाग का कार्य सराहनीय रहा है। इसे कुछ उदाहरणों से समझा जा सकता है। वर्ष 2019 में बाढ़ अवधि के दौरान पुनपुन एवं गंगा नदी में अप्रत्याशित बाढ़ आई जिसके कारण पटना शहर की शुरक्षा के लिए गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गयी थी, किन्तु अहर्निश तटबंधों को निगरानी कर इसे सुरक्षित रखा गया। इसमें लागातार स्वंय मेरे द्वारा, विभागीय अधिकारियों एवं अभियंताओं द्वारा कैम्प कर सुरक्षा कार्य का मोनिटरिंग किया गया एवं इसमें प्रशासन का भी पूरा सहयोग प्राप्त किया गया।

कमला नदी : कमला बलान नदी के नेपाल प्रभाग के जलग्रहण क्षेत्र में 12 एवं 13 जुलाई, 2019 को भीषण वर्षापात के कारण कमला बलान नदी में 13 जुलाई, 2019 की रात्रि में अत्यधिक जलश्राव का प्रवाह हुआ। फलस्वरूप जयनगर में कमला वीयर के ऊपर लगभग 2 फीट जल का बहाव होने लगा। कमला बलान नदी का जलस्तर पिछले सारे रिकार्ड को तोड़ते हुए झंझारपुर रेल पुल पर 54.5 मीटर हो गया, जबकि पूर्व में यहाँ का अधिकतम जलस्तर 1987 में 54.34 मीटर रहा था। पानी के अत्यधिक दबाव के कारण कमला बलान बायां तटबंध दो स्थलों पर तथा दायां तटबंध 6 स्थलों पर क्षतिग्रस्त हो गया। लेकिन, तत्कालिक रूप से इसकी मरम्मति करा ली गई।

अब इसके मजबूतीकरण हेतु एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया गया है। इसके लिए आई०आई०टी०, रूड़की द्वारा टूट के कारणों का अध्ययन कराया गया और तकनीकी सेवाएँ ली गई। आई०आई०टी० से प्राप्त प्रतिवेदन की समीक्षा के उपरांत सर्वोत्तम तकनीक का उपयोग करते हुए ब्रीच क्लोजर का कार्य कराया जा रहा है।

बागमती नदी : 13 जुलाई, 2019 को बागमती नदी के नेपाल प्रभाग के जलग्रहण क्षेत्र में भी अत्यधिक वर्षा हुई। इसके फलस्वरूप बागमती नदी में अप्रत्याशित जलश्राव का प्रवाह हुआ और पूर्व के उच्चतम जलस्तर के रिकार्ड को पार कर गया। बागमती नदी के ढेंग और सोनाखान गेज स्टेशन पर क्रमशः 73 एवं 72.05 मीटर उच्चतम जलस्तर दर्ज किया गया, जहां पूर्व में क्रमशः 72.6 मीटर (2017) और 70.77 मीटर (2014) उच्चतम जलस्तर दर्ज किया गया था। इसके बावजूद बागमती के सभी तटबंधों पर अहर्निश गश्ती एवं निगरानी कर इसे सुरक्षित रखा गया।

अधवारा और ललबेकिया नदी में भी अप्रत्याशित जलश्राव का प्रवाह हुआ एवं नए उच्चतम जल स्तर दर्ज किए गए, लेकिन सभी तटबंधों पर अहर्निश गश्ती एवं निगरानी कर इसे सुरक्षित रखा गया।

कोसी नदी : 13 जुलाई, 2019 को कोसी नदी पर वीरपुर स्थित बराज से 3 लाख 71 हजार क्यूसेक से अधिक जलश्राव प्रवाहित हुआ, जो विगत 15 वर्षों में सर्वाधिक था। इसके कारण कुछ स्थलों पर सीपेज की स्थिति बन गई थी, किंतु सभी स्थलों पर अहर्निश गश्ती एवं निगरानी कर तटबंध को सुरक्षित रखा गया।

फल्गू एवं अन्य नदियां : हालांकि वर्ष 2019 में दक्षिण बिहार में सामान्य से कम वर्षापात हुआ, लेकिन झारखण्ड के जलग्रहण क्षेत्र में 26 सितंबर से 30 सितंबर, 2019 के बीच अत्यधिक वर्षापात के कारण दक्षिण बिहार की नदियों यथा पंचाने, जिराईन, सोएबा, फल्गू, दरधा एवं पुनपुन में अप्रत्याशित जलश्राव प्राप्त हुआ। इसके कारण पंचाने नदी और जिराईन नदी में नया उच्चतम जलस्तर दर्ज किया गया। पुनपुन का जलस्तर भी अब तक के उच्चतम स्तर के बिल्कुल पास पहुँच गया था। इसके बावजूद अहर्निश गश्ती एवं निगरानी करते हुए सभी तटबंधों को सुरक्षित रखा गया।

2020 की संभावित बाढ़ के लिए पूर्व तैयारी

बाढ़ 2019 के दौरान क्षतिग्रस्त स्थलों तथा नदियों के व्यवहार एवं आक्रामकता को देखते हुए संवेदनशील स्थलों की पहचान कर कुल 120 अदद् बाढ़ सुरक्षात्मक/कटाव निरोधक कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिनकी कुल लागत राशि 606 करोड़ रुपए है। इसमें कोसी एवं गंडक नदी के नेपाल भू–भाग में कराए जाने वाले 21 अदद् कार्य भी शामिल हैं, जिन पर 71.24 करोड़ रुपए का व्यय प्रस्तावित है।

इसके अतिरिक्त तटबंधों के अनुरक्षण मद में 220.6 करोड़ रुपए व्यय करने का कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत वर्ष 2020 की बाढ़ अवधि के दौरान आवश्यक कार्य यथा बाढ़ संघर्षात्मक कार्य, विभागीय सामग्रियों का भंडारण, स्लूईस गेटों की मरम्मति, तटबंधों पर प्रतिनियुक्त गृह रक्षकों के वेतन भत्ता का भुगतान, नदियों के सेटेलाइट इमेजरी का क्रय आदि किया जाएगा।

इस वर्ष गृह रक्षकों के साथ–साथ स्थानीय दैनिक मजदूरों का उपयोग करने का विचार किया गया है। इससे तटबंध के निगरानी करने में सहयोग तथा स्थानीय लोगों की सहभागिता से बाढ़ पूर्व चेतावनी प्रकिया मजबूत होने की पूरी संभावना है।

बाढ़ सुरक्षात्मक एवं कटाव निरोधक कार्यों के पर्यवेक्षण हेतु विशेष जाँच दल का गठन भी किया जाएगा, जो कार्यों की विशिष्टता तथा प्रगति पर नजर रखेंगे और आवश्यकतानुसार सलाह भी देंगे।

2020 में कराए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य इस प्रकार हैं :–

लोकनायक जय प्रकाश नारायण के जन्मस्थल, सिताब दियारा ग्राम की सुरक्षा के लिए रिंग बाँध का निर्माण।

सीतामढ़ी जिलान्तर्गत रातो नदी के तट पर नो मेंस लैंड से निशा रोड तक तटबंध का निर्माण।

दायाँ कमला बलान तटबंध का विस्तारीकरण, ब्रीक सोलिंग एवं सुरक्षात्मक कार्य– प्रोफेसर नयन शर्मा, आई०आई०टी०, रूडकी के विशेषज्ञ द्वारा सुझाये गये जियोबैग पीचिंग जैसे आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल विभाग द्वारा करने की योजना है।

सीतामढ़ी, मधुबनी एवं दरभंगा जिलान्तर्गत अधवारा नदी के बायें तटबंध का उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य।

मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, समस्तीपुर, दरभंगा और खगड़िया जिलों में बागमती बाढ़ प्रबंधन योजना फेज–टू के तहत तटबंध का उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं निर्माण कार्य।

सुपौल एवं मधुबनी जिलान्तर्गत पश्चिमी कोसी तटबंध के उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण तथा इस पर बिटुमिनस सड़कों का निर्माण।

सुपौल एवं सहरसा जिलान्तर्गत पूर्वी कोसी तटबंध के उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण तथा इस पर बिटुमिनस सड़क का निर्माण

भागलपुर जिलान्तर्गत गंगा नदी के बायें तट पर जहान्वी चौक से इस्माईलपुर तक तटबंध निर्माण कार्य।

उक्त ज्यादातर कार्यों को 2020 की बाढ़ से पहले पूर्ण करने का कार्यक्रम है।

इसके अलावा, कटिहार जिलान्तर्गत मनिहारी प्रखण्ड में केवाला ग्राम से बाघमारा ग्राम तक गंगा नदी के बायें तट पर बोल्डर रिवेटमेन्ट कार्य की स्वीकृति गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई है। इससे रेलवे लाईन के निकट हो रहे कटाव एवं इस इलाके के लोगों को बाढ़ से सुरक्षा मिलेगी।

बागमती बाढ़ प्रबंधन योजना फेज–4(ए) के अंतर्गत बागमती नदी के दायें तट पर बेलवा के नजदीक हेड रेगुलेटर का निर्माण, बाँध का निर्माण एवं एज प्रोटेक्शन का कार्य प्रगति पर है। इससे पिपराही प्रखण्ड को बाढ़ से सुरक्षा मिलेगी तथा पूर्वी चम्पारण–बेलवाघाट–शिवहर स्टेट हाईवे–54 पर आवागमन बहाल हो जाएगा। इसे अगस्त, 2021 तक पूर्ण कराने का कार्यक्रम है।

बाढ़ से बचाव के लिए गैर संरचनात्मक उपाय

बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य में गैर संरचनात्मक उपायों का विशेष महत्व है। इससे स्थल पर कराए जा रहे भौतिक कार्यों की गुणवत्ता बढ़ती है तथा लागत कम होता है। गैर संरचनात्मक उपाय बाढ़ से होने वाले नुकसान को कम करने में भी काफी प्रभावी होते हैं।

वर्ष 2006 में जल संसाधन विभाग के अंतर्गत बाढ़ प्रबंधन सुधार सहायक केंद्र (FMISC) की स्थापना की गई है, जो विभाग को गैर संरचनात्मक तरीकों से बाढ़ प्रबंधन में सहायता प्रदान करता है। इसके अंतर्गत फेज–वन, फेज–टू, बिहार कोसी बाढ़ समुत्थान परियोजना एवं साउथ एशिया वाटर इनीशिएटिव ट्रस्ट फण्ड की योजनाओं को पूर्ण किया जा चुका है। बिहार कोसी बेसीन विकास परियोजना एवं नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट का कार्य प्रगति पर है।

साउथ एशिया वाटर इनीशिएटिव ट्रस्ट फण्ड के तहत् बागमती–अधवारा बेसीन के लिए फ्लड मॉडल विकसित किया गया है, जिससे बाढ़ पूर्वानुमान एवं जल प्लावन मानचित्र प्राप्त हो सकेगा। नेशनल सेंटर

ऑफ एटमॉस्फेरिक रिसर्च (NCAR, USA) के सहयोग से मेटियोरोलॉजिकल पूर्वानुमान के तहत् इन्सेम्बुल वर्षापात पूर्वानुमान प्रणाली विकसित की गई है, जिसका उपयोग फ्लड मॉडलिंग में होगा।

इसके अतिरिक्त आगामी मॉनसून अवधि के लिए 72 घंटे पूर्व बाढ़ चेतावनी निर्गत करने हेतु मॉडलिंग कार्य के लिए रीजनल नेटवर्क को विकसित किया जाना है।

महोदय, एक कविता की चंद पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा–

कहीं न हो मृगजल,
बस थोड़ी सी कोशिश भर में
छिपा हुआ है हल,
अगर सहेजी आज बूंद तो
बचा रहेगा कल।
बची रहेगी रंगत, रौनक,
धरती की हरियाली,
फूल, पांखुरी, डाली, बेलें,
तितली रंगों वाली,
बूंद–बूंद संचय करने की,
हम सब करें पहल।

बची रहे मुस्कान अधर की,
बची रहे अभिलाषा,
रहे धरा पर इतना पानी,
रहे न कोई प्यासा,
नदियाँ भी हो, पोखर भी हो,
कहीं न हो मृगजल।

(मनोज जैन मधुर की कविता)

इसी आशा, विश्वास और संकल्प के साथ सदन से अनुरोध है कि जल संसाधन विभाग के लिए प्रस्तावित बजट उपलब्ध कराया जाए। विभाग सभी जनोपयोगी कार्यक्रमों को ससमय पूरा करने के प्रति दृढ़संकल्पित है।

धन्यवाद !